



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934

No. 389]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

महानिदेशक (रक्षोपाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

विषय : कार्बन ब्लैक के आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच—अन्तिम निष्कर्ष के संबंध में ।

सा.का.नि. 602(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने सीमा-शुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 के संबंध में ।

(क) प्रक्रिया

1. मैसर्स एसोसिएशन ऑफ कार्बन ब्लैक मैन्यूफैक्चरर्स, 5ए राबाकैलाश, 55/4, बालीगुंजी सरकुलर रोड, कोलकाता-700019 ने इसकी दो सदस्य कंपनियों अर्थात् मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, 31, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 और मैसर्स हाइटैक कार्बन मुर्धबा इन्डस्ट्रियल एरिया, डाकघर रेनुकूट, जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) द्वारा भारत में कार्बन ब्लैक के घरेलू उत्पादकों की ओर से चीन जन.गण. से भारत में कार्बन ब्लैक के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 के नियम 5 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिससे कि चीन जनवादी गणराज्य से भारत को कार्बन ब्लैक के संवर्धित आयात से होने वाली बाजार विकृति और बाजार विकृति की चुनौतियों से कार्बन ब्लैक के स्वदेशी उत्पादकों की रक्षा की जा सके ।

2. इस बात से संतुष्ट होते हुए कि नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया था, चीन-जन.गण. से कार्बन ब्लैक के आयात के खिलाफ रक्षोपाय जाँच की शुरुआत दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 के नोटिस, तहत की गई थी, और उसी दिन इसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

3. दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 के जाँच शुरुआत नोटिस की एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र के अंगोपनीय रूपांतर की एक प्रति रक्षोपाय नियम, 2002 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार केन्द्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों, चीन जन.गण. की सरकार को नई दिल्ली स्थित इसके राजदूतावास के जरिए तथा अधोलिखित अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित कर दी गई थी ।

(I) घरेलू उत्पादक

क. मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, 31, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 ।

ख. मैसर्स हाइटैक कार्बन मुर्धबा इन्डस्ट्रियल एरिया, डाकघर रेनुकूट, जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) ।

ग. कान्तीनेन्टल कार्बन इण्डिया लिमिटेड, ए-14, इन्डस्ट्रियल एरिया नं. 1 जी टी रोड के दक्षिण कौ ओर, गाजियाबाद-201001 ।

घ. राल्सन कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जितवाल कलां, तहसील मालेरकोटला, जिला संगरूर, पंजाब ।

ङ. कैबाट इण्डिया लिमिटेड एमआईडीसी, प्लॉट नं. 3, ट्रांस थाणे क्रीक एरिया थाणे बेलापुर रोड, डाकघर घन्सोली, थाणे-400701, महाराष्ट्र ।

- च. हिमाद्रि कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, फाचुना टावर 23-ए, नेताजी सुभाष रोड 8वां तल कोलकाता-700001.

(iii) आयातक

- क. मैसर्स जेके टायर, लिंक हाउस, 3, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
- ख. मैसर्स बिरला टायर, शिवम चैम्बर्स 53, सैय्यद अमीर अली एवेन्यू, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल।
- ग. मैसर्स अपोलो टायर्स, अपोलो हाउस, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुडगाँव -122001 (हरियाणा)।
- घ. मैसर्स सिएट लिमिटेड, सिएट महल, 463, डा0 एनी बेसेन्ट रोड वर्ली, मुंबई-400030.
- ड. मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड, 124, ग्रीन्स रोड, चेन्नई-06
- च. मैसर्स राल्सन, प्लाट सं0 3, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मण्डीदीप, जिन्ना सयसेन, मद्रास-462046
- छ. मैसर्स पोद्दार टायर, जी.टी.रोड जुगियाना, लुधियाना (पंजाब)-141420.
- ज. मैसर्स ओरएंटल रबड़ इण्डस्ट्रीज, 525 कोरेगाँव, बीमा पुणे नगर रोड, पुणे
- झ. मैसर्स हिन्दुस्तान रबड़, 1 जानकी सेंटर ऑफ वीरा देसाई रोड अंधेरी(प0) मुंबई-53.
मै0 अग्रवाल रबड़ 15- 1 - 503/49/-ए अशोक मार्केट, सिद्धियाम्बर बाजार, हैदराबाद 500001 आन्ध्र प्रदेश।
- ट. मैसर्स एक्सेल रबड़, फ्लैट सं0 507, साई सदन अपार्टमेंट्स, एसबीआई बचतबैंक के सामने, एस.आर नगर, हैदराबाद-500038.
- ठ. मैसर्स तेगा इंडस्ट्रीज, प्रथम तल, सं0 210, 5वां मेन रोड, चिन्नय नगर द्वितीय स्टेशन, बंगलूर-560040.
- ड. मैसर्स फीनिक्स यूएल, आइडियल प्लाज्मा, चौथा तल, 11/1, सरस बस रोड, कोलकाता-700002, पश्चिम बंगाल।
- ढ. मैसर्स मोनोटोना टायर्स मुम्बई, मुम्बई-422001, महाराष्ट्र।
- ण. मैसर्स टीवीएस श्रीचक्रा, पेरुमलपट्टी रोड, बेलारीपट्टी रोड, मेतूर तालुक मद्रास-625122.
- त. मैसर्स आहूजा कॉन्टीनेन्टल, 1109, मित्तल टॉवर्स, एमजी रोड, बंगलूर।
- थ. मैसर्स मिडास रबड़ पी.जान जकारिया बिल्डिंग्स, कोट्टायम, केरल-686001.
- द. मैसर्स टालिन, एमसी रोड, कालाडी-683574, केरल।
- ध. मैसर्स टीएम टायर्स, 5-35, सर्वे सं. 305 एवं 321 कलकल गाँव मेडक -502320-आंध्र प्रदेश।
- न. मैसर्स हार्टव्स रबड़, (प्रा0) लि0 कमला टावर्स, द्वितीय तल प्लाट नं0 1-8-304 से 307 पटिंगड्डा रोड, बेगमपेट, हैदराबाद - 500016, आन्ध्र प्रदेश

(iii) निर्यातक

- क. हीबेई डागुनगमिंग इण्डस्ट्री ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, वेस्टर्न साइड, डान्हुआन साउथ रोड, शाही सिटी, हीबेई प्रान्त, पी.आर चीन।
- ख. शेंघाई कारगोस इण्टरनेशनल ट्रेड कम्पनी लिमिटेड, टी-2-12एफ, नं0 2601 जीटु रोड, शेंघाई पीआर.चीन।
- ग. हीबीजिंग कण्ट्री जिनयुआन रबड़ कैमिकल कं0 शेग ली रोड, गुआंगशा जिला 31-1-101, हेंगशुई सिटी, हीबेई प्राविन्स पी.आर.चीन।

- घ. हीबेई योन्घुई कैमिकल इण्डस्ट्रीज इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड सं० 199, जिन्हुआ रोड शीजुआंगहुआंग हीबेई, पी.आर.चीन।
- ङ. गान्य जिन्शी कैमिकल कम्पनी लिमि. 109#वेस्ट सुपर्व, मिन्ते काउण्टी, गान्सु पी.आर.चीन।
- च. शान्डोंग शुआंगयांग कैमिकल कम्पनी लिमि. सं० 787 डोंगर रोड, डोंगीइंग सिटी, शान्डोंग, पी.आर.चीन।
- छ. वीफेंग लोंगझाऊ इण्डस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स कम्पनी लिमि. लुआचेन्ग टाउन, शाङ्गुआंग सिटी, शान्डोव प्राविन्स, पी.आर.चीन
- ज. लाइवू ताइशान कार्बन ब्लैक कम्पनी लिमिटेड गोवोझुआंग इण्डस्ट्रियल जोन, लाइचेंग, लाइवू, पी.आर.चीन।
- झ. क्यूचांग कैमिकल कम्पनी लिमिटेड बीचेनवांग, टैन्गीयिन काउंटी, एनियांग सिटी, हीनान प्राविन्स पी.आर. चीन।
- ट. जियान्गक्सी ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक कम्पनी, लिमिटेड लियाओ, जिंगडेझेन सिटी, जियान्गक्सी प्राविन्स, 333000, पी.आर.चीन सुझाऊ बोआहुआ कार्बन क्यूशुगुआन सुझोऊ पी.आर. चीन-21515.
4. चीन जन.गण के ज्ञात निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और चीन जन.गण की सरकार सहित उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ प्रश्नावलियां भेज दी गई थीं कि वे जांच शुरूआत नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
5. हितबद्ध पक्षकार के रूप में उन पर विचार करने का अनुरोध मैसर्स ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन(एटीएमए) से प्राप्त हुआ था और अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।
6. निम्नलिखित पक्षकारों ने अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने का अनुरोध किया:
- क. निर्यातकर्ता राष्ट्र चीन जन.गण
- ख. ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन(एटीएम)
- ग. जियान्गक्सी ब्लैक कैट कार्बन इन्क लिमि. चीन।
7. जांच को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करने पर विचार करते हुए रक्षोपाय नियमावली 2002 के नियम 6(4) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध की अनुमति दे दी गई।
8. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच के दौरान अपना निवेदन प्रस्तुत किया
- क. चीन धातु खनिज एवं रसायन आयातक एवं निर्यातक वाणिज्य परिषद तथा चीन रबर उद्योग एसोसिएशन
- ख. ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (ए.टी.एम.ए.)
- ग. जियान्गक्सी ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक इंक. लिमिटेड चीन
9. अधोलिखित पक्षकारों ने प्रश्नावली के प्रत्युत्तर के रूप में सूचना प्रस्तुत की:
- क. हाई-टेक कार्बन (घरेलू उत्पादक प्रश्नावली)
- ख. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमि. (घरेलू उत्पादक प्रश्नावली)
- ग. जियान्गक्सी ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक इंक. लिमि. चीन (निर्यातक प्रश्नावली)

- घ. अपोलो टायर्स (आयातक प्रश्नावली)
- ड. सिएट टायर्स (आयातक प्रश्नावली)
- च. जे.के. टायर्स एंड इण्डस्ट्रीज लिमि. (आयातक प्रश्नावली)
- छ. फीनिक्स कन्वेयर बेल्ट इंडिया (प्रा०) लिमि० (आयातक प्रश्नावली)

10. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना का, घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल पर दौरा करके, यथासंभव सत्यापन किया गया। सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय पाठ की सार्वजनिक फाइल में रखा गया।
11. समुचित निर्धारित करते समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए सभी विचारों को ध्यान में रखा गया। प्राप्त अथवा अवाप्त अगोपनीय जानकारी को पब्लिक फाइल में रखा गया।
12. त्वरित जांच करने के उपरांत 30% यथामूल्य की दर से रक्षोपाय शुल्क का अनन्तिम अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक निष्कर्ष 16 मार्च, 2012 को जारी किए जाए।

13. 25 मई, 2012 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें कई हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। तथापि निम्नलिखित हित बद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए:

क. याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग

ख. चीन धातु, खनिज एवं रसायन आयातक एवं निर्यातक वाणिज्य परिषद तथा चीन रबड़ उद्योग एसोसिएशन

ग. आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए)

घ. जियान्क्सी ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक इंक. लिमि० चीन

14. सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 के नियम 6 के उपनियम (6) में दी गई शर्तों के अनुसार लिखित रूप में दर्ज करें। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल किए गए लिखित प्रस्तुतीकरण की प्रति सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित प्रस्तुतियों के प्रति-प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित प्रस्तुतियों या उनके प्रति-प्रत्युत्तरों द्वारा व्यक्त सभी विचारों की जांच की गई और समुचित निर्णय लेते समय उनको ध्यान में रखा गया है।

ख. घरेलू उत्पादकों (आवेदक) के विचार

15. याचिकाकर्ताओं/घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचार संक्षेप में निम्नलिखित हैं-

क) विचाराधीन उत्पाद रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाने वाला 'कार्बन ब्लैक' है। यह एक अकार्बनिक रसायन है, जिसका प्रयोग रबड़ (टायरों सहित) के उत्पादन/प्रसंस्करण में, संबलनपूरक के रूप में किया जाता है। कार्बन ब्लैक को एसीटाइलीन ब्लैक, चैनल ब्लैक, फरनेस ब्लैक, लैम्प ब्लैक, लैम्पब्लैक, थर्मल ब्लैक और न्वायर डी कार्बन के रूप में भी जाना जाता है। रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक वह कार्बन ब्लैक है जिसका प्रयोग रबड़(टायरों सहित) के उत्पादन/प्रसंस्करण में संबलन पूरक के रूप में किया जाता है। यह याचिका, रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाने वाले कार्बन ब्लैक के बड़े हुए आयातों के बारे में है। गैर-रबड़ अनुप्रयोगों जैसे कापियर्स तथा कम्प्यूटर प्रिन्टर काट्रिजों में इंक, पेण्ट्स, क्रेयान्स और पालिशेस में प्रयोग किए जाने वाला कार्बन ब्लैक मौजूदा जॉच के दायरे के अन्तर्गत नहीं

आता है। सम्बद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अन्तर्गत उपशीर्षक संख्या 28030010 में आती हैं।

- ख) इस माल के चार अन्य उत्पादक भी हैं परन्तु आवेदक कम्पनियाँ अर्थात् मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और मैसर्स हाईटेक कार्बन 80% से अधिक का उत्पादन करती हैं और अतः वे प्रमुख उत्पादक हैं।
- ग) विचाराधीन उत्पाद का आयात समस्त क्षति अवधि में निरपेक्ष रूप से बढ़ा है परन्तु इसके आयातों में अभी हाल ही की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई है। हाल ही अवधि में आयातों में अचानक, तीव्र एवं अत्यधिक वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में उत्पादन के संबंध में भी आयातों में वृद्धि हुई परन्तु अभी हाल की अवधि में इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अभी हाल ही में आकस्मिक, महत्वपूर्ण और तीव्र वृद्धि हुई है। इस संबंध में नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें स्पष्टतया पूरी होती हैं।
- घ) विचाराधीन उत्पाद का पाटन इतिहास रहा है जिससे विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उद्योग को क्षति होती है।
- ङ) आवेदक ने 4 वर्षों की अवधि के आयात और क्षति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। याचिकाकर्ता ने अवधि के लिए की प्रत्येक तिमाही की अलग-अलग जानकारी तथा दिसम्बर, 2011 तक की माहवार जानकारी प्रस्तुत की है।
- आयात मात्रा के निर्धारण का आधार: याचिकाकर्ता ने आयातों के संबंध में आई बी आई एस, डी जी सी आई एण्ड एस तथा चीन के सीमा शुल्क द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी पर विचार किया। डी जी सी आई एंड एस तथा चीन के सीमा शुल्क द्वारा प्रकाशित जानकारी को इस कारण से अंगीकार नहीं किया जा सका कि कार्बन ब्लैक के ऐसे भी आयात किए गए जो रबड़ अनुप्रयोगों के लिए नहीं हैं।
- च) चीन से सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार आयात: चीन के सीमा शुल्क की सांख्यिकी पर इस कारण से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसमें अन्य प्रकार के कार्बन ब्लैक को भी शामिल जाता है, उनका उल्लेख कर दिया जाता है कि ये आयात प्रमुखतया विचाराधीन उत्पाद के हैं और अन्य प्रकार के कार्बन ब्लैक की संपूर्ण जरूरत अत्यधिक न्यून है, परन्तु चीन के सीमा शुल्क द्वारा प्रकाशित जानकारी में इस तथ्य का संकेत होता है कि कार्बन ब्लैक के आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- छ) आयातों में वृद्धि: विचाराधीन उत्पाद के आयातों में न केवल समग्र रूप से वृद्धि हुई है बल्कि इसके उत्पादन एवं खपत के संबंध में अभी हाल ही की अवधि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आयातों में इस वृद्धि के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- i) लागत लाभ: घरेलू द्वारा उद्योग कार्बन ब्लैक का विनिर्माण करने के लिए सी बी एफ एस को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है जबकि चीन के उत्पादक सी बी ओ का प्रयोग करते हैं। दोनों कच्चे माल की कीमत में बहुत अधिक अन्तर है (चीन में प्रचलित सी बी ओ की कीमतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित सी बी एफ एस की कीमतों की तुलना) दोनों कच्चे माल की कीमत में अन्तर चीन के उत्पादकों को अत्यधिक लागत लाभ प्रदान करता है जिसके कारण चीन से कार्बन ब्लैक का न्यून कीमतों पर आयात होता है।
 - ii) कार्बन ब्लैक उद्योग में कच्चा माल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस आधार पर कार्बन ब्लैक के उत्पादक कीमत का निर्धारण करते हैं। अतः कच्चे माल की कीमत कार्बन ब्लैक की कीमत निर्धारण प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कीमत प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि जून माह से सी बी ओ की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गयी और उसी समय सी बी एफ एस की कीमतें बढ़नी

शुरू हो गई। इसलिए घरेलू उद्योग और चीन दोनों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी। परन्तु इस बढोत्तरी के बावजूद, घरेलू उद्योग की कीमतों और तृतीय देशों की कीमतों की तुलना में चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्भूत की गई कीमत के बीच भारी अन्तर था। तृतीय देशों अर्थात् कोरिया, आस्ट्रेलिया और थाईलैंड के कार्बन ब्लैक की कीमत चीन की कीमत से उच्चतर बनी रही जिससे यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि चीन से आयात में वृद्धि तथा तृतीय देशों से आयात में गिरावट क्यों हुई।

- (iii) चीन के आपूर्तिकर्ताओं ने सी बी एफ एस की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमतों में वैश्विक वृद्धि के मद्देनजर अपनी कीमतें बढ़ा दीं। तथापि, कार्बन ब्लैक की प्रचलित कीमतों की तुलना में चीन की कीमतें अब भी अत्यधिक न्यूनतर बनी रहीं और उसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए चीन का कार्बन ब्लैक अत्यधिक लाभप्रद हो गया। इस तथ्य के कारण भारत में कार्बन ब्लैक के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई।
- (iv) कच्चे माल की कीमत में अन्तर के कारण चीन सस्ते कार्बन ब्लैक का आयात हुआ तथा इसने भारतीय बाजार में अपना कब्जा जमा लिया जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई।
- (v) चीन से आयातों पर पाटनसेधी शुल्क जोड़ने के बावजूद भी चीन के कार्बन ब्लैक की कीमतें घरेलू उद्योग के कार्बन ब्लैक की तुलना में अत्यधिक कम बनी रहीं जिससे चीन के उत्पादकों को बाजार का फायदा पहुंचा।
- (vi) अत्यधिक क्षमता: चीन के उत्पादकों में बेसी उत्पादन करने की क्षमता है और इसलिए वे बाजार अवसरों की खोज करते हैं। चीन के कार्बन ब्लैक के बाजार में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि हो रही है और तद्वारा उनके निर्यात मात्रा में वृद्धि हो रही है। चीन की कार्बन ब्लैक उत्पादन की क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक हो गयी और इसका आउटपुट प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन टन है। दोनों कच्चे माल की कीमतों में यह अन्तर अक्टूबर, 2011 के बाद और अधिक बढ़ गया। संयुक्त देश में सम्यक् वस्तु की भारी उत्पादन क्षमता और उनकी निर्यातव्युत्पत्ति तथा भारत में संयुक्त वस्तु की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए इस तथ्य की पूर्ण समझ है कि वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 की तुलना में आयात में वृद्धि बनी रहेगी।

झ. संबंधित उत्पाद की मांग संपूर्ण क्षति अवधि में बढ़ती रही।

न. सम्बन्धित आयातों से आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोगीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

ट. घरेलू उत्पादन वर्ष 2010-11 तक बढ़ा परन्तु तत्पश्चात् अभी हाल ही की अवधि में उसमें गिरावट आई। कार्बन ब्लैक की उत्पादन प्रक्रिया ऐसी है कि घरेलू उद्योग को न केवल अर्थ व्यवस्था की दूर प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने बल्कि संयंत्र एवं उत्पादन कुशलताओं से जुड़ी निर्धारित लागत को प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। तथापि, आयातों की गति में बढोत्तरी इतनी तीव्रता से हुई कि घरेलू उद्योग को अपने उस उत्पादन की विपत्ति करने के लिए जो घरेलू बाजार में नहीं थिक सका भारत के बाहर बाजार अवसरों की तलाश करने के लिए विवश होना पड़ा। घरेलू उद्योग द्वारा इस अतिरिक्त प्रयास के बावजूद घरेलू उद्योग का मालसूची स्तर इस सीमा तक बढ़ा कि घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन एकाएक बढ़ करने के लिए विवश होना पड़ा।

- ठ. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि यह अतिरिक्त क्षमता बाजार में इस उत्पाद की मौजूदा एवं सम्भावित मांग के मद्देनजर आई है। वर्ष-दर-वर्ष आधार तथा तिमाही आधार पर क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ड. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वित्त वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई। परन्तु अभी हाल ही की अवधि में इसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में संबंधित आयातों के कारण अत्यधिक कमी आई है। घरेलू उद्योग को निरन्तर न्यूनता बिक्री मात्रा का सामना करना पड़ रहा है। बिक्री मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई जबकि आयातों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई।
- ढ. घरेलू उद्योग को संचित मालसूची की समस्या का संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सामना करना पड़ता है। मालसूची का स्तर जो वर्ष 2008-09 में 3912 मी० टन था वर्ष 2011-12 में बढ़कर 9832 मी० टन हो गया।
- ण. आयातों की लैण्डिड कीमत (क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और (ख) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से न्यूनतर है। आयातों से घरेलू कीमतों में अत्यधिक गिरावट आ रही है। कीमत में गिरावट आने के कारण कीमत हास और शमन हो रहा है। यह उल्लेख करना संगत है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के बीच अन्तरात्त तिमाही दर तिमाही आधार पर घटा है क्योंकि वर्ष 2011-12 की पिछली दो तिमाहियों में बिक्री लागत बिक्री कीमत से अधिक रही। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अभी हाल की अवधि वित्तीय घाटा हुआ।
- त. घरेलू उद्योग की लाभ पदायकता में वर्ष 2009 - 10 में सुधार हुआ परन्तु तत्पश्चात उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई।
- थ. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वार्षिक और तिमाही दोनों अवधियों में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों को रोजगार पर लगाना और उन्हें रोजगार से हटाना घरेलू उद्योग के लिए अन्तिम रास्ता है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि क्षति के एक तथ्य के रूप में रोजगार का, देश में श्रम विधियों और उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के मद्देनजर, संबंधित आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है।
- द. घरेलू बाजार में पहले से ही कष्ट पहुँचा रहे बाजार विघटन के अतिरिक्त कार्बन ब्लैक के सम्बंधित आयात घरेलू उद्योग के बाजार विघटन की चुनौती उपस्थित कर रहे हैं।
- ध. घरेलू उद्योग की बाजार विघटन के लिए पाटन और न्यून कीमत पर आयातों के अतिरिक्त अन्य कोई घटक उत्तरदायी नहीं है। चीन जनगण (तथा अन्य देशों) से उत्पाद के पाटन की वजह से घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति हुई। तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की संस्तुति पहले ही कर दी है। अतः घरेलू उद्योग को हाल ही में हुई क्षति वह क्षति है जो पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- न. विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में तीव्र अधोगति के मद्देनजर अन्तरिम उपाय अनिवार्य है।

- प. याचिकाकर्ता ने अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण बाजार विघटन की चुनौती और घरेलू उद्योग के निष्पादन में तीव्र अधोगति के मद्देनजर अन्तरिम उपाय अत्यावश्यक है। घरेलू उद्योग पर उत्पादन कम करने के लिए दबाव डाला गया है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में अत्यधिक कमी आई है। आयातों की अधिकता के कारण बिक्री में कमी से अभी हाल ही की अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोगीकरण में अत्यधिक कमी आई है। घरेलू उद्योग की फिहरिस्त में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग कार्बन ब्लैक प्रचालनों से वित्तीय क्षति का सामना कर रहा है।
- फ. याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि रक्षोपाय शुल्क की प्रमात्रा को पाटनरोधी शुल्क की राशि से घटाया जा सकता है। घरेलू उद्योग न तो दोहरा संरक्षण चाहती है और न ही उसने पाटन रोधी शुल्क की अनदेखी कर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि महानिदेशक घरेलू उद्योग को होने वाली सकल क्षति का निराकरण करें।
- ब. लोक हित: प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना निम्नलिखित कारणों से लोकहित में होगा:
- i. उत्पादकों का हित:- रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करना भारतीय विनिर्माता सेक्टर के विचार से लोकहित में होगा क्योंकि यह भारत में घरेलू उद्योग का पतन होना रोकने में सहायता करेगा, आयातों को बढ़ने से रोकेगा और यह इन बढ़ते आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही भारी क्षति का निराकरण करेगा। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है और इसलिए इसकी कम कीमत वाले आयातों से रक्षा करने की जरूरत है।
 - ii. उपभोक्ताओं का हित- विचाराधीन उत्पाद का मुख्य उपयोग टायर बनाने में होता है। विचाराधीन उत्पाद उपभोक्ता उद्योग के लिए प्रमुख लागत तत्व नहीं है (प्रमुख लागत तत्व है प्राकृतिक रबड़)। घरेलू उद्योग के आकलन के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए कार्बन ब्लैक की लागत 6% के लगभग आती है (इस तथ्य को टायर उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है)। इसके अतिरिक्त आयातों में बढोत्तरी की अवधि के दौरान भारत में उत्पाद की मांग में चीन का हिस्सा 11% के लगभग बनता है। हालांकि उपभोक्ताओं को चीन से कार्बन ब्लैक का आयात करने की जरूरत नहीं है और घरेलू उद्योग देश की वर्तमान एवं संभावित मांग को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम है, फिर भी यदि यह तर्क दिया जाता है कि उपभोक्ता उद्योग को इस उत्पाद का चीन से समान स्तर पर आयात जारी रखना चाहिए और रक्षोपाय शुल्क लगाने से चीन से किए जा रहे इस आयात में उपभोक्ता की लागत में 30% की वृद्धि हो जाएगी, इससे यह स्पष्ट होता है किसी भी हाल में उपभोक्ता पर प्रभाव 0.33% से अधिक (पाटन रोधी शुल्क को नकार दिए जाने पर भी) नहीं होगा। इसलिए यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग पर यह मामूली सा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा क्योंकि टायर उद्योग अपनी जरूरत की सम्पूर्णमात्रा घरेलू बाजार से प्राप्त कर सकता है और रक्षोपाय शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का अपनी कीमतों में वृद्धि करने का कोई इरादा नहीं है।
 - iii. भारत सरकार ने रबड़ रसायनों (पी एक्स-13) में से एक के आयात पर इससे पहले रक्षोपाय शुल्क लगाया था जिसमें महानिदेशक (रक्षोपाय) ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पी.एक्स -13 के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा।
- ग) आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएसन (ए टी एम ए) के विचार
16. याचिकाकर्ताओं / घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार संक्षेप में निम्नलिखित हैं:-

- क) घरेलू उद्योग द्वारा मध्य में कीमत आंकड़ों में परिवर्तन: घरेलू उद्योग ने जांच के दौरान की कीमत आंकड़ों में परिवर्तन, उनका कोई स्पष्टीकरण दिए बिना, कर दिया।
- ख) घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा का महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा न्यून रिपोर्टिंग: प्रारंभिक निष्कर्ष के पृष्ठ सं० 16 पर उल्लिखित निर्यात मात्रा डी आई की 'स्थल पर सत्यापन' रिपोर्ट में उल्लिखित निर्यात मात्रा से मेल नहीं खाती है और इससे यह प्रतीत होता है कि प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्यात मात्रा को कम करके दर्शाया गया है।
- ग) प्रारंभिक निष्कर्ष में आयातकों के आत्मनिवेदन की अवहेलना: माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) ने प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 65 के तहत यह उल्लेख किया है कि "ए टी एम ए ने इसके कई सदस्यों द्वारा किए गए कार्बन ब्लैक के आयात के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। तथापि माननीय डी जी एस का यह उल्लेख उचित नहीं है क्योंकि अपोलो, जे के टायर्स और सिएट ने कार्बन ब्लैक के आयात आंकड़ों, सी आई एफ कीमत और घरेलू अधिप्रापण कीमत का उल्लेख किया था। ए टी एम ए के पास डी जी एस को किए गए आत्म निवेदन की प्राप्ति स्वीकृत रसीद है।
- घ) महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा प्रदत्त अति गोपनीयता: घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 2 जनवरी, 2012 के आत्म निवेदन के तहत यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग के प्लान्ट्स बंद हो गए हैं। तथापि घरेलू उद्योग ने उसके करणों का उल्लेख नहीं किया है। ए टी एम ए निवेदन करता है कि घरेलू उद्योग एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है इसलिए इसे इसके संयंत्रों के बंद होने के कारणों से शेयर होल्डरों को अवगत कराना चाहिए था। इसलिए इस सूचना को 'गोपनीय' अथवा 'बिजनेस संवेदनशील' के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहिए था जैसाकि घरेलू उद्योग के काउन्सेल ने तर्क दिया है कि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
- ड) घरेलू उद्योग कार्बन ब्लैक के उत्पादन के लिए एक इनपुट के रूप में कोलतार की अन्तर्निहित प्रतिस्पर्धात्मकता को मानता है।
- i. कोलतार के प्रयोग से होने वाले स्पष्ट लागत लाभ को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग कोलतार का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में, पी सी बी एल की वार्षिक रिपोर्ट में प्रावधान है कि पी सी बी एल कोलतार को एक इनपुट उत्पाद के रूप में वित्त वर्ष 2008-09 से प्रयोग का रहा है। इस प्रकार पी सी बी एल कार्बन ब्लैक के उत्पादन में कोलतार को एक इनपुट के रूप में पहले से ही प्रयोग कर रहा है। इस संबंध में ए टी एम ए यह आत्म निवेदन करता है कि किसी कंपनी के लिए गैर क्षतिकारी (एन आई पी) कीमत संसाधनों के अत्यधिक कार्यकुशल उपयोग पर आधारित होनी चाहिए। चूंकि पी सी बी एल पहले से ही कोलतार का प्रयोग कर रहा है इसलिए घरेलू उद्योग की एन आई पी का निर्धारण कोलतार की कीमतों के अनुरूप किया जाना चाहिए न कि सी बी एफ एस कीमतों के अनुरूप।
 - ii. इसके अतिरिक्त, पी सी बी एल ने उड़ीसा में एक कोलतार संयंत्र भी शुरू किया है। पी सी बी एल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह प्लान्ट वित्त वर्ष 2012-13 की द्वितीय तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग ने याचिका के अनुसार 4 वर्षों के लिए शुल्क संरक्षण मांगा है। तथापि, इस तथ्य के मद्देनजर कि कोलतार संयंत्र (वर्ष 2012-13) की) द्वितीय तिमाही में कार्य करना शुरूकर देगा, सी बी एफ एस कीमतों के आधार पर शुल्क न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि एन आई पी में और अधिक कमी आएगी।

च) घरेलू उद्योग द्वारा बेहतर वित्तीय निष्पादन

- i. संस्थापित क्षमता 5,00,000 मी० टन से बढ़कर 7,24,000 मी० टन हो गई।
- ii. उत्पादन 4,16,244 मी० टन से बढ़कर 6,14,105 मी० टन हो गया जो 48% की वृद्धि है। प्रति माह औसत उत्पादन में भी वृद्धि हुई जो वर्ष 2008-09 में 34,687 मी० टन से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 51,175 मी० टन हो गया।
- iii. क्षमता उपयोगीकरण 83% से बढ़कर 85% हो गया।
- iv. घरेलू बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में केवल 4.8% घटी परन्तु आधार वर्ष से इसमें 32% की भारी वृद्धि हुई।
- v. घरेलू बिक्री मूल्य वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 65% बढ़ा।
- vi. घरेलू उद्योग को लाभ हो रहा है।
- vii. लाभों में गिरावट क्षमता विस्तार के कारण आई।

छ) कोई कीमत निग्रह/मंदी नहीं : महानिदेशक रक्षोपाय ने अपने दिनांक 3.11.2009 के कोटिड पेपर बोर्ड संबंधी आने विगत निर्णय में उल्लेख किया कि जब, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य विपरीत साक्ष्य के अभाव में, आयात कीमतों में वृद्धि हुई हो तो लाभ में किसी भी गिरावट के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वर्तमान याचिका के अनुसार, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि लाभ में कमी चीन जन गण से आयात में वृद्धि के कारण आई है। तथापि उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए लाभ में हुई कमी के लिए चीन जन गण से होने वाले आयात को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि डी जी रक्षोपाय ने घरेलू अधिप्रापण कीमत में वृद्धि के मुद्दे का निराकरण नहीं किया है, हालांकि ए टी एम ने इसे अपने गोपनीय एवं अगोपनीय दोनों आधार पर प्रदान किया है।

ज) बाजार विकृति की चुनौती नहीं: घरेलू उद्योग ने लाभ सहित सभी क्षति पैरामीटरों के संबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय निष्पादन भेजा है। तथापि लाभ में वर्ष 2011-12 में गिरावट आई है। अतः ए टी एम ए यह निवेदन करता है कि लाभ में अल्प गिरावट से घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति की चुनौती का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

झ) घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क द्वारा आच्छादित कथित क्षति: घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि घरेलू बिक्री मूल्य में वृद्धि से हुई है जो उसी अवधि के दौरान 65% तक बढ़ा, जो स्टैटतः यह दर्शाता है कि कीमत वृद्धि बिक्री मात्रा को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती है। अतः ए टी एम ए यह निवेदन करता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से पूरी हो जाती है।

ञ) क्षति के गैर-पृथक्करण के कारण कारणात्मक संबंधों में परस्पर टूट: डी जी एस दोहरे शुल्क संरक्षण की अनुमति न देने की अपनी परंपरा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अपवादात्मक परिस्थितियों में किसी उत्पाद पर पाटनरोधी और रक्षोपाय दोनों शुल्क लगाए जा सकते हैं। तथापि एक साथ शुल्क केवल तभी अधिरोपित किया जा सकता है जबकि क्षति का कारणों से 'पृथक्करण' किया गया हो, जैसाकि माननीय डी जी एस ने चीन जन गण से फ्रंट एक्सल बीम मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्टीयरिंग नकल एंड क्रैंकशैफ्ट्स आयात के विरुद्ध रक्षोपाय जांच में उल्लेख किया है। प्रारंभिक निष्कर्षों से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बाजार विकृति का हल निकालने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है जैसाकि फ्रंट एक्सल बीम के निर्णय द्वारा

अपेक्षित है। मौजूदा याचिका में क्षति के गैर-पृथक्करण के परिणामस्वरूप चीन से आयातों और घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों परस्पर टूट हुई।

घ. मै0 जियाग्विक्सन ब्लैक कैट कार्बन इंक. लिमि0 के विचार

17. मै0 जियाग्विक्सन ब्लैक कैट कार्बन इंक. लिमि0 व्यक्ति किए गए विचार संक्षेप में निम्नलिखित है -
- क) उन उत्पादों को शामिल करना जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं और गलत आयात आंकड़े प्रदान करना।
- i) यह जांच कार्बन ब्लैक के केवल रबड़ अनुप्रयोगों के संबंध में है और गैर-रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाने वाले अन्य ग्रेडों के कार्बन ब्लैक को वर्तमान जांच के जांच के दायरे से स्पष्टतः अलग कर दिया गया है। तथापि, डी जी एस जी द्वारा जारी प्रारम्भिक निष्कर्ष इस तथ्य का कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं कि आयात विश्लेषण किस तरह किया गया और क्या कोई अपवर्जन किया गया या नहीं।
 - ii) वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही के लिए जांच शुरुआत नोटिस और घरेलू उद्योग की याचिका में प्रदान कराए गए आंकड़े समान हैं। जबकि प्रारम्भिक निष्कर्षों में थोड़ी सी कमी दर्शाई गई है। वर्ष 2011-12 की प्रथम तिमाही के लिए जांच शुरुआत नोटिस, प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा घरेलू उद्योग की याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़े एक समान हैं।
 - iii) प्रारम्भिक निष्कर्षों में डी जी एस जी ने उल्लेख किया है कि संपूर्ण जांच अवधि अर्थात् 2008-09 से अक्टूबर, 2011-12 के लिए इसने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आई बी आई एस आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। यदि ऐसा मामला है तो याचिका और प्रारम्भिक निष्कर्षों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए थी। यदि यह परिकल्पना भी कर ली जाए कि डी जी एस जी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों में कुल आयातों से गैर-पी यू सी को अलग रखा है तो भी यह स्पष्ट नहीं है कि वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के आंकड़े ऊपर उल्लिखित तीनों स्रोतों में एक समान क्यों हैं।
- ख) बाजार विकृति का दावा सही नहीं है।
- i) डी जी एस जी ने घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि चीन जन गण से आयातों की अधिकता के मद्देनजर इसे बाजार विकृति का सामना करना पड़ रहा है और इससे भविष्य में बाजार विकृति की चुनौती उपस्थित हो रही है और अनन्तिम रूप से यह धारित किया है कि घरेलू उद्योग को बाजार विकृति और बाजार विकृतिकी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
 - ii) यद्यपि घरेलू उद्योग वर्ष 2011-12 की द्वितीय तिमाही और अक्टूबर 2011 में हुए आयातों में तीव्र वृद्धि के आयात आंकड़ों पर विश्वास कर रहा है, तथापि यह न तो भौतिक क्षति स्थापित करने में और न ही क्षति एवं संबंधित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में सक्षम रहा है।
 - iii) हालांकि हाई-टेक कार्बन के राजस्व में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 (वार्षिक आधार पर) में 21% की वृद्धि हुई है, तथापि फिलिप्स कार्बन ब्लैक की उसी अवधि के दौरान बिक्री राजस्व में 30.43% वृद्धि हुई। समग्र रूप से, घरेलू उद्योग कुल मिलाकर वर्ष 2011-12 में बिक्री राजस्व में लगभग 26% वृद्धि करने में सक्षम रहा है। अतः चीन जन गण से होने वाले आयातों ने घरेलू उद्योग की उन्नति को अवरुद्ध नहीं किया है और घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम हुआ है।

- iv) वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के लिए बिक्री राजस्व की तिमाही - दर - तिमाही तुलना घरेलू उद्योग के बिक्री राजस्व में अत्यधिक वृद्धि दर्शाता है। राजस्व में पहली तिमाही में 51% वृद्धि हुई और दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमशः 28% एवं 15% की वृद्धि हुई। वर्ष 2010 से घरेलू उद्योग को कोई घाटा नहीं हुआ और न ही इसके राजस्व में कमी आई।
- v) घरेलू उद्योग की उन्नति को पिछले 2 वर्षों से लगातार बढ़ते उत्पादन और क्षमता संबंधन से आंका जा सकता है। वर्ष 2008-09 की तुलना में घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं इसके क्षमता निर्माण में 45% तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11 की तुलना में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि उत्पादन क्षमता में 12% वृद्धि हुई है परन्तु उसी अवधि में उत्पादन में भी 4% की वृद्धि हुई।
- vi) अतः जहां तक बिक्री, उत्पादन और उत्पादन क्षमता का संबंध है, बढ़ते हुए आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई मात्रा प्रभाव नहीं पड़ा।
- vii) वर्ष 2008-09 के पश्चात घरेलू उद्योग व्यवधान रहित रहा और अच्छा निष्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- viii) डी जी, एस जी ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित लाभ को यह उल्लेख करते हुए नामंजूर कर दिया कि रिपोर्ट किया गया वार्षिक निष्पादन अनन्य रूप से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही नहीं है। ऐसा होने पर विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उत्पादन, क्षमता, बिक्री राजस्व और लाभ की पृथक जानकारी दी जानी चाहिए थी। और यदि पृथक्करण संभव नहीं हो पाता तो डी जी एस जी को 'कार्बन ब्लैक' के संबंध में घरेलू उद्योग के समग्र रूप से निष्पादन पर विचार करना चाहिए था।
- ग) क्षति के अन्य कारण: घरेलू ने उद्योग डी जी एस जी को यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसके संघटकों में से एक संघटक थाइलैंड से आयातित वस्तु हाइटेक कार्बन है। इस प्रकार घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हुई क्षति इस तथ्य के कारण हुई कि संबंधित अस्तित्व ने उन निर्यातों में अपनी पैठ बना ली। अतः डी जी एस जी को यह जांच या तो समाप्त कर देनी चाहिए या इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए यह मामला डी जी ए डी को भेज देना चाहिए।
- घ) कोई कारणात्मक संबंध नहीं: चीन से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा कमाया गया लाभ दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्षतः अनुपातिक हैं। जब भी आयातों में वृद्धि हुई घरेलू उद्योग के लाभ में भी वृद्धि हुई और जब भी घरेलू उद्योग के लाभ में कमी आई, तब आयातों में भी कमी आई। कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो घरेलू उद्योग के निष्पादन का निर्धारण करते हैं और घरेलू उद्योग के निष्पादन तथा चीन से आयात के बीच कारणात्मक संबंधों के अभाव के स्पष्टतः स्थापित करते हैं।
- ड.) कच्चे माल की लागत: सी बी एफ एस कार्बन ब्लैक एक प्रमुख कच्चा माल है और यह कार्बन ब्लैक के उत्पादन में प्रमुख लागत घटक है। कार्बन ब्लैक की लागत में आने वाला कोई भी बदलाव, कच्चे माल अर्थात् सी बी एफ एस की कीमत में हुए बदलाव के अनुक्रम में होगा। प्रथम तिमाही की तुलना में सी बी एफ एस की कीमतों में 2% की गिरावट आई है। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में 10% की वृद्धि हुई है। तथापि, तृतीय तिमाही में सी बी एफ एस की कीमतों में द्वितीय तिमाही में प्रचलित कीमतों की तुलना में 8% की वृद्धि हुई। इसके विपरीत बिक्री की लागत में 1% की वृद्धि हुई। इस प्रकार कच्चे माल की कीमत में बदलाव और उसके परिणामस्वरूप बिक्री की लागत में हुए फेर बदल में कोई

संपर्क नहीं है। जब एक प्रमुख कच्चे माल की कीमत कार्बन ब्लैक की लागत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ अन्य तथ्य हैं जो लागत में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।

च) चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता है: चीन के विरुद्ध टी पी एस एस जांच स्वभावतः अपवादात्मक है जिसका डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्य देशों द्वारा किराया से प्रयोग करना चाहिए तथा इसे आयात में वृद्धि के हर मामले प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

छ) रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क दोनों एक साथ अधिरोपित नहीं किए जा सकते हैं:- वर्ष 2010 में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क क्षति मार्जिन पर आधारित थे। अतः इस प्रकार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क में घरेलू उद्योग का आयातों द्वारा कारित क्षति का पहले ही ख्याल रखा गया है।

ज) पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण की अवधि के दौरान बिक्री कीमत में 24% की वृद्धि हुई जबकि उत्पादन लागत में केवल 12% की वृद्धि हुई। अप्रैल, 2011 से अक्टूबर 2011 के बीच जब सी बी एफ एस कीमत में 4% की वृद्धि हुई, तो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसी अवधि के दौरान 8% की वृद्धि हुई। इस प्रकार कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत अधिक दर पर बढ़ाने में सक्षम रहा। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि के बीच चीन से आयात कीमत में 17% की वृद्धि हुई। इससे स्पष्टतः यह संकेत मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण करने के समय से घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत सतत रूप से बढ़ाने और लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा। बिक्री कीमत में वृद्धि के साथ-साथ चीन की आयात कीमतों में भी सतत वृद्धि होती रही। अतः ऐसी कोई क्षति नहीं है जिसे पाटनरोधी शुल्क द्वारा कवर न किया गया हो। पाटनरोधी शुल्क के साथ-साथ अधिरोपित कोई रक्षोपाय शुल्क से घरेलू उद्योग को केवल दोहरा संरक्षण ही मिलेगा।

ड. चीन धातु खनिज और रसायन आयातक एवं निर्यातक वाणिज्य परिसंघ तथा चीन रबड़ उद्योग एसोसिएशन

18. चीन धातु, खनिज और रसायन आयातक एवं निर्यातक वाणिज्य परिसंघ तथा चीन रबड़ उद्योग एसोसिएशन द्वारा व्यक्त विचार संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

क) याचिका में प्रस्तुत जानकारी की अयथार्थता एवं अपर्याप्तता: यह एक सुनिर्धारित सिद्धान्त है कि जांच शुरुआत करने के लिए आयातों क्षति तथा कारणात्मक संपर्क से संबंधित 'पर्याप्त' साक्ष्य युक्त विधिवत भरी हुई याचिका का होना अनिवार्य है। तथापि, याचिकाकर्ताओं के दिनांक 7 जनवरी, 2012 के आत्मनिवेदनो के अनुसार यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने वस्तुतः जांच शुरू होने के उपरांत अपने आयात विवरण तथा लागत निर्धारण सूचना में संशोधन किया है। अतः, जांच शुरुआत ऐसी याचिका पर आधारित थी जिसमें अपर्याप्त जानकारी दी गई थी और जिससे मौजूदा जांच शुरुआत न्यायोचित नहीं ठहरती है।

ख) प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सूचना का अविश्वसनीय स्रोत: उक्त निष्कर्षों के पैराग्राफ सं0 65 में माननीय महा निदेशक (रक्षोपाय) ने याचिकाकर्ताओं द्वारा यथाप्रस्तुत गैर-सरकारी स्रोत आई बी आई एस से संग्रहित आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है न कि डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर। बड़े सम्मान के साथ यह प्रस्तुत किया जाता है कि गैर सरकारी स्रोत से संग्रहित आंकड़ों पर भरोसा करना माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा पिछली जांचों में अपनाई गई सुस्थापित प्रक्रिया के

अनुरूप नहीं है जिनमें माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) ने डी जी सी आई एंड एस से संग्रहित सूचना पर कम से कम यथासंभव सीमा तक भरोसा किया है।

ग) जांच की अवधि के बाद आयात में गिरावट: विनम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि सितम्बर-अक्टूबर 2011 माह में आयातों का असामान्य संचय के आलोक में माननीय महा निदेशक (रक्षोपाय) को देश में आयातों का सही-सही आकलन करने के लिए अक्टूबर, 2011 के पश्चात के वास्तविक आयातों के जांच करनी चाहिए थी। वास्तव में, मांग प्रणाली में परिवर्तन अक्टूबर, 2011 के पश्चात के आयात आंकड़ों में स्पष्टतः प्रदर्शित होता है जो चीन जन गण से आयातों की तीव्रता से गिरावट दर्शाता है। आयात आंकड़ों का गहन अध्ययन स्पष्टतः व्यक्त करता है कि सितम्बर, 2011 के पश्चात की अवधि में आयातों में वास्तव में गिरावट आई है और वे रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए अपेक्षित सतत बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति नहीं दर्शाते हैं।

घ) जांच अवधि अभिनव नहीं है: अर्जेन्टीना पदत्राण में डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय (डब्ल्यू टी/ डी एस 121 / ए बी / आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999) ने स्पष्ट किया कि 'आयातों में वृद्धि एकाएक एवं अभिनव' होनी चाहिए। यह विवाद पदत्राणों के आयात पर अर्जेन्टीना द्वारा 1997 में अधिरोपित अनन्तिम और निर्णायक रक्षोपाय शुल्क से संबंधित था। अपीलीय निकाय ने यह पाया कि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार में प्रयोग की गई भाषा "आयात किया जा रहा है" के आलोक में पांच वर्षों की अवधि की आयात प्रवृत्ति की जांच करना तर्क संगत नहीं है।

ङ) इस मामले के तथ्यपरक मैट्रिक्स में जांच की अवधि अप्रैल, 2008 में प्रारंभ होती है तथा अक्टूबर, 2011 में समाप्त होती है। स्पष्ट, 42 माह तक के पुराने आंकड़ों को 'अभिनव' के रूप में नहीं माना जा सकता है। माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा विश्लेषण किए गए आयात तिथिबद्ध हैं और क्षति विश्लेषण को विकृत करते हैं।

च) चीन जन गण में कच्चे माल की कीमतें "अन्य तथ्यों" के रूप में, न कि "अप्रत्याशित परिस्थितियों" के रूप में: सी बी एफ एस की कीमत प्रवृत्ति को ऐसे "अप्रत्याशित विकास" के रूप में नहीं माना जा सकता है जिससे आयातों में वृद्धि हो और घरेलू उद्योग को क्षति हो अथवा क्षति की चुनौती की स्थिति उत्पन्न हो। माननीय महानिदेशक, रक्षोपाय सी बी ओ में वृद्धि की संभाव्यता की अनदेशी नहीं कर सकते हैं जो सी बी एफ एस से अधिक महंगा हो सकता है। चीन के कार्बन ब्लैक उद्योग को न्यून लागत वाले कच्चे माल का उपयोग करके संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए अधिक लागत प्रभावी तरीका अपनाने के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता है।

छ) घरेलू उद्योग को क्षति न होना

i) अपेक्षित मानक का मूल्यांकन किसी ऐसे नकारात्मक प्रभाव को उद्घाटित नहीं करता है जो नितान्त: चीन जन गण से बड़े हुए निर्यातों से जुड़ा हो और अतः घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई।

ii) आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का विस्तार हो रहा है तथा यह अपनी क्षमताएं बढ़ा रही है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठापित क्षमता, घरेलू उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की कुल बिक्री, उत्पादन में बढ़ोत्तरी के अनुक्रम में रही है।

- ज) बाजार विकृति की चुनौती की अनुपस्थिति: देखा जा सकता है कि चीन का निर्यात तथा वैश्विक निर्यात का अनुपात सितम्बर, 2011 के पश्चात से तेजी से घटा है। चीन जन गण से निर्यातों में वृद्धि भारत में विशिष्ट मांग-आपूर्ति स्थिति के कारण एक अस्थायी प्रभाव थी और अब व्यापार प्रवाह सामान्य स्तर पर आ गया है तथा इस प्रकार बाजार विकृति की कोई चुनौती नहीं है।
- झ) गैर आरोपण तथा कारणात्मक संबंध का आभाव: विनम्रतापूर्वक यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए संबंध वस्तु केवल चीन जन गण से आयातों में वृद्धि को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और कारणात्मक संबंधों का अभाव है।
- ञ) अन्य स्रोतों जैसे थाईलैंड, रूस और कोरिया से बढ़ते आयातों के प्रभाव का माननीय महानिदेशक द्वारा विश्लेषण और उन पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे होने वाले क्षतिकारी प्रभावों, यदि कोई हो, को पृथक कर देना चाहिए।
- ट) घरेलू उद्योग का निर्यात फोकस: आधार वर्ष 2008-09 की तुलना में निर्यातों तथा घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार अपनी बिक्री घरेलू बाजार और / या निर्यात बाजार, जिसने कथित क्षति कारित की है, में करने की वाणिज्यिक पसन्द के लिए चीन जन गण से आयातों में वृद्धि को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह स्पष्टतः स्वतः पहुंचायी गई क्षति है।
- ठ) प्रभावोत्पादक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता: विनम्रतापूर्वक यह उल्लेख किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के दावों को माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं सहबद्ध शुल्क निदेशालय में आसन्न मध्यावधि समीक्षा, जिस पर पहले से ही कार्य चल रहा है, द्वारा हल किया जा सकता है। अतः याचिका कर्ताओं के पास पहले से ही एक प्रभावोत्पादक तंत्र है जिसके द्वारा क्षति के सभी दावों का उपयुक्त निपटारा किया जा सकता है और मौजूदा परिवर्ती रक्षोपाय शुल्क जांच अनावश्यक है।
- ड) जनहित: अतिरिक्त व्यापार उपचार संरक्षण भारतीय टायर उद्योग के विकास के लिए हानिकारक होगा जिससे व्यापक जन हित और देश के आर्थिक हित को क्षति हो रही है।

च आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए) का प्रति-प्रत्युत्तर

- क) घरेलू उद्योग का यह उल्लेख कि आयातों में बढोत्तरी का एक कारण चीन के उत्पादकों को लागत लाभ रहा है जो उन्हें कोलतार आयल का प्रयोग करने की वजह से प्राप्त हुआ। जैसा कि ए टी एम ए ने अपने इस प्रस्तुतिकरण तथा पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में स्पष्टतः दिखाया है कि घरेलू उद्योग खुद भी वर्ष 2008-09 से कोलतार आयल का प्रयोग करता रहा है और इसके अतिरिक्त एक कोलतार संयंत्र आगामी तिमाही अर्थात् जुलाई, 2012 से सितम्बर, 2012 में शुरू हो जाएगा। उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग की एन आई पी का निर्धारण कोलतार को एक इनपुट के रूप के आधार पर किया जा सकता है।
- ख) ए टी एम ए द्वारा अपने पी ओ एस टी पी एच डब्ल्यू एस में लाभ आंकड़ों के साथ प्रदान कराए गए क्षति आंकड़े स्पष्टतः व्यक्त करते हैं कि घरेलू उद्योग को बाजार विकृति से कष्ट नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ए टी एम ए को इस दावे का खंडन करने में सक्षम नहीं रहा है कि घरेलू अधिप्रापण कीमतों में वर्ष 2010-11 की तृतीय तिमाही की तुलना में वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 38-41 % की वृद्धि हुई है। घरेलू अधिप्रापण कीमतें स्पष्टतः प्रदर्शित करती हैं कि आयातों का घरेलू

कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है खासकर तब जब आयात कीमतों में वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही की तुलना में वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 45% की वृद्धि हुई है।

ग) ए टी एम ए अनुरोध करता है कि माननीय डी जी एस द्वारा घरेलू उद्योग को अपने आंकड़े मध्य में परिवर्तित करने की अनुमति न दी जाए और यद्यपि इसकी अनुमति दी जाती है तो उसका स्पष्टीकरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान कराया जाना चाहिए।

घ) ए टी एम ए माननीय डी जी एस का ध्यान कारणात्मक संबंधों में विघटन के प्रति आकृष्ट करना चाहता है। ए टी एम ए ने अपने पिछले आत्म निवेदन में यह उल्लेख किया है कि पाटन एवं आयातों में वृद्धि के कारण हुई क्षति का ब्यौरा न तो घरेलू उद्योग ने और न ही माननीय डी जी एस ने उपलब्ध कराया है। अतः डी जी एस द्वारा फ्रंट एक्सल बीम, माध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए चीन जन गण 17 में यथा प्रतिबिम्बित पिछली प्रक्रिया के मद्देनजर आयातों तथा घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क टूट गया है।

ङ) घरेलू उद्योग यह दर्शाने में अक्षम रहा है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाले क्षति को पूरा करने में पर्याप्त क्यों नहीं रहा है। इस संबंध में ए टी एम ए अपने विगत निवेदनों पर विश्वास करता है। यह नोट किया जना चाहिए कि घरेलू उद्योग ने ए टी एम ए के दावों का खंडन करने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है।

छ. मै0 जियान्तिक्सन ब्लैक कैट कार्बन इंक. लिमि0 का प्रत्युत्तर

क) चूंकि घरेलू उत्पादकों के पास ऐसी सुविधा है जो केवल सी बी एफ एस का प्रयोग करती है जबकि चीन के उत्पादक सी बी ओ का प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों उत्पादकों की लागतों के बीच आना लाजमी है।

ख) चीन के आयात में वृद्धि केवल एक अस्थायी प्रवृत्ति है।

ग) टी पी एस एस एम एक अपवादी उपाय है।

घ) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं।

ङ) कोई क्षति नहीं हुई।

च) गंभीर क्षति की कोई चुनौती है।

छ) मामला डी जी ए डी के भेजने के लिए उपयुक्त है।

ज. चीन धातु खनिज और रसायन आयातक एवं निर्यातक वाणिज्य परिसंघ चीन रबड़ उद्योग एसोसिएशन का प्रत्युत्तर

क. मौजूदा जांच की शुरुआत त्रुटिपूर्ण है।

ख. जांच की अवधि अभिनव नहीं है।

ग. आयातों का अभिशून्यन / वहिर्बेशन त्रुटिपूर्ण है।

घ. जांच की बाद वाली अवधि में आयातों में प्रभावकारी गिरावट

ङ. घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव।

च. चीन जन गण में कच्चे माल की कीमतें 'अन्य तथ्य' के रूप में न कि 'अप्रत्याशित परिस्थितियों' के रूप में

छ. नाजुक परिस्थितियों का अभाव।

- ज. कच्चे माल की कीमतों और तकनीकी भिन्नता स्पष्टतः एक ऐसा तथ्य है जिसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- झ. घरेलू उद्योग को बाजार विकृति की कोई चुनौती नहीं है
- ञ. अपनी बिक्री को घरेलू बाजार में और / या निर्यात बाजार में निदेशित करने की वाणिज्यिक पसंद, जिसके द्वारा उन्हें कथित क्षति हुई, के लिए चीन जन गण से आयातों में वृद्धि को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- ट. रक्षोपाय शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को दोहरा उपचार-संरक्षण प्राप्त होगा।
- ठ. अतिरिक्त व्यापार उपचार संरक्षण भारतीय टायर उद्योग के विकास के लिए हानिकारक होगा जिससे व्यापक जनहित और देश के आर्थिक हित को क्षति हो रही है।

झ) घरेलू उद्योग का प्रत्युत्तर

(i) एटी एम ए के निवेदन के संदर्भ में -

- क) महानिदेशक को भारत में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं से प्रश्नावली का बिल्कुल अनुपयुक्त/अपर्याप्त प्रत्युत्तर/जानकारी/सहायोग मिला है क्योंकि (क) ए टी एम ए सादस्य कंपनियां विचाराधीन उत्पाद की कुल के केवल 64% की खपत ही करती है (ख) मौजूदा जांच में भाग लेने वाली ए टी एम ए सदस्य कंपनियों द्वारा की जाने वाली खपत भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल खपत का बहुत थोड़ा सा भाग बनती है। (ग) विचाराधीन उत्पाद के अन्य उपभोक्ताओं ने महानिदेशक को सहयोग न करने को अधिमानता ही है (घ) महानिदेशक को उत्पाद के उपभोक्तावार आयात पर विचार करना चाहिए (हम आशा करते हैं कि महानिदेशक के पास उपलब्ध जानकारी में आयातकों के नामों का उल्लेख होगा) (ड.) आयातों में भारी वृद्धि अन्य बातों के साथ साथ, बालकृष्ण टायर्स द्वारा किए गए आयातों के कारण आई है जो वस्तुतः एक सहयोग न करने वाला पक्षकार है।
- ख) न ही चीन के उत्पादकों और न ही भारत के उपभोक्ताओं के प्रत्युत्तरों को 'पर्याप्त' माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में महानिदेशक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीन निर्यातों और भारतीय उपभोक्ताओं से अपर्याप्त/अनुपयुक्त प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है।
- ग) निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत निवेदन में टंकण त्रुटि है। पाटन रोधी मामलों से संबंध देशों (आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, चीन और रूस) से आयातों की रिपोर्ट देने के बजाय घरेलू उद्योग ने अनजाने में केवल चीन के आयातों का उल्लेख किया और इस उल्लेख में भी दिए गए आंकड़े गलत हैं। इसलिए वर्तमान जांच में प्रयोग की गई आयात सांख्यिकी केवल चीन से संबंधित है। हर हाल में महानिदेशक ने अपने निजी सत्यापित आंकड़ों को अंगीकार किया है और घरेलू उद्योग के दावों का बिना विचार किए उपयोग नहीं किया है।
- घ) जहां तक देश में इस उत्पाद के सकल आयात के संबंध में अपेक्षित जानकारी का सवाल है, आयात की मात्रा का निर्धारण करने के लिए प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों या आयातकों/उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जहां आयात मात्रा के संबंध में घरेलू उद्योग के आंकड़े विवादास्पद हैं वहीं ए टी एम ए ने चीन और तृतीय देशों से भारत में कार्बन ब्लैक के कुल आयात के संबंध में कोई सत्यापन योग्य दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
- ड) यह वह मामला नहीं है जिसका संबंध चीन जन गण और घरेलू उद्योग द्वारा सी बी ओ के प्रयोग का है। इस मामले का संबंध उस कीमत से है जिस पर चीन के उत्पादकों, घरेलू उद्योग और वैश्विक उत्पादकों को सी बी ओ उपलब्ध है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि सी बी ओ की कीमत चीन में और केवल चीन के उपभोक्ताओं के लिए चयनित रूप से न्यून है। वे इन कीमतों पर सी बी ओ का न तो चीन से आयात कर सकते हैं और न ही वैश्विक बाजार में सी बी ओ की कीमतें कम हैं।

- च) बिक्री राजस्व में वृद्धि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री लागत में बढ़ोत्तरी के कारण हुई परन्तु घरेलू उद्योग के लाभ में वर्षवार तथा तिमाहीवार दोनों तरह से गिरावट आई है।
- छ) ए टी एम ए की पहुंच 10 टायर विनिर्माता कंपनियों के साथ है क्योंकि ये कंपनियां ए टी एम ए की सदस्य हैं परन्तु ए टी एम ए ने केवल तीन कंपनियों (अपोलो, जे के टायर और सिएट) के संबंध में ही आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। एसोसिएसन ने इसके शेष सदस्यों से संबंधित आंकड़ों का खुलासा जानबूझकर नहीं किया है। पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के उपरांत क्षति मार्जिन काफी अधिक है और यह स्थापित करता है कि पाटनरोधी शुल्क होते हुए भी घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

(iii) मी0 जियान्गक्सन ब्लैक कैट कार्बन इंक लिमि0 के प्रस्तुतिकरण के संबंध में

- क) याचिका में प्रदान कराए गए आंकड़े अपरष्कृत आंकड़े हैं जिसमें कार्बन ब्लैक के सभी आयातों को शामिल किया गया है। तथापि, आयात विवरण में क्षति विश्लेषण और संबंधित आयात विश्लेषण, केवल रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक से संबंधित आयात पर ही विचार किया गया है। हर हाल में महानिदेशक (रक्षोपाय) ने अपने निजी विश्लेषण के आधार पर विचार किया है। महानिदेशक ने घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत आयात मात्रा पर विचार नहीं किया है। अतः इस तर्क के लिए कोई विधिक आधार नहीं है कि जिन आयातों पर विचार किया गया है उनमें विचाराधीन गैर उत्पाद भी शामिल हैं।
- ख) जहां तक महा निदेशक (रक्षोपाय) के समक्ष दायर आवेदन में वर्ष (2011-12) की द्वितीय तिमाही के लिए आंकड़े अर्थात् 25772 मी0 टन का संबंध है, यह एक तथ्य है कि उक्त मात्रा का रक्षोपाय याचिका में उल्लेख किया गया है परन्तु महा निदेशक (रक्षोपाय) द्वारा वर्ष (2011-12) की द्वितीय तिमाही के लिए अपनाए गए आंकड़े अर्थात् 25686 मी0 टन किए गए सतपन पर आधारित हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित आयातों से संबंधित प्रारंभिक निष्कर्षों का विरोध करने वाले किसी पक्षकार ने भारत में कार्बन ब्लैक के सकल आयातों के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
- ग) यह कि आयात आंकड़े विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं इसलिए उनमें भिन्नता है। जांच शुरूआत अधिसूचना में महानिदेशक रक्षोपाय ने डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों को अंगीकार किया है जबकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में आई बी आई एस आंकड़ों को अपनाया है। तथापि, प्रारम्भिक निष्कर्षों में डी जी एस डी ने विचाराधीन उत्पाद के लेनदेनवार आंकड़ों का स्वयं विश्लेषण करके आई बी आई एस आंकड़ों को अपनाया है।
- घ) बिक्री राजस्व में वृद्धि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री लागत में वृद्धि के कारण हुई है परन्तु घरेलू उद्योग के मुनाफे में न केवल वर्षवार बल्कि तिमाही वार भी अत्यधिक कमी आई है। मूल्यों में वृद्धि से किसी भी उद्योग के निष्पादन के संबंध में कोई संकेत नहीं मिलता है। कुल कारोबार में वृद्धि कच्चे माल में वृद्धि का परिणाम हो सकती है जैसी कि स्थिति टायर उद्योग और कार्बन ब्लैक उद्योग के मामले में है।
- ड) यह कि क्षमता में वृद्धि एक दीर्घावधि प्रक्रिया है जो सूक्ष्म आर्थिक तथ्यों के कारण होती है और वास्तविक संवर्धन की अवधि को अलग से नहीं देखा जा सकता है। घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद की देश में मौजूदा और सम्भावित मांग पर विचार करते हुए अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है। तथापि, संबंधित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में कमी आई है।
- च) इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर विचार घरेलू बाजार से जुड़े कार्बन ब्लैक के केवल रबड़ अनुप्रयोगों के संबंध में विचार किया गया।
- छ) याचिकाकर्ता कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार लाभ में वृद्धि कंपनी के समय निष्पादन के संबंध में है, जबकि वर्तमान जांच कार्बन ब्लैक के रबड़ अनुप्रयोगों के लिए घरेलू प्रचालनों के लिए है।

- ज) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त सूचना और यह सूचना जिस पर महानिदेशक (रक्षोपाय) ने भरोसा किया है केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। चूंकि घरेलू उद्योग ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पृथक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं इसलिए समग्र निष्पादन पर न तो भरोसा किया जा सकता है और न ही उस पर विश्वास करने की जरूरत है।
- झ) याचिकाकर्ता ने क्षति अवधि के दौरान इसकी संबंधित कंपनी से किसी भी वस्तु आयात नहीं किया है। तर्क पूर्णतया काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त तीसरे देशों से किए गए सामूहिक आयात में गिरावट आई है और चीन के आयातों में वृद्धि हुई है। चीन से आयातों में वृद्धि के अलावा कोई अन्य ऐसा कारण नहीं है जिससे क्षति हुई हो।
- ञ) आयातों में वृद्धि जुलाई - सितम्बर, 2011 से प्रारंभ हुई और आयातों में उद्रेक से घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में तेजी से कमी आई। इसलिए चीन से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ दोनों एक-दूसरे से प्रत्यक्षतः आनुपातिक नहीं हैं।
- ट) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में सी बी एफ एस कीमतों के आगे-पीछे उतार चढ़ाव आया है। वर्ष 2011-12 जो कि प्रोत्कर्ष अवधि है, में भी सी बी एफ एस की कीमतों में वृद्धि हुई। परन्तु घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत नहीं बढ़ा सका जिसके परिणामस्वरूप मुनाफे में कमी आई। वर्ष 2011-12 में आयात कीमत बढ़ गई, परन्तु यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा इसकी बिक्री लागत दोनों से बहुत न्यून रही।
- ठ) चीन जन गण के साथ हुई अभिगमन संधि में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि परिवर्ती उत्पाद - विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र अपवाद है और इसका उपयोग केवल दुरुह स्थिति में ही किया जाना चाहिए। ऐसा होते हुए भी घरेलू उद्योग के समक्ष उपस्थित हालात आपवादिक है जिनमें घरेलू उद्योग को मात्रा के रूप में भी गिरावट का सामना करना पड़ रही है।
- iii) चीन धातु, खनिज एवं रसायन आयातक एवं निर्यातक वाणिज्य चैम्बर तथा चीन रबड़ उद्योग एसोसिएशन
- क) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में निरापवाद रूप से क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई। इन आयातों में अभी हाल ही की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई। अभी हाल की अवधि आयातों में यकायक, तीव्र वृद्धि हुई। अभी हाल की अवधि आयातों में यकायक, तीव्र एवं भारी वृद्धि हुई। वार्षिक एवं तिमाहीवार दोनों आयात मात्रा दर्शाती है कि आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई।
- ख) वित्त वर्ष 12 की चौथी तिमाही में आयातों में कुछ कमी आई परन्तु इस अवधि के दौरान भी आयातों का स्तर पिछली तिमाही के स्तर की तुलना में उच्चतर स्तर पर रहा तद्वारा आयातों में भारी वृद्धि परिलक्षित हुई। किसी भी हाल में यह निर्णय करने के लिए कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है कि आयातों में इस समय वृद्धि हो रही है। आयात अभिनव विगत तक 'बढ़' सकते हैं परन्तु जरूरी नहीं है कि वे जांच की अवधि के अन्त तक या जांच निर्णय से तुरन्त पहले तक 'बढ़' रहे हों।
- ग) इस हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कि आई बी आई एस आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कराया है। सीमा शुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली 2002 में किसी ऐसी एजेंसी को परिभाषित नहीं किया है जहां से ये आंकड़े लिए जाने चाहिए परन्तु यह जांच प्राधिकारी के विवेक पर है कि वह कौन से आंकड़ों को विश्वसनीय समझता है। अतः यह विगत की जांचों में अपनाई गई स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है।
- घ) विमत में पी एक्स-13, एल्यूमिनियम एफ आर पी एंड फ्याइल, थैलिक एनहाइड्राइड आदि मामलों का अधिकार रहा है जिनमें महानिदेशक (रक्षोपाय) ने आई बी आई एस आंकड़ों पर भरोसा किया जाय।
- ङ) महानिदेशक ने जांच अवधि 2008-09 से 2011-12 की तृतीय तिमाही तक मानी है। इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्ष 2011-12 के संपूर्ण वर्ष को जांच में शामिल नहीं किया गया है, आंकड़ों का विश्लेषण

वार्षिक तथा तत्पश्चात तिमाही आधार पर किया गया। घरेलू उद्योग के तिमाही निष्पादन में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण तिमाही विश्लेषण को अधिक महत्व दिया गया।

- च) दोनों कच्चे पदार्थों की कीमत में बहुत अधिक अंतर है स्कीम में प्रचलित सी बी ओ कीमतें तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित सी बी एफ एस कीमतें। दोनों कच्चे पदार्थों की कीमत में यह अन्तर चीन के उत्पादकों को भारी लागत लाभ प्रदान करता है जिसके कारण चीन के न्यून कीमत वाले कार्बन ब्लैक उपभोक्ताओं को अधिक लाभप्रद हो गया। यह वह तथ्य है जो प्रस्तुत परिस्थितियों में अप्रत्याशित है और जिसके कारण भारत में कार्बन ब्लैक के आयातों में प्रबलता आई।
- छ) सी बी ओ और सी बी एफ एस के बीच कीमत अन्तर अप्रैल जून 2011 के आसपास से बढ़ना शुरू हुआ और जुलाई 2011 की अवधि के पश्चात यह अत्यधिक प्रभावकारी हो गया। तत्पश्चात, यह कीमत अन्तर लगातार बढ़ा। चीन में बाजार स्थिति पर उपलब्ध जानकारी दर्शाती है कि चीन में सी बी ओ की कीमतों में 2011 की पहली तिमाही से गिरावट आनी शुरू हो गई और तत्पश्चात इसमें अधिक गिरावट आई।
- ज) यह कि म० पी सी बी एल और म० हाई-टेक दोनों ही निर्यात केन्द्रित कंपनियां नहीं हैं। घरेलू बिक्री उनकी कुल बिक्री का प्रमुख हिस्सा बनी रही। इसके अतिरिक्त, विरोधी पक्षकारों ने अपने दावों के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी प्रदान नहीं की है।

झ. महानिदेशक(रक्षोपाय) के निष्कर्ष

19. मैंने मामले के रिकॉर्डों, घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्र द्वारा दायर उच्चतम का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उनसे उत्पन्न मुद्दों का इस निष्कर्ष में उचित स्थानों पर हल निकाला गया है।

(i) जांचाधीन उत्पाद

20. शामिल उत्पाद "कार्बन ब्लैक" है जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 28030010 के तहत वर्गीकृत किया गया है। कार्बन ब्लैक को एसिटिलिन ब्लैक, चैनल ब्लैक, फर्नेस ब्लैक, लैप ब्लैक, थर्मल ब्लैक तथा नॉयर डी कार्बन भी कहा जाता है। कार्बन ब्लैक को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - रबड़ तथा नॉन रबड़ एप्लिकेशन कार्बन ब्लैक। रबड़ अनुप्रयोगों हेतु कार्बन ब्लैक का प्रयोग रिड्फोर्सिंग फिलर के रूप में रबड़ (टायरों सहित) के उत्पादन/प्रसंस्करण में किया जाता है। वर्तमान याचिका रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के बड़े हुए आयातों के बारे में है। गैर-रबड़ अनुप्रयोगों, जैसे कॉपियर की स्याही तथा कम्प्यूटर प्रिंटर कार्टेज, पेंट, क्रेयोन तथा पॉलिश में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक वर्तमान जांच के दायरे के भीतर नहीं है।
21. यह नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण 280 30010 कार्बन ब्लैक के संबंध में है और इसमें सभी तरह का कार्बन ब्लैक शामिल है। तथापि वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद का दायरा केवल रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाने वाले कार्बन तक सीमित है। अतः सीमा शुल्क वर्गीकरण विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है।

(ii) घरेलू उद्योग:

22. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग(7)(क) में घरेलू उद्योग निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(क) "घरेलू उद्योग का आशय उन उत्पादकों से है जो -

- समान मद या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी मद का भारत में समग्र उत्पादन करते हैं।
- समान मद या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी मद का भारत में समग्र आउटपुट का भारत में उक्त मद के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है।

23. यह आवेदन मैसर्स एसोसिएशन ऑफ कार्बन ब्लैक मैन्यूफैक्चरर्स, 5ए राबा कैलाश, 55/4 बेलीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता द्वारा इसकी दो सदस्य कंपनियों मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, 31, नेताजी सुभाष रोड कोलकाता-700001 और मैसर्स हाईटेक कार्बन मुर्धवा इंक. एरिया पीओ रेणुकट, जिला सोनभद्र (30 प्र0) की ओर से दायर किया गया है। भारत में कार्बन ब्लैक के चार अन्य उत्पादक अर्थात् कान्टीनेन्टल कार्बन एण्डिया लिमिटेड, ए-14 इण्डस्ट्रियल एरिया बं0 1 साउथ साइड ऑफ जीटी रोड, गाजियाबाद-201001, राब्सन कार्बन ब्लैक लिमि0 जितवाला कलां, तहसील मलेरकोटला जिला संगरूर, पंजाब, कैबाट इण्डिया लिमिटेड एमआईडीसी प्लॉट नं0 3, ट्रान्स थाणे क्रीक एरिया थाणे बेलापुर रोड पोस्ट घनसोली थाणे-400701 महाराष्ट्र, हिमाद्रि कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय फार्चुना टॉवर 23-ए, नेताजी सुभाष रोड 8वां तल कोलकाता-700001. आवेदकों का भारतीय उत्पाद में 80% से अधिक का हिस्सा है और इसलिए वे प्रमुख उत्पादक हैं।

वित्त वर्ष	तिमाही	उत्पादन		अखिल भारतीय उत्पादक	हिस्सा	
		याचिकाकर्ता	अन्य भारतीय उत्पादक		याचिकाकर्ता	अन्य भारतीय उत्पादक
2008-09		416,244	97,598	513,842	81%	19%
2009-10		492,862	121,766	614,628	80%	20%
2010-11		585,899	108,823	694,722	84%	16%
2011-12	Q1	163,458	29,086	192,544	85%	15%
	Q2	148,188	28,367	176,555	84%	16%
	Q3	137,035	34,854	171,889	80%	20%
2011-12(A)		598,241	123,076	721,317	83%	17%

24. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी को मद्देनज़र यह निश्चय किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने यह याचिका दायर की है और जिन्होंने संगत जानकारी उपलब्ध कराई है, का उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। तदुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग(7)(क) के अनुरूप याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक हैं।

(III) जांच की अवधि (पी ओ आई)

25. सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली 2002 में स्पष्टतः यह परिभाषित नहीं है कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। तथापि, जांच की अवधि के मुद्दे का निराकरण कोरिया के विरुद्ध यू एस - लाइन पाइप केस में पैनल निष्कर्षों के अनुरूप किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया कि यह आयातक सदस्य के जांच प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि "जांच की अवधि" और उसका "समापन" कब और कितनी हो।

" हम नोट करते हैं कि करार में इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच की अवधि कितनी लंबी हो, और न ही यह उल्लेख है कि विश्लेषण के उद्देश्य से उस अवधि को भागों में किस तरह बांटा जाए। अतः, जांच की अवधि और इसके ब्रेकडाउन को जांच प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आई टी सी द्वारा चयनित अवधि पांच वर्ष एवं छः माह थी, यह अवधि अर्जेंटीना फुटवीयर सेफगार्ड में अर्जेंटीना के जांच प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की अवधि के बराबर है। तथापि हम नोट करते हैं कि अपील्य निकाय ने, अपने निर्णय में जांच अवधि की सीमा के प्रश्न पर तर्क देने के लिए कोरिया पर विश्वास किया और उन्होंने समयावधि पर जोर न देते हुए कहा कि अभिनव आयातों पर फोकस डाला जाना चाहिए, न कि जांच अवधि की प्रवृत्तियों पर लाइन पाइप मामले की जांच में आई टी सी ने केवल अंतिम बिन्दुओं की ही तुलना नहीं की बल्कि जांच की संपूर्ण अवधि में प्रचलित समग्र प्रवृत्तियों पर विचार किया (जैसा कि अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना - फुटवीयर सेफगार्ड मामले की जांच में किया था।) इसने आयात के संबंध में पूरे पांच वर्षों के लिए आयात आंकड़ों का वर्ष - दर - वर्षवार विश्लेषण किया और इस तथ्य पर भी विचार किया कि क्या अन्तरिम 1998 की तुलना में अन्तरिम 1999 में कोई वृद्धि हुई। हमारा विचार है कि आई टी सी ने जांच की अवधि पांच वर्ष और छह माह का चयन करके अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद xix के असंगत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है, प्रथम, इस करार में इस तरह का कोई विशिष्ट नियम नहीं है कि जांच अवधि कितनी होनी चाहिए; द्वितीय आई टी सी द्वारा चयनित अवधि में अभिनव आयातों पर विचार करने की अनुमति थी; और तृतीय संबंधित आयातों की मौजूदगी के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आई टी सी द्वारा चयनित अवधि काफी लंबी है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)

26. उक्त यू एस - लाइन पाइप मामले में पैनल ने निर्णय दिया कि:

" रक्षोपाय जांच में संवर्धित आयातों की जांच करने केवल जांच की अवधि वही रहती है जैसे कि घरेलू उद्योग का गंभीर क्षति की जांच करने के लिए रही है। पाटनरोधी अथवा समकक्ष शुल्क जांच में स्थिति इसके विपरीत होती है जहां पाटन या इम्पेदीकरण की उपस्थिति का मूल्यांकन करने की अवधि सामान्यतः भौतिक क्षति का निर्णय लेने के लिए जांच की अवधि से कम रहती है। हमारा विचार है कि इस भिन्नता के पीछे एक कारण यह है कि जैसा कि अर्जेंटीना - फुटवीयर सेफगार्ड मामले में अपील्य निकाय ने निर्णय किया है "क्या "इन संवर्धित मात्राओं में आयातों की अपेक्षाओं का निर्धारण केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं होता है।" अपील्य निकाय ने नोट किया कि जब संवर्धित आयातों का निर्धारण करने की बात आती है तो "सक्षम प्राधिकारियों से जांच की अवधि

से अधिक के आयातों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है।" आयातों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए संगत तथ्यों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन एक समयावधि में ही किया जा सकता है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वे विचार जो अपीलीय निकाय ने क्षति निर्धारण की संगत अवधि के बारे में व्यक्त किए हैं, संवर्धित आयातों का निर्धारण करने पर भी लागू होते हैं।"

27. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ने तो परिवर्ती रक्षोपाय से संबंधित घरेलू विधि, न ही रक्षोपाय करार और गाट का अनुच्छेद XIX, और न ही चीन जनवादी गणराज्य के अभिगमन प्रोटोकॉल में जांच की अवधि के संबंध में किन्हीं विशिष्ट दिशानिर्देशों का प्रावधान किया गया है। तथापि मौजूदा जांच की प्रकृति और उद्देश्य / प्रयोजन से यह स्पष्ट है कि संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से दीर्घ हो ताकि संबंधित आयात और बाजार विकृति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और यह केवल बहुत अभिनव समय तक सीमित न रहे बल्कि जांच की अवधि अत्यधिक निकट की अवधि होनी चाहिए।
28. विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लंबे इतिहास, वर्ष 2009 में वसूले गए पाटनरोधी शुल्क और इस लक्ष्य पर विचार करते हुए कि चयनित अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए जिससे कि संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और सीजनल विभिन्नताओं को निष्क्रिय किया जा सके, वित्त वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 (दिसम्बर तक) के आंकड़ों पर विचार किया गया है। जांच शुरूआत एवं प्रारम्भिक निष्कर्ष नोटिस में अक्टूबर, 2011 तक के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया था। अतः, आयात आंकड़ों को दिसम्बर, 2011 तक अद्यतन कर दिया गया है। जांच की अवधि को दिसम्बर 2008-09 से वर्ष 2011-12 की तृतीय तिमाही तक को माना गया है। इस तथ्य के आलोक में कि वर्ष 2011-12 के संपूर्ण वर्ष के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है, आंकड़ों का विश्लेषण वार्षिक और तत्पश्चात तिमाही आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग के तिमाही निष्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण तिमाही विश्लेषण को अधिक महत्व दिया गया।
29. भारत में कार्बन ब्लैक के आयातों की जांच संपूर्ण विचारित अवधि के लिए की गई। इसके अतिरिक्त, आयातों की पद्धति की तुलना घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचलों में यथाप्रदर्शित निष्पादन से की गई। भारत एवं चीन में बाजार विकास के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की भी जांच की गई। प्रमुख कच्चे माल - सी बी एफ एस तथा सी बी ओ की प्रकृति का भी जांच की अवधि के दौरान परीक्षण किया गया। यह देखा जा सकता है कि सी बी ओ और सी बी एफ एस की कीमतों में अंतर अप्रैल - जून 2011 से बढ़ना शुरू हो गया था और जुलाई, 2011 की अवधि के पश्चात यह ज्यादा हो गया। तत्पश्चात कीमतों में अंतर लगातार बढ़ता रहा। चीन में बाजार दशाओं के संबंध में उपलब्ध जानकारी यह दर्शाती है कि चीन में सी बी ओ की कीमतों में गिरावट वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही से आनी शुरू हुई और तत्पश्चात इसमें और तेजी से कमी आई। रिकार्ड में उपलब्ध समस्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त समझा गया कि वर्ष 2011-12 की दूसरी और तीसरी तिमाही को उद्रेक अवधि माना जाए। तदनुसार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नियमों के आशय के अन्तर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि हुई है या नहीं, इस अवधि के आयातों की जांच की गई और उनकी विगत वर्ष की अवधि के आयातों से तुलना की गई। इसके अतिरिक्त, अप्रैल - दिसम्बर, 2011 की पूरी जानकारी पर भी विचार किया गया और मौजूदा निर्णय के लिए उसकी विगत वर्ष से तुलना की गई। तथापि, चूंकि यह अवधि नौ माह की है, इसलिए निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना उनका वार्षिकीकरण करने के पश्चात की गई। यह निर्णय करने के लिए यह उपयुक्त माना गया कि क्या भारत में कार्बन ब्लैक के आयात में नियमों के आशय के

अन्तर्गत वृद्धि हुई है और क्या इन संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है, छह माह की अवधि पर्याप्त और काफी है।

IV सूचना का स्रोत:

30. विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्षक 28030010 के अन्तर्गत किया गया है। रक्षोपाय जांच वर्ष 2008-09 से 2010 - 11 तक के लिए डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों तथा शेष अवधि के लिए एक गौण आंकड़ा संग्रहण एजेंसी (आई बी आई एस) से घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई थी। प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग द्वारा गौण आंकड़ा संग्रहण एजेंसी (आई बी आई एस) से प्रदान कराए गए आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण अवधि के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त जानकारी की जांच की गई और यह पाया गया कि इसमें कुछ ऐसे उत्पादों के आयात को भी शामिल किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे हैं। अतः हालांकि याचिकाकर्ताओं ने आयातों को आई बी एस के अनुसार रिपोर्ट किया था जिसमें एच एस कोड 28030020 और 28030090 के अन्तर्गत किए गए आयात भी शामिल थे अन्वीक्षण के पश्चात एच एस कोड 28030010 के अंतर्गत आने वाले आयातों पर ही विचार किया गया। संबंधित आयातों का संगत अवधि के लिए विश्लेषण सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्षक 2803001 के अंतर्गत केवल 'रबड़ अनुप्रयोगों' के लिए कार्बन ब्लैक के आयात पर ही विचार किया गया।
31. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत अक्टूबर, 2011 तक के विभिन्न आर्थिक प्राचलों संबंधी आंकड़ों का इस निदेशालय द्वारा यथासंभव सीमा तक सत्यापन किया गया और सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ सार्वजनिक फाइल में रखा गया। इन सत्यापित आंकड़ों पर ही क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया। नवम्बर और दिसम्बर, 2011 के आंकड़ों को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर अंगीकार किया गया।
32. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा संबंधित आयातों के दावे का विरोध करते हुए आत्मनिवेदन किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत आयात मात्रा का कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी विरोध किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चलाई जा रही पाटन रोधी मध्यावधि समीक्षा जांच में प्रस्तुत आत्मनिवेदनों का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया है कि पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत आयात मात्रा महानिदेशक द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों में भरोसा की गई आयात मात्रा से काफी भिन्न है। घरेलू उद्योग ने अधोहस्ताक्षरी तथा पाटनरोधी निर्दिष्ट प्राधिकारी - दोनों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया है कि पाटनरोधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके आत्मनिवेदनों में रिपोर्ट की गई आयात मात्रा में टंकण संबंधी त्रुटि है। जहां तक डी जी (रक्षोपाय) के समक्ष प्रस्तुत अपने आवेदन में (वर्ष 2011-12) की द्वितीय तिमाही के आंकड़ों अर्थात् 25772 का संबंध है, यह सत्य है कि रक्षोपाय याचिका में भी इसी मात्रा का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस कार्यालय द्वारा (2011-12) की द्वितीय तिमाही के लिए अंगीकृत 25686 मी० टन के आंकड़े किए गए सत्यापन पर आधारित हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संवर्धित आयातों के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों का विरोध करने वाले इन पक्षकारों में से किसी ने भी भारत में कार्बन ब्लैक के सकल आयात के संबंध में विचारार्थ कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्रश्नावलियों के उत्तर निम्नलिखित विदेशी उत्पादको से प्राप्त हुए थे।

- क. जियान्गक्सी ब्लैक कैट कार्बन इंक. लिमि० चीन (निर्यातक प्रश्नावली)
33. इसके अतिरिक्त भारत में निम्नलिखित आयातकों / उपभोक्ताओं से भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।
- क. अपोलो टायर्स (आयातक प्रश्नावली)
- ख. सिएट टायर्स (आयातक प्रश्नावली)
- ग. जे के टायर एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आयातक प्रश्नावली)
- घ. फिनिक्स कन्वेयर बेल्ट इंडिया (प्रा०) लिमि० (आयातक प्रश्नावली)
34. प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों और आयातकों/उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान करायी गई आयात संबंधी जानकारी की भी जांच एवं विश्लेषण किया गया। यह नोट किया गया कि इन पक्षकारों ने केवल अपनी गतिविधियों के संबंध में ही जानकारी दी है। इनमें से किसी भी पक्षकार ने चीन और तृतीय देशों से भारत में कार्बन ब्लैक के सकल आयात के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। चूंकि देश में इस उत्पाद के सकल आयात से संबंधित जानकारी अपेक्षित थी इसलिए प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों या आयातकों / उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी पर आयात की मात्रा का निर्धारण करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सका। आयात मात्रा के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों का विरोध करते हुए मैंने पाया कि ए टी एम ए ने चीन और तृतीय देशों से भारत में कार्बन ब्लैक के कुल आयातों के संबंध में कोई सत्यापन योग्य दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
35. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने आई बी आई एस आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी तर्क प्रस्तुत किया है। तथापि, उन्होंने यह दर्शाने की लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आई बी आई एस आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। सीमा शुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 में विशेषकर किसी ऐसी एजेंसी को परिभाषित नहीं किया गया जिससे आयात आंकड़ा लिया जाना चाहिए, परन्तु यह जांच प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि वह उनके पास उपलब्ध आंकड़ों पर विचार करे। विगत में ऐसे मामले भी हैं जिनमें इस निदेशालय ने आई बी आई एस आंकड़ों पर भरोसा किया है। अतः कार्रवाई स्तर पर संपूर्ण जांच के पश्चात् आई बी आई एस आंकड़ों पर आयात आंकड़ों के स्रोत के रूप में विश्वास करना विगत की जांचों में अपनाई गई सुस्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है।
- (iv) प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता:
36. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर कुछ सूचना दी है और प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों पर गोपनीयता मांगी है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 6.9.1997 की व्यापार सूचना सं. एसजी/टीएन/1/97 और सुरक्षोपाय नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सुरक्षोपाय लागू करने के लिए आवेदन के गैर-गोपनीय पाठ को दिया था। इसके अलावा, आवेदन करते समय गोपनीयता प्राप्त करने के लिए घरेलू उद्योग ने कारण प्रस्तुत किए हैं।
37. अन्य इच्छुक पार्टियों ने भी कुछ जानकारी गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की है और सूचना की गोपनीयता के लिए अनुरोध किया है और प्रस्तुत की गई सभी सूचनाओं के गैर-गोपनीय पाठों को प्रस्तुत किया है। तथापि, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा मांगी गई अत्यधिक गोपनीयता का विशेष किया है। घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और तर्क दिया है कि सार्थक तर्क तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब आर्थिक प्राचलों पर वास्तविक आंकड़ों का हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष खुलाशा किया जाए। इन हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ऐसी सूचना के संबंध में गोपनीयता प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
38. सीमा शुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 के नियम 7 और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.2 में कुछ जानकारी को गोपनीयता प्रदान करने के

भारे में प्रावधान है। (चीन जनवादी गण राज्य की अभिग्रहण संधि के अंतर्गत इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है)। इन नियमों में प्रावधान है कि हितबद्ध पक्षकार से ऐसी जानकारी का वास्तविक आधार पर खुलासा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो कंपनी की गोपनीय जानकारी है और जिसका खुलासा उक्त पक्षकार के वाणिज्यिक हितों के प्रति ऐसी गंभीर पूर्वावधारणा का कारण बन सकती जो सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्रों में नहीं है और जिसका याचिकाकर्ता ने जख्ता के समक्ष पहले कभी खुलासा नहीं किया है।

39. तदनुसार, मैंने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यथासमय मांगी गई गोपनीयता के अनुरोध पर विचार किया है और उक्त नियम के प्रावधानों के अंतर्गत उसे स्वीकार कर लिया है।

VI. इससे पहले किए गए पाटनरोधी उपाय:

40. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का अभिज्ञान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अन्तिम निष्कर्ष 24 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं० 14/21/2008 - डी जी ए डी के तहत अधिसूचित किए थे और चीन जन गण, आस्ट्रेलिया, रूस एवं थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'रबड अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाने वाले कार्बन ब्लैक' के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं० 6/2010 - सीमा शुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। यह जांच 1 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ करके 30 सितम्बर, 2008 तक की 12 माह की अवधि को "जांच अवधि" के रूप में मानते हुए की गई थी और इसी विश्लेषण अप्रैल, 2005 - मार्च 2006, अप्रैल 2006 मार्च, 2007, अप्रैल 2007 - मार्च 2008 और अक्टूबर 2007 से सितम्बर, 2008 की अवधि पर विचार करते हुए किया गया था।
41. पाटनरोधी संबंधी निर्दिष्ट प्राधिकारी की इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इस उत्पाद के आयात पर दिनांक 28 जनवरी 2010 की अधिसूचना सं० 6/2010 - सीमा शुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है।
42. तत्पश्चात्, मै० ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएसन, मै० ऑटोमोटिव कार मैनुफैक्चर्स एसोसिएसन (ए टी एम ए) ने इस उत्पाद के आयात पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अनुसार मध्यावधि समीक्षा शुरू करने का अनुरोध करते हुए पाटनरोधी एवं सहबद्ध शुल्क निदेशालय के समक्ष एक आवेदनपत्र दायर किया था। ए टी एम ए द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन गण आस्ट्रेलिया, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबंध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा दिनांक 30 अगस्त 2011 की अधिसूचना सं० 15/41/2010-डी जी ए डी के तहत शुरू की थी। ऊपर उल्लिखित मध्यावधि समीक्षा की जांच अवधि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च, 2011 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 की अवधि भी शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अभी तक इस समीक्षार्थ अपना अन्तिम निर्णय नहीं दिया है।
43. निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी के समक्ष दायर आवेदन ए टी एम ए के इस दावे पर आधारित है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है और पाटनरोधी शुल्क उन्हीं रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1) में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने का प्रावधान है और यह उल्लेख करता है कि

निर्दिष्ट प्राधिकारी आवश्यकता पड़ने पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की निरन्तरता की जरूरत की समीक्षा यह तो स्वयं अपनी पहल पर या उन हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर शुरू करेंगे जो इस समीक्षा की जरूरत के संबंध में साक्ष्यांकित सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करते हैं और ब्रियर्याक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से अब तक काफी समयावधि बीत चुकी है और इस समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है या उसे कमोवेश किया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली छति बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और अतः इसे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, उक्त समीक्षा करने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से पाटनरोधी शुल्क वापस लेने की सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी ने निम्नलिखित अभिकथन किया है।

समीक्षा के लिए आधार

5. आवेदक ने निवेदन किया है कि कार्बन ब्लैक की आयात कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है 0 यह कि घरेलू बिक्री कीमत में भी बहुत वृद्धि हुई है; यह कि कच्चे माल-कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक (सी बी एफ एस) की कीमत में बहुत अधिक गिरावट आई है और यह कि प्रमुख कच्चे माल की कीमत में कमी आई है और घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) में अत्यधिक कमी आई है। याचिकाकर्ता ने इसके अग्रे निवेदन किया कि आयात कीमतों में अत्यधिक बंदोत्तरी के साथ-साथ आयात की लैण्डिड कीमत में भी वृद्धि हुई है, क्षति मार्जिन घट गया है और इसके परिणामस्वरूप शुल्क के मौजूदा स्तर की समीक्षा करने की जरूरत उत्पन्न हो गई है।

जांच अवधि (पी ओ आई)

10. जांच अवधि के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 है। तथापि क्षति जांच अवधि में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और जांच अवधि (2010-11) शामिल होगी।

44. इस प्रकार, यह ए टी एस ए (और चीन के निर्यातकों) के मामले में हुआ कि अप्रैल 2010-मई 2011 की अवधि के दौरान उत्पाद का पाटन नहीं किया जा रहा था और यह कि घरेलू उद्योग को इस अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई। घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी के समक्ष (प्रस्तुत जांच शुरूआत पश्चात निवेदन लिखित निवेदन और प्रत्युत्तर निवेदनों) की एक प्रति उपलब्ध कराई है। फलस्वरूप, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में उद्रेक आना 2011-12 की पहली तिमाही से शुरू हुआ था और अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन की लिए जुलाई-दिसंबर, 2011 को उद्रेक अवधि के रूप में माना है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच की लिए विचारणीय जांच अवधि निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी द्वारा विचार की जा रही उत्पादों की जांच अवधि से भिन्न है।

(VII) संवर्धित आयात

45. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 में रक्षणीय शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्तावित शर्तों का उल्लेख है और उसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- "1. धारा 8 में उल्लिखित किसी बस्त के होते हुए भी, यदि केन्द्र सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे लिए जांच के प्रारम्भ इस तथ्य से संतुष्ट है कि भारत में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित बस्त यस्तु इसकी अधिक मात्रा में है और यह आयात उन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया गया है

जिनसे घरेलू उद्योग की बाजार विकृति होती है अथवा बाजार विकृति की चुनौती उत्पन्न होती है तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।”

46. इन नियमों में रक्षोपाय का प्रयोग करने के लिए आयातों की अधिकता आधारभूत प्रवापेक्षा होती है। इस प्रकार यह निर्णय लेने के लिए कि क्या आयातों में “इस हद तक बढ़ोत्तरी हो गई है कि रक्षोपाय साधन का सहारा लिया जाए, इसलिए नियमों में इस बात की अपेक्षा की गई है कि आयातों में वृद्धि की राशि और दर का विश्लेषण समग्ररूप से और घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में किया जाए जैसा कि पैनल ने निर्धारण किया है और तत्पश्चात अर्जेन्टीना – फुटवीयर मामले में अपीलीय निकाय ने भी इसकी सम्पुष्टि की है।

47. अर्जेन्टीना – फुटवीयर मामले में पैनल ने अपने इस मुल्यांकन में कि क्या अर्जेन्टीना के प्राधिकारियों द्वारा जांच में अनुच्छेद 2.1 और 4.2 (क) के अंतर्गत आयात में अपेक्षित वृद्धि का प्रदर्शन किया है, यह उल्लेख किया कि

“..... करार में आयातों में न केवल वृद्धि (या किसी वृद्धि) की अपेक्षा नहीं है बल्कि वृद्धि “ऐसी मात्रा” में होनी चाहिए जो गंभीर क्षति कारित कर सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर सके। इस करार में किसी ऐसे संख्यात्मक मार्ग दर्शन का प्रावधान नहीं है कि इसका निर्णय कैसे किया जाएगा और हमारे विचार से न ही ऐसा किया जा सकता है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि यह अपेक्षा निरर्थक है। इसके विपरीत हमें विश्वास है कि इसका आशय है कि आयातों में वृद्धि का निर्णय इसके पूर्ण संदर्भ में, खासकर अनुच्छेद 4.2(क) द्वारा यथापेक्षित इसकी “दर और राशि” के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अतः यह निर्णय करते समय कि आयातों में वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के अनुसार “ऐसी मात्रा में हुई है” कि संपूर्ण जांच अवधि में आयात के स्तर में हुए परिवर्तन पर विचार किया जाना, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपरिहार्य प्रतीत होता है।

48. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन परिवर्ती रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 2(iii) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“संवर्धित मात्रा” में घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों में समग्र रूप से या संगत रूप से वृद्धि शामिल है।

49. उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में कार्बन ब्लैक के आयातों में वृद्धि का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि चीन जन गण से कार्बन ब्लैक (रबड़ अनुप्रयोगों के लिए) के भारत में आयातों में समग्र और संगत दोनों रूपों में तीव्र वृद्धि प्रदर्शित हुई। यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन गण से आयातों में वृद्धि की दर चीन जनगण से भिन्न अन्य देशों से आयात की तुलना में काफी अधिक है जिससे घरेलू उद्योग को बाजार विकृति हो रही है अथवा बाजार विकृति की चुनौती उत्पन्न हो गई है।

क) निरपेक्ष संदर्भ में चीन से आयात में वृद्धि

50. विचाराधीन उत्पाद का आयात, निरपेक्ष संदर्भ में क्षति की पूरी अवधि के दौरान बढ़ा है। हाल ही की अवधि के दौरान आयातों में अचानक, अधिक और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में चीन से किया गया 12971 एमटी का आयात वर्ष 2011-12 (वार्षिक आधार पर) में बढ़कर 77804 एमटी हो गया जो 600% का द्योतक है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 (ए) में चीन से आयात में अचानक 465% की वृद्धि हुई है तथापि समसामयिक अवधि के दौरान कुल आयातों में केवल 173% की वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष	तिमाही	चीन से आयात (मीटन.)	कुल आयात (मीटन.)	चीन से आयात का प्रतिशत
		वार्षिक	तिमाही	

2008-09		12971		39187	33
2009-10		17722		63244	28
2010-11		16724		61185	27
2011-12	Q1		5789	14828	39
	Q2		25686	32465	79
	Q3		26878	31972	84
2011-12(A)		77804		105686	74

51. वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2009-10 आयातों में कमी संघट्टित वस्तु पर 30 जुलाई 2009 (अन.) की अधिसूचना सं 2010, जनवरी 28 और सीमाशुल्क-2009/83 (अन्तिम) की अधिसूचना सं 06/2010 सीमा शुल्क के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण हुई। चूंकि पाटनरोधी शुल्क 28 जन. 2010 से प्रभावी हुआ इसलिए 2010-11 में आयात की मात्रा वही प्रदर्शित करती है।
52. उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि चीन से कार्बन ब्लैक के आयात समग्र रूप में तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन से कार्बन ब्लैक का समग्र आयात वर्ष 2008-09 में आयातित कुल 12971 मी.टन की मात्रा से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 77804 मी० टन हो गए। वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में चीन से आयात 5789 मी० टन हुए थे जो वर्ष 2011-12 दूसरी तिमाही में बढ़कर 25686 मी० टन हो गए। इसके अतिरिक्त चीन जन गण से आयातों में वर्ष 2011-12 की की दूसरी तिमाही और वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में अत्यधिक वृद्धि हुई।
53. चीन से आयातों में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद का विभिन्न स्रोतों से समग्र आयात जो वर्ष 2008-09 में 39187 था बढ़कर वर्ष 2011-12 में 105686 हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 पहली तिमाही में विभिन्न देशों से समग्र आयात 14828 थे, बढ़कर वर्ष 2011-12 की द्वितीय तिमाही में 32465 मी० टन और वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में 31972 हो गए। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद का समग्र औसत आयात जो वर्ष 2008-09 में 9797 प्रति तिमाही था, वर्ष 2009-10 में बढ़कर 15811 हो गया, वर्ष 2010-11 में इसमें थोड़ी सी कमी आई और यह 15296 हो गया परन्तु तत्पश्चात 2011-12 की पहली दूसरी और तिमाही में इसमें जबरदस्त उछाल आया और यह क्रमशः 14828, 32465 तथा 31972 हो गया।

54. तृतीय देशों से आयात निम्नलिखित थे

वित्त वर्ष	तिमाही	चीन से आयात मी० टन		तृतीय देशों से		कुल आयात (मी० टन)	तृतीय देशों से आयात का प्रतिशत
		वार्षिक	तिमाही	वार्षिक	तिमाही		
2008-09		12971		26216	6554	39187	66.90
2009-10		17722		45522	11381	63244	71.98
2010-11		16724		44461	11115	61185	72.67
2011-12	Q1		5789		9039	14828	60.96
	Q2		25686		6779	32465	20.88

	Q3		26878		5004	31972	15.98
2011-12(A)		77804		27882		105686	26.38

55. यह देख जा सकता कि वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही तक भारत में कार्बन ब्लैक के कुल आयात में तीसरे देशों के आयात का अनुपात बहुत अधिक रहा। तथापि, चीन से आयात में उद्रेक के कारण तृतीय देशों के हिस्से में बहुत अधिक विसरट आई तथा वर्ष 2011-12 की दूसरी और तीसरी तिमाही में तृतीय देशों से समूहिक आयात क्रमशः 21% और 16% रहा।
56. यह नोट किया जाता है कि आयात में उद्रेक इतना अधिक था कि पाश्चात्यी शुल्क लगाने के बाद तृतीय देशों से आयात में काफी आने के बावजूद भारत में विद्यमान उत्पाद के समान आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई।

(ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में भारत में वृद्धि

57. भारत में चीन के कार्बन ब्लैक का आयात घरेलू उद्योग के भारतीय उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ा है। चीन जन गण से बड़े हुए अस्थिरता के कारण अभी हाल ही की अवधि (2011-12) में सकल रूप में घरेलू उद्योग के उत्पादन में विसरट आई है। यह देखा जा सकता है कि चीन से कार्बन ब्लैक के आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2008-09 और वर्ष 2010-11 के दौरान न्यूनतम स्तर पर (3-4% के बीच) रहे। तथापि, उसके बाद वर्ष 2011-12 में आयात इससे तेजी से बढ़े कि भारतीय उत्पादन की तुलना में आयात बढ़कर 13% हो गए।

वित्त वर्ष	तिमाही	चीन से आयात (मी टन)	उत्पादन (मी टन)	घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन से आयात का प्रतिशत
2008-09		17722	402863	3
2009-10		16724	585899	3
2010-11		5799	163456	4
2011-12	Q1	26886	148188	17
	Q2	26878	137035	20
	Q3	77804	508241	13
2011-12(A)				

(ग) खपत/मांग के संबंध में आयात

58. एक निश्चित अवधि के दौरान इस तरह निर्धारित मांग/ खपत में बदलाव की तुलना विभिन्न देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तियों में हुए परिवर्तनों से की गई जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या भारत में कार्बन ब्लैक के आयात में देश में हुए उत्पाद के लिए खपत या मांग के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
59. चीन उत्पादित कार्बन ब्लैक का भारत में आयात, भारत में कार्बन ब्लैक की खपत के संबंध में बहुत तेजी से बढ़े। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 और वर्ष 2010-11 के दौरान चीन से कार्बन ब्लैक के आयात न्यूनतम स्तर (3%) पर रहे। तथापि, उसके बाद वर्ष 2011-12 में आयात इससे तेजी से बढ़े कि भारत में होने वाली खपत की तुलना में आयात बढ़कर 11% हो गए।

वित्त वर्ष	तिमाही	चीन से आयात (मी.टन)	कुल मगन/खपत (मी.टन)	घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन से आयात का %
2008-09		12971	460678	3
2009-10		17722	582930	3
2010-11		16724	614152	3
2011-12	Q1	5789	180228	4
	Q2	25686	164671	16
	Q3	26878	165321	16
2011-12 (Total)		77804	653627	11

60. घरेलू खपत की तुलना में चीन से आयातों में वर्ष 2010-11 में 3% वृद्धि तथा वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में 4% की वृद्धि हुई। तथापि, तत्पश्चात्, घरेलू खपत की तुलना में चीन से आयातों में वर्ष 2011-11 की द्वितीय तिमाही तथा तृतीय तिमाही में 16% की वृद्धि हुई। अतः यह देखा जा सकता है कि घरेलू खपत की तुलना में चीन से भारत को कार्बन ब्लैक के आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई।
61. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, यह पाया गया है कि चीन पीआर से कार्बन ब्लैक का आयात निरपेक्ष और प्रासंगिक संदर्भों में बढ़ा है और यह कि यह वृद्धि हाल में अचानक, पर्याप्त, तेजी और महत्वपूर्ण रूप से हुई है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 के अन्वये के अंतर्गत "बड़ा हुआ आयात" है।
62. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि सितंबर और अक्टूबर, 2011 में आयातों में वृद्धि एक प्रवृत्ति नहीं बल्कि यह एक यथार्थक होने वाली घटना है। यह पाया गया कि विद्यमान अर्थव्यवस्था के आयातों में क्षति अवधि में समग्र रूप में वृद्धि हुई जबकि इसमें अभी हाल की अवधि में अत्यधिक वृद्धि हुई। अभी अतिरिक्त अवधि में आयातों में अत्यधिक तीव्र एवं अत्यधिक वृद्धि हुई। चीन से आयात जो वर्ष 2008-09 में 12971 एम टी थे वृद्धि के वित्त वर्ष 2011-12 (ए) में 77804 मीटो टन हो गए जो भारी वृद्धि दर्शाती है। आयातों में वृद्धि विश्लेषण केवल दो महीने के आंकड़ों पर आधारित नहीं है। जहाँ तक कि वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है।

(viii) अप्रत्याशित विकास

63. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के इस निवेदन से महा निदेशक (रक्षोपाय) को अप्रत्याशित परिस्थितियों का विश्लेषण करने का कोई अभिव्यक्त दायित्व/ अपेक्षा नहीं है क्योंकि भारतीय निषेधों या चीन जनवादी गणराज्य की प्रणाली विज्ञान संबंधी अभिगृहण संधि में ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है जिसका अप्रत्याशित विकास का विश्लेषण करने के लिए अनुकरण किया जाना चाहिए और न ही ऐसा कोई प्रमाण है जिसे अप्रत्याशित विकास का निर्धारण करने हेतु पूरा किया जाना चाहिए। तथापि, यह ध्यान में रखा है कि उन हालातों की जांच करना महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से आयातों में वृद्धि हुई।
64. अर्थव्यवस्था - पुनर्वसन (ई सी) और कोरिया - जपान में आपसी विवाद ने यह धारित किया कि उद्योग टी अंतःक्षेत्र के प्रभाव होने के कारण अधिपोषित प्रत्येक रक्षोपाय को रक्षोपाय संबंधी दोनों मामलों और गाट 1994³ के अनुच्छेद XIX दोनों के प्राधान्यों का अनुपालन करना पड़ेगा।
65. मॉट 1994 के अनुच्छेद XIX में उल्लेख किया गया है कि

1. (क) यदि, अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप और इस कसर, टैरिफ रियायतों सहित, के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा अपने ऊपर लिये गये इसी दायित्व के प्रभावस्वरूप यदि किसी उत्पाद का आयात संविदाकारी पक्षकार के भूभाग में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसे हालातों में किया जाता है कि उस भूभाग में उसके समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होती है तो संविदाकारी पक्षकार इन उत्पादों के संबंध में उस सीमा तक और ऐसे समय तक आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा जो ऐसी खति को रोकने या उसका उपचार करने के लिए आवश्यक हो तथा वह अपने संपूर्ण या आंशिक दायित्व को समाप्त करने या रियायतों को वापस लेने या उसमें संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

66. अर्जेंटीना - फुटवियर (इ सी मामला) में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अप्रत्याशित विकास वाक्यांश का आशय ऐसे विकास से है जो अप्रत्याशित रूप से हुआ हो। 'अप्रत्याशित विकास' अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण उत्पाद का आयात इतनी बड़ी हुई मात्रा में और ऐसे हालात में किया जा रहा है जिससे कि घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है, वह अप्रत्याशित होना चाहिए। निकाय ने उसी मामले में एक गाट पैनल रिपोर्ट को नोट किया जिसमें यह कहा गया कि वह विकास टैरिफ वार्ताओं के समय अप्रत्याशित होना चाहिए। कोरिया - डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि अप्रत्याशित विकास वे विकसस हैं जो सदस्य द्वारा दी गई बचनबद्धता के समय प्रत्याशित न हों।
67. अर्जेंटीना में अपीलीय निकाय - फुटवियर(ईसी) ने तब यह माना कि 'अप्रत्याशित विकास' की जरूरत, सुरक्षोपायों को अधिरोपित करने के लिए पृथक "शर्त" स्थापित नहीं करती है लेकिन "परिस्थितियों" की कतिपय शर्तों का वर्णन करती है।

68. यूएस-स्टील सुरक्षोपायों के पैनल का मानना है कि कई घटनाओं के मिल जाने से अप्रत्याशित विकास का आधार बन जाता है।

"यूनाइटेड स्टेट इस बात पर जोर देता है कि यूएस डॉलर का मजबूत हो जाना एक विकास था जो एशिया और पूर्व यूएसएसआर में मुद्रा के अभाव और दूसरे बाजारों द्वारा स्टील से इंकार कर दिए जाने के कारण 'यूनाइटेड स्टेट' में स्टील की बढ़ती मांग जैसी दूसरी गतिविधियों के साथ मिलकर अत्यंत बढ़ने का कारण बना।"

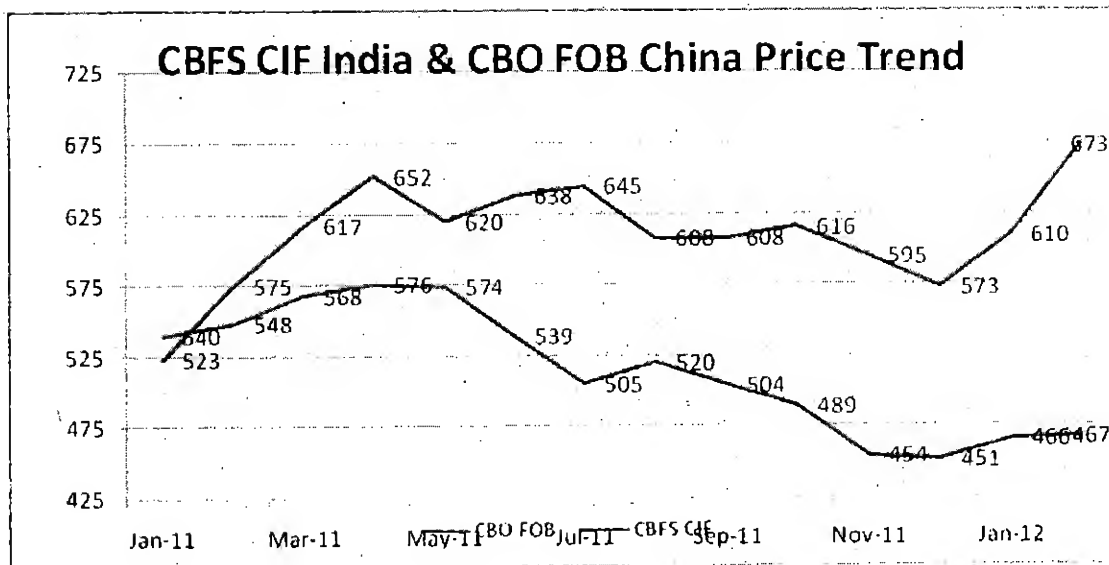
69. याचिकाकर्ता ने डीआई सहित दूसरे देशों द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल की तुलना में चीन द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल की कम कीमत की ओर संकेत किया और इसका बढ़ता अंतर अप्रत्याशित विकास माना। यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग, कार्बन ब्लैक का विनिर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में सीबीएफएस (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक) का उपयोग करते हैं जबकि चीनी उत्पादकर्ता सीबीओ (कार्बन ब्लैक ऑयल) का उपयोग करते हैं। इन दो कच्चे मालों की कीमत में अत्यधिक अंतर है। दो सामग्रियों के कच्चे माल की कीमतों में अंतर, चीनी उत्पादकों को लगभग लाभ प्रदान करती है जिसके कारण चीनी कार्बन ब्लैक की कम कीमतें होती हैं।

70. कार्बन ब्लैक उद्योग में कच्चा माल ही कार्बन ब्लैक का उत्पादन करने में सबसे अधिक खर्चीला सामान है। इस प्रकार कार्बन ब्लैक की कीमत की प्रवृत्ति का निर्णय करने में कच्चे माल की कीमत मुख्य भूमिका निभाती है। कीमत प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के बाद यह देखा जाएगा कि क्षति की पूरी अवधि में सीबीओ और सीबीएफएस के बीच कीमत में अंतर रहा है और जून, 2011 के माह से सीबीओ की कीमतें गिरनी शुरू हो गईं और इसी बीच सीबीएफएस की कीमत बढ़नी शुरू हो गईं जिसे

नीचे दिए गए विवरण से देखा जा सकता है।

घरेलू उद्योग ने सी बी ओ और सी बी एफ एस की कीमतों निम्नलिखित प्रवृत्ति का दावा किया है।

	चीन का सी बी ओ एफ ओ बी अमरीकी डालर / मी० टन	सी बी एफ एस सी आई एफ भारत, अम०डा०/मी० टन	भारत और चीन सी बी ओ, सी बी एफ एस सी आई एफ के बीच अन्तराल अमरीकी डालर/ मी० टन
Jan-11	540	523	(17)
Feb-11	548	575	27
Mar-11	568	617	50
Apr-11	576	652	75
May-11	574	620	46
Jun-11	539	638	99
Jul-11	505	645	140
Aug-11	520	608	88
Sep-11	504	608	104
Oct-11	489	616	126
Nov-11	454	595	141
Dec-11	451	573	122
Jan-12	466	610	144
Feb-12	467	673	206



सी बी एफ एस की आई एफ इंडिया एवं सी बी ओ एफ ओ बी चीन की कीमत रुझान

71. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बी ए आई आई एन एफ ओ कोल कैमिकल वीकली (1 जून से 7 जून, 2012 तक की रिपोर्ट) की जांच की गई। प्रकाशित रिपोर्ट सुझाती है कि चीन में निर्माण कंपनियों को चीन की सरकार की नीति के कारण मंदी का सामना करना पड़ रहा है इसके परिणामस्वरूप कोलतार, औद्योगिक नेफ्थालीन तथा एन्धासीन आयल की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई।
72. रिपोर्ट यह भी सुझाती है कि चीन में सी बी ओ की क्रय कीमत चीसन बाजारों के लिए कम हो गयी। यह भी देखा जाता है कि वर्ष 2011 में चीन का कुल कार्बन ब्लैक उत्पादन उसकी कुल मांग से कहीं अधिक रहा जिससे आने वाली अवधि में चीन से निर्यातों में बढोत्तरी का संकेत मिलता है।

73. इस प्रकार, रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य दर्शाता है कि कार्बन ब्लैक के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल की सी बी एफ एस जैसे कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक रूप से वृद्धि वहीं चीन की बाजार में उसमें गिरावट आई। चूंकि उत्पादन लागत का अधिकांश हिस्सा कच्चे माल की लागत होती है (कुल उत्पादन लागत का लगभग 80% कच्चे माल की लागत होती है) इसलिए चीन के तथा अन्य देशों के उत्पादकों की कीमत में भिन्नता के कारण घरेलू उद्योग तथा चीन के निर्यातकों के लागत ढांचे में भीषण भिन्नता थी। परिणामस्वरूप, चीन के उत्पादकों द्वारा भारत को निर्यात के बारे में अपनी कीमतों में वृद्धि कर दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं (अपनी लागत में कमी करने के बावजूद) को नुकसान हो रहा है क्योंकि निर्यातों की लैण्डिड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम रही। घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत अन्तराल के कारण भारत में चीन से कार्बन ब्लैक के आयात में उद्रेक आया।

	सीबीओ एफओबी कीमत	सीबी एफएस कीमत	एडीडी सहित कार्बन ब्लैक आयात कीमत (रुपया प्रति मी.टन)					
माह	RS./MT	Rs./MT	china	Australia	Korea (No ADD)	Thailand	Russia	Selling price Domestic Industry (Indexed)
11-अप्रैल	26,044	29,457	56,012	67,492	60,766	61,781	56,683	100
11-मई	25,814	27,878	59,410	65,813	60,596	60,611	59,540	102
11-जून	24,621	29,136	60,144	66,448	79,838	65,184	57,238	101
11-जुला	22,993	29,342	61,890	74,700	74,197	64,787	58,117	104
11-अग.	23,264	27,198	60,676	77,415	72,906	65,390	---	107
11-सि.	23,459	28,313	62,010	80,508	73,244	81,266	60,507	107
11-अ.	24,278	30,547	65,646	85,015	78,138	84,048	67,362	108
नव. 11	22,725	29,770	69,720	79,403	91,707	-	70,576	106
दिस 11	23,740	30,129	70,615	-	86,931	-	76,226	105

74. हाल में घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं लेकिन इसी बीच चीन ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दीं। लेकिन ऐसी वृद्धि के बावजूद, चीन और तीसरे विश्व के देशों द्वारा उद्धृत कीमत, घरेलू उद्योग की कीमतों से कहीं कम हैं। कार्बन ब्लैक के उन अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों की कीमत, जो कच्चे माल के रूप में सीबीएफएस का इस्तेमाल करते हैं अर्थात् रूस, कोरिया, आस्ट्रेलिया और थाइलैंड, उन्होंने भी उसी अवधि के दौरान अर्थात् जून, 2011 से आगे कीमत बढ़ानी शुरू कर दी और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों की तुलना में वे समरूप या उनसे अधिक बनी रहीं हैं। यह नोट किया जाता है कि यह वह अवधि थी जब चीन से अत्यधिक ऊंचे स्तर पर आयात शुरू हो गया था और जिसने कम कीमत का प्रस्ताव करके भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया था।

75. अभी हाल ही में अप्रैल, 2011 से अक्टूबर, 2011 की अवधि के लिए कच्चे माल की कीमत में के परिणामस्वरूप चीन से सस्ते कार्बन ब्लैक का आयात हुआ तथ उसने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। जिससे ऐसी बाजार स्थिति उत्पन्न हो गई जिसका सुधार असंभव था।
76. यह स्पष्टतः दर्शाता है कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के बावजूद चीन अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा और फिर भी वे अन्य निर्यातकों की तुलना में अपना माल सस्ती कीमतों पर बेच रहे थे क्योंकि कच्चे माल की कीमत में अन्तर का चीन के कार्बन ब्लैक के उत्पादकों को लाभ मिल रहा था।
77. कच्चे माल में कीमत भिन्नता निम्नवत् देखी जा सकती है:-

	चीन सीबीओ एफओबी अम/डालर0 मीटन.	सीबीएफएस सीआईएफ भारत अम/डालर0 मीटन.	सीबीएफएस सीआईएफ भारत और चीन सीबीओ के बीच अंतर अम/डालर0 मीटन.
जन-11	540	523	(17)
फर-11	548	575	27
मार्च-11	568	617	50
11-अप्रैल	576	652	75
11-मई	574	620	46
11-जून	539	638	99
11-जुला	505	645	140
11-अग.	520	608	88
11-सि.	504	608	104
11-अ.	489	616	126
11 नव	454	595	141
11 दिस	451	573	122

78. चीनी उत्पादकों ने उत्पादन की अत्यधिक क्षमताओं का सृजन कर लिया है इसलिए वे बाजार के अवसरों का पता लगा रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना जिसका चीन की सरकार सहित विरोधी हितबद्ध पक्षकारों में विरोध नहीं किया, के अनुसार चीन का कार्बन ब्लैक बाजार, वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर फैल रहा है और इस प्रकार वे अपने निर्यात का आकार बढ़ा रहे हैं। चीन में कार्बन ब्लैक की क्षमता 5 मिलियन प्रतिवर्ष को पार कर गई है और इसका आउट-पुट 3.4 मिलियन टन है। संबद्ध देश में संबद्ध माल की भारी उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, जो व्यर्थ पड़ी रहती है तथा उनके निर्यात अभिमुखीकरण और भारत में संदभित माल की बढ़ती मांग को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि आयात वर्ष 2011-12 तथा इसके बाद भी वर्ष 2008-09 और 2010-11 की तुलना में भी अधिक बने रहेंगे।
79. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि चीन जन गण में कच्चे माल की कीमतों को "अन्य तथ्यों" न कि "अप्रत्याक्षित परिस्थितियों" के रूप में लिया जाना चाहिए। यह नोट किया दोनों कच्चे माल की कीमतों में पर्याप्त कीमत भिन्नता है (चीन में सी बी ओ की प्रचलित कीमतें तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

में सी बी एफ एस की प्रचलित कीमतें)/ दोनों

कच्चे माल के बीच कीमत अंतर को चीन के उत्पादकों को पर्याप्त लागत लाभ पहुंचाया जिसके कारण चीन से न्यून कीमत वाले कार्बन ब्लैक का आयात हुआ। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्तों को चीन का कार्बन ब्लैक ज्यादा फायदेमंद लगने लगा। मैं पाया कि इस तथ्य के कारण ही भारत में कार्बन ब्लैक के आयातों में बढ़ोतरी आई और इस वजह से कच्चे माल की कीमत स्पष्टतः अप्रत्याशित परिस्थिति है जिसके कारण आयात बढ़े।

(IX) बाजार विघटन और बाजार विघटन के लिए खतरा

80. सांविधिक ढांचा: नियमों के अन्तर्गत "बाजार विघटन" तब होता है जब कभी समान वस्तु या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की जा रही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का आयात तेजी से बढ़ जाता है, यह आयात निरपेक्ष या प्रासंगिक रूप से बढ़ता है, ताकि यह घरेलू उद्योग को सामग्री क्षति का महत्वपूर्ण कारण बने या इससे भौतिक क्षति की आशंका हो। "बाजार विकृति को खतरा" से यह तात्पर्य है कि बाजार विकृति को स्पष्ट और आसन्न खतरा।
81. यह देखा गया है कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 के नियम 8 के अनुलग्नक में तकनीकी दृष्टि से यह अपेक्षित है कि बाजार विकृति या बाजार विकृति के खतरे का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों और अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऐसा प्रत्येक मूल्यांकन अलग-अलग मामलों में अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग होगा जो किसी मामले विशेष के तथ्यों पर आधारित होगा और संबंधित उद्योग की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के मूल्यांकन में यह दर्शाना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ऐसे कारक में "गिरावट" आ रही है। एक मामले में, उदाहरणार्थ, बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में तेजी से गिरावट आ रही हो जिससे घरेलू उद्योग को 'सामग्री की क्षति' का पता चलता है और इसलिए यह बाजार विकृति को सही ठहरा सकता है। दूसरे मामले में कतिपय कारकों में गिरावट न आ रही हो लेकिन समग्र स्थिति से घरेलू उद्योग को 'सामग्री क्षति' की तस्वीर का पता न चलता हो। इस प्रकार सभी सूचीबद्ध कारकों और अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच करने के अलावा यह आवश्यक है कि उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए।
82. तदुसार, बाजार विकृति अथवा बाजार विकृति के खतरे के सभी कारकों का विश्लेषण करने के लिए, जिनका उल्लेख नियमों में किया गया है तथा अन्य कारकों का भी जो बाजार विकृति या बाजार विकृति के खतरे का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक हैं, पर विचार किया गया है। किसी एक कारक को स्वाभाविक कारक के रूप में नहीं माना गया है। संगत व्यापार चक्र और प्रतियोगिता की शर्तों के संदर्भ में उन सभी प्रासंगिक कारकों को, जो प्रभावित उद्योग के लिए प्रासंगिक हैं, विचार में लिया गया है। बाजार विकृति या बाजार विकृति के लिए खतरे का निर्धारण, उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत कारकों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।
83. यह पाया गया है कि चीन पीआर से कार्बन ब्लैक के बढ़ते आयात के कारण, नीचे बताए गए कारकों से कार्बन ब्लैक के घरेलू उत्पादकों के बाजार विकृति को कारित किया है अथवा बाजार विकृति के लिए खतरा बन गया है:

क बाजार हिस्सा: घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही तक बढ़ा परन्तु उसके पश्चात इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। वर्ष 2008-09 में जब घरेलू उद्योग का पाटित आयातों से क्षति हो रही थी, तब भी घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 70% था। यह बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 में कम होकर 69% रह गया परन्तु तत्पश्चात पाटनरोधी शुल्क लगाने पर इसमें सुधार आया और यह (वर्ष 2010 - 11 में) बढ़कर 72% तथा (वर्ष 2011-2012 की पहली तिमाही में) 74% हो गया। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में 74% था वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में घटकर 61% रह गया। यह वह अवधि थी जब चीन के आयातों ने तीव्र गति से भारतीय बाजार में प्रवेश किया और उस पर अपनी पकड़ बना ली। चीन से संबद्ध अयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2008-09 में 3% था, बढ़कर वर्ष 2011-12 (ए) में 12% हो गया, जबकि इस अवधि में तृतीय देशों से होन वाल आयातों के बाजार हिस्से में कमी आई। चीन की बाजार हिस्से में तीव्र वृद्धि ने घरेलू उद्योग तथा चीन के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात दोनों के बाजार हिस्से में गिरावट ला दी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट बहुत अधिक थी और यह चीन सहित विभिन्न स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण के बावजूद हुई। चीन से कार्बन ब्लैक के आयात में तीव्र वेग से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर विपरीत प्रभाव पड़ा। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में यह गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने तथा घरेलू उद्योग की माल सूची में तीव्र वृद्धि के बावजूद आई।

वित्त वर्ष	तिमाही	कुल आयात	चीन से आयात (मीटन.)	घरेलू उद्योग की बिक्री (मीटन.)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कुल मांग (मीटन.)	का % बाजार हिस्सा		
							डीआई	चीन से आयात	अन्य देशों से आयात
2008-09		39187	12971	322809	98052	460048	70	3	6
2009-10		63244	17722	400295	119391	582930	69	3	8
2010-11		61185	16724	443430	109537	614152	72	3	7
2011-12	Q1	14828	5789	119327	26073	160228	74	4	6
	Q2	32465	25686	99206	33000	164671	60	16	4
	Q3	31972	26878	100608	32741	165321	61	16	3
	2011-12 (A)	105686	77804	425521	122419	653627	65	11	4

ख. उत्पादन: घरेलू उद्योग के एक्साइज रिकॉर्ड्स द्वारा दी गई उत्पादन की सूचना के आधार पर उत्पादन निर्धारण किया गया है। यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही तक घरेलू उत्पादन बढ़ा है लेकिन अभी हाल की अवधि में इसमें तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उत्पादन में लगातार गिरावट आई है जो पहली तिमाही (2011-12) में 163458 मी.टन था वह दूसरी तिमाही (2011-12) में 148188 मी.टन हो गया और पुनः वर्ष (2011-12 की तीसरी तिमाही में घटकर 137035 मी टन हो गया। अर्थात् 16% की गिरावट। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कार्बन ब्लैक की उत्पादन प्रक्रिया ऐसी है कि घरेलू उद्योग को उत्पाद का अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिए ताकि

न केवल पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त की जा सके बल्कि संयंत्र और उत्पादन से जुड़ी निश्चित लागत को भी कम किया जा सके।

वित्त वर्ष	तिमाही	उत्पादन (मी.टन)	उत्पादन (मी.टन)
2008-09		416244	104061
2009-10		492863	123216
2010-11		585899	146475
2011-12	Q1	163458	163458
	Q2	148188	148188
	Q3	137035	137035
2011-12 (A)		598241	149560

चूंकि इस उत्पाद की मांग है, इसलिए घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि की तुलना में अपनी क्षमता बढ़ा दी है। तथापि, आयात में इतनी अधिक तेजी संवृद्धि हो रही है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इन अतिरिक्त प्रयासों के बावजूद घरेलू उद्योग के साथ माल सूचियों का स्तर इतना अधिक बढ़ा है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन निलंबित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उच्च क्षमता के साथ उत्पादन बढ़ाने का यह अर्थ है कि माल सूची की स्थिति और खराब होगी। घरेलू उद्योग इस बात से संतुष्ट है कि कार्बन ब्लैक के बढ़ते आयात के कारण घरेलू उद्योग द्वारा अभी हाल की अवधि में उत्पादन निलंबित करना पड़ा। घरेलू उद्योग के परिसर में सत्यापन से यह पता चलता है कि बढ़ती मालसूचियों को रोकने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों ने उत्पादन बंद कर दिया है।

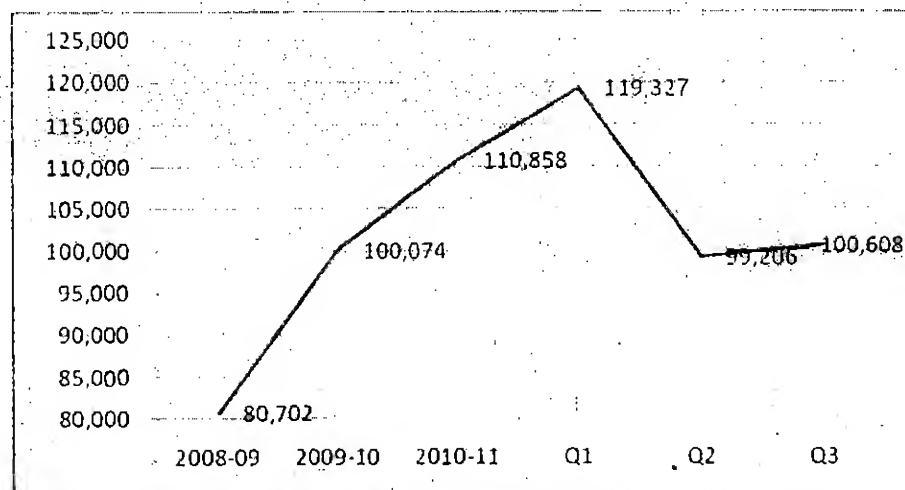
यूनिट	बंद पड़े रहने की अवधि			सुनियोजित बंद का कारण
	से	तक	दिन	
फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड दुर्गापुर				उच्च माल सूची कारण लाइन डाउन
	07.09.2011 16.09.2011	13.09.2011 19.09.2011	7 4	उच्च माल सूची के कारण सी ए टी -1 डाउन
	06.10.2011	31.10.2011	26	
	27.07.2011	07.07.2011	12	उच्च माल सूची के कारण सी ए टी -1 डाउन
फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड मुंद्रा				बाजार मंदी के कारण सी ए टी -1 डाउनलोड
	29.07.2011 26.09.2011	04.08.2011 31.10.2011	7 37	बाजार मंदी के कारण सी ए टी -3 डाउनलोड
	12.09.2011 22.09.2011	22.09.2011 27.09.2011	11 6	उच्च माल सूची के कारण
	25.10.2011	31.10.2011	7	

84. यह भी नोट किया जाता है कि उक्त अवधि में कार्बन ब्लैक की मांग लगातार बढ़ती रही। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के उत्पादन में हुई यह कमी देश में इस उत्पाद की लगातार वृद्धि होने के बावजूद

आई। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में, इस उत्पादन का देश में पाटन होने के दौरान भी, कमी नहीं आई। यस्तुतः घरेलू उद्योग उत्पादन के पाटन के बावजूद अपने उत्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने अभी हाल ही की अवधि में अपनी निर्यात मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि निर्यात घरेलू मांग और घरेलू बाजार से उत्पाद के आफटेक पर विचार करते हुए किए गए थे। तथापि, अतिरिक्त निर्यात किए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग को मालसूची का संग्रहण होने का सामना करना पड़ा और इस कारण अपना उत्पादन घटाना पड़ा। घरेलू उद्योग को बढ़ती मालसूची को कवर करने के लिए अपना उत्पादन स्थगित करना पड़ा।

ग. बिक्री: बिक्री का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा, अपने माल की बिक्री, जिसका उन्होंने उत्पाद कर रिकार्ड में उल्लेख किया है के आधार पर किया गया।

वित्त वर्ष	तिमाही	उत्पादन (मी.टन)	घरेलू उद्योग की बिक्री (मी.टन)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कुल मांग (मी.टन)	घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात (मी.टन)
2008-09		416244	322809	98052	460048	94395
2009-10		492863	400295	119391	582930	89021
2010-11		585899	443430	109537	614152	141383
2011-12	Q1	163458	119327	26073	160228	44909
	Q2	148188	99206	33000	164671	45295
	Q3	137035	100608	32741	165321	35153
2011-12 (A)		598241	425522	122419	653627	167143



- i) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री वित्त वर्ष 2010-11 तक बढ़ी और यह प्रवृत्ति चीन से आयातों का प्रवाह शुरू होने से पहले वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही तक जारी रही। तथापि अभी अत्यधिक निम्न की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा जो वर्ष 2010-11 में 443430 मी० टन थी तेजी से घटकर वर्ष 2010-11 में 425521 मी० टन हो गई। सकल रूप से बिक्री जो वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में 119327 मी.टन थी वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में घटकर कर 84675 मी.टन रह गई। बिक्री में यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद है कि मांग में संपूर्ण जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

- ii) यह नोट किया जाता है कि निरपेक्ष संदर्भ में उत्पाद की कुल मांग के प्रतिशत के रूप में घरेलू उद्योग की बिक्री में आयातों में बढ़ोत्तरी से भारी कमी आई। मांग की प्रतिशत के रूप में घरेलू उद्योग की बिक्री में जो वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में 74% थी तीव्र कमी आई और यह वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में 61% रह गई। यह स्पष्टतः दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की मांग के संबंध में तथ्य समग्र रूप से बिक्री में घाटा उठाना पड़ा।

वित्त वर्ष	तिमाही	मांग के प्रतिशत के रूप में बिक्री
2008-09		70
2009-10		69
2010-11		72
2011-12	Q1	74
	Q2	60
	Q3	61
2011-12 (A)		65

- (iii) यह पुनः नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री के प्रतिशत के रूप में चीन के आयातों में वृद्धि हुई है। चीन के आयात जो वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग की बिक्री में 4% थे बढ़कर वर्ष 2011-12 (वार्षिक) में 18% हो गए; इससे आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री पर इसका प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। वास्तव में, प्रवणता अवधि के दौरान (वर्ष 2011-12 की दूसरी एवं तीसरी तिमाही) चीन के आयात घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा के लगभग 26% थे।

वित्त वर्ष	तिमाही	चीन से आयात मी० टन	घरेलू उद्योग की बिक्री मी० टन	घरेलू उद्योग की बिक्री के प्रतिशत के रूप में चीन के आयात
2008-09		12971	322809	4.02
2009-10		17722	400295	4.43
2010-11		16724	443430	3.77
2011-12	Q1	5789	119327	4.85
	Q2	25686	99206	25.89
	Q3	26878	100608	26.72
2011-12 (A)		77804	425521	18.28

- (iv) घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कार्बन ब्लैक के बढ़ते आयात ने घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन, घरेलू बाजार में बेचने से रोक दिया है। घरेलू उद्योग का मानना है कि आयात में यह वृद्धि इतनी अधिक थी कि इससे घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आ गई है। घरेलू बिक्री में यह गिरावट, मांग में वृद्धि और पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने के बावजूद है। घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन का निर्यात किए जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है जबकि घरेलू मांग काफी अधिक है। आयात में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है कि घरेलू उद्योग भारत से बाहर बाजार के अवसर तलाशने के लिए मजबूर हो गया ताकि वह उस उत्पादन को बेच सके जिसे वह घरेलू बाजार में नहीं बेच सका है।
- (v) घरेलू उद्योग ने आगे यह बात भी कही है कि घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में काफी अंतर है। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया कि यद्यपि यह उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगा है। आयात की कीमतें इतनी कम हैं कि चीन की कुछ कंपनियों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क

जोड़ने पर भी, आयात की लैण्डिङ कीमत, घरेलू उद्योग की विक्रय मूल्य से कम हैं। घरेलू और आयातित उत्पाद की कीमत में यह महत्वपूर्ण अंतर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को चीनी उत्पादों के पास ले जा रहा है। अभी हाल ही में घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है। इसके अलावा, उत्पाद की मांग वर्ष 2010-11 से 2011-12(ए) में लगभग 39000 मी.टन बढ़ गई। जबकि उसी अवधि में चीन से आयात लगभग 61000 मी.टन बढ़ गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में हुई वृद्धि की तुलना में आयात में कहीं अधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण आयात ने भारतीय उत्पादकों के बाजार के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री प्रभावित हुई है जो बाजार विकृति का कारण बना है।

- (vi) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मै0 पी सी बी एल एवं मै0 हाईटेक निर्यात केन्द्रित कंपनियां हैं, यह पाया गया कि मै0 पी सी बी एल और मै0 हाई टेक दोनों ही निर्यात केन्द्रित कंपनियां नहीं हैं। दोनों कंपनियों की घरेलू बिक्री उनकी कुल बिक्री का प्रमुख हिस्सा रही है।

		घरेलू बिक्री	निर्यात बिक्री	कुल बिक्री	घरेलू बिक्री का हिस्सा
2008-09		322809	94395	417204	77%
2009-10		400295	89021	489316	82%
2010-11		443430	141383	584813	76%
2011-12	Q1	119327	44909	164236	73%
	Q2	99206	45295	144501	69%
	Q3	100608	35153	135761	74%
2011-12 (A)		425522	167143	592664	72%

- (vii) इसके अतिरिक्त, विरोधकर्ता पक्षकारों ने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग की मालसूची में, उत्पादन में कटौती और क्षमता उपयोगीकरण में गिरावट के बावजूद, तीव्र एवं अत्यधिक वृद्धि हुई। यदि घरेलू उद्योग निर्यात केन्द्रित होता तो वह अपने उत्पादन को कायम रखकर अपनी मालसूची से निर्यात बाजार में आसानी से बिक्री कर सकते थे। निर्यात उनकी पसन्द नहीं था परन्तु यह आयात उद्रेक की स्थिति में अपनी दुर्गति को कम करने का एक प्रयास था।

- (viii) हितबद्ध पक्षकारों ने अपने निवेदन में यह इंगित किया है कि प्रारंभिक निष्कर्ष में उल्लिखित वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, अक्टूबर 11, तीसरी तिमाही (वार्षिकीकृत) निर्यात प्रविष्टियां सार्वजनिक फाइल में रखे गए सत्यापित आंकड़ों से मेल नहीं खाती हैं। इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि सार्वजनिक फाइल में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं परन्तु प्रारंभिक निष्कर्षों में भूलवश, टंकण त्रुटि के कारण निर्यात की मात्रा के बजाय निर्यात मूल्य का उल्लेख कर दिया। इस टंकण त्रुटि से क्षति विश्लेषण और निष्कर्ष में कोई फर्क नहीं पड़ा परन्तु स्पष्टता एवं आंकड़ों की शुद्धता के लिए दिनांक 21.06.2012 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया।

- (ix) घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत की तुलना घरेलू बाजार में बिक्री कीमत से की गई। अधोलिखित तालिका में उल्लिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू बिक्री कीमत से कम थी। इसके अतिरिक्त यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य रिकार्ड में नहीं लिया गया कि घरेलू उद्योग ने भारत में प्रयोक्ता उद्योग की घरेलू आपूर्तियों ने मना कर दिया अथवा विलम्ब किया और यह कि घरेलू उद्योग ने निर्यात को अधिमानता दी।

वित्त वर्ष	निबल बिक्री कीमत (सूचीबद्ध)	आयातों की लैण्डेड कीमत एडीडी (सूचीबद्ध)	निर्यात कीमत (सूची बद्ध)
	Rs.per MT	Rs.per MT	Rs.per MT
2008-09	100	87	79
2009-10	98	85	70
2010-11	112	97	79
2011-12 (Till Dec.)	125	112	106

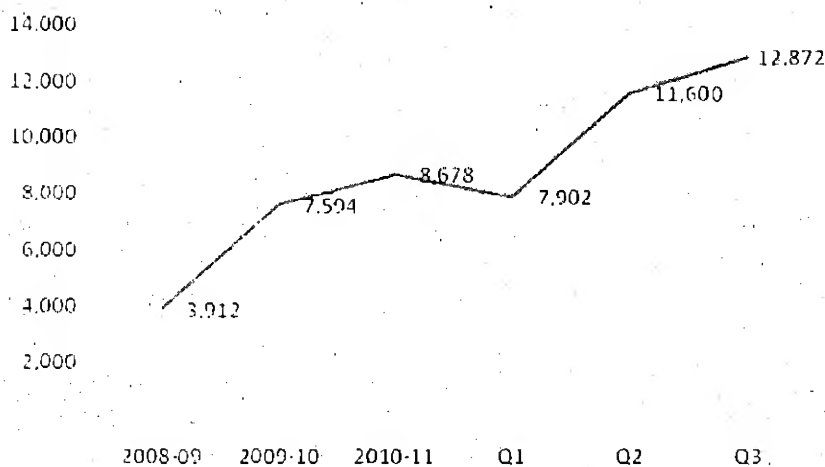
ध. क्षमता का उपयोग: घरेलू उद्योग ने कुछ समय से अपनी क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि क्षमता में वृद्धि, बाजार में उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को ध्यान में रखकर की गई है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने 2011-12 की पहली तिमाही तक क्षमता बढ़ाई है और क्षमताओं में इन वृद्धियों के बावजूद घरेलू उद्योग 2011-12 की पहली तिमाही में क्षमता का 90% उपयोग करने में सफल रहा। तथापि, इसके बाद क्षमता उपयोग में तेजी से गिरावट आई जो दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में क्रमशः 82% और 76% रह गई। अभी हाल की अवधि में घरेलू उद्योग की उपयोग क्षमता सबसे कम स्तर पर है। वर्ष 2011-12(ए) की क्षमता विस्तार, 2010-11 की तुलना में 9% थी लेकिन इसी अवधि में आयात के बाजार हिस्से में वृद्धि होने के कारण उपयोग क्षमता में 5% की गिरावट आ गई। यह नोट किया गया कि क्षमता में यह वृद्धि वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में हुई और घरेलू उद्योग ने इस अवधि में संवर्धित क्षमता के 90% का क्षमता उपयोग किया। तथापि क्षमता उपयोग में उसके बाद चीन से आयातों में वृद्धि के कारण दूसरी और तीसरी तिमाही में गिरावट आई। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि क्षमता उपयोग में गिरावट आयातों में बढ़ोतरी एक संयोग है।

वित्त वर्ष	तिमाही	उत्पादन (मीटन.)	स्थापित क्षमता	क्षमता उपयोग (%)
2008-09		416244	500000	83
2009-10		492863	552500	89
2010-11		585899	667000	88
2011-12	Q1	163458	181002	90
	Q2	148188	181002	82
	Q3	137035	181002	76
2011-12(A)		598241	724008	83

85. इस प्रकार घरेलू उद्योग नवक्षमता वृद्धि और देश में उत्पाद के पाटन के बावजूद क्षमता उपयोग में सुधार करने में सक्षम रहा। तथापि, द्वितीय तिमाही और तत्पश्चात तृतीय तिमाही में, जब चीन से आयातों की प्रचलता थी, क्षमता उपयोग में तेजी से गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अतिरिक्त निर्यात किए जाने के बावजूद भी क्षमता उपयोग में गिरावट आई।

- ड. **मालसूची:मालसूची का स्तर घरेलू उद्योग द्वारा अनुरक्षित उत्पाद कर रिकॉर्डों के अनुरूप माना गया था।** यह देखा जा सकता है कि जब घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आ रही थी और आयात बढ़ रहे थे। तब घरेलू उद्योग की माल सूची में वृद्धि हो रही थी। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री मात्रा को बढ़ाने में अक्षम रहा बिक्री मात्रा वास्तव में घटी और उसे संचित वस्तु सूची की समस्या का सामना करना पड़ा। वस्तु सूची का स्तर सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक बढ़ा है। अधोलिखित तालिका वस्तु सूची स्तर को दर्शाता है जिसमें वर्ष 2008-09 में 3912 मी.टन की तुलना में तीव्र वृद्धि होकर 2011-12 की तीसरी तिमाही में 12872 मी.टन हो गया। यह वृद्धि वर्ष 2008-09 के स्तर की तुलना में वर्ष 2011-12 में लगभग तीन गुनी है जिससे घरेलू उद्योग पर आयात का विपरीत प्रभाव परिलक्षित होती है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि बढ़ते हुए आयातों का सामना करने के लिए वस्तु सूची के स्तर में कटौती करने और उत्पादन को व्यवहार्य सीमा तक बनाए रखने के लिए उन्होंने अतिरिक्त निर्यात के प्रयास किए। तथापि चीन से किए जाने वाले आयात में वृद्धि इतनी तीव्र है कि उत्पादन में गिरावट आने के बावजूद घरेलू उद्योग को बढ़ती वस्तु सूची का सामना करना पड़ रहा है।

वित्त वर्ष	तिमाही	उत्पादन (मीटन.)	डीआई की बिक्री (मीटन.)	इन्वेन्टरी (मीटन.)
2008-09		416244	322809	3912
2009-10		492863	400295	7594
2010-11		585899	443430	8678
2011-12	Q1	163458	119327	7902
	Q2	148188	99206	11600
	Q3	137035	100608	12872
2011-12(A)		598241	425521	12872



- ड. **रोजगार और उत्पादकता:** घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में बढोत्तरी हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने भी उत्पादन की तरह ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की। उत्पादकता में 2011-12 की पहली तिमाही तक वृद्धि हुई। तथापि, उत्पादकता में वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही और तत्पश्चात तीसरी तिमाही में गिरावट आई।

वित्त वर्ष	तिमाही	सूचीबद्ध रोजगार (संख्या)	उत्पादन	उत्पादकता (प्रति दिन मीटन.)	उत्पादकता मी० टन प्रति कर्मचारी
2008-09		1,057	416,244	1,140	394
2009-10		1,133	492,863	1,350	435
2010-11		1,280	585,899	1,605	458
2011-12	Q1	1,290	163,458	1,816	127
	Q2	1,257	148,188	1,647	118
	Q3	1,302	137,035	1,523	105

छ. लाभ/हानि: घरेलू उद्योग ने एक पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित कर पूर्व लाभ की सूचना दी है:

वित्त वर्ष	तिमाही	बिक्री लागत (सूचीबद्ध)	बिक्री मूल्य (सूचीबद्ध)	लाभदायकता (सूचीबद्ध)
		रुपये/टन.मी./	रुपये/टन.मी./	रुपये/टन.मी./
2008-09		100	92	(8)
2009-10		77	85	8
2010-11		97	102	4
	Q1	92	96	3
	Q2	104	105	2
	Q3	104	103	(0.3)

i) घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किये गये लाभ पर विचार विचाराधीन उत्पाद के बारे में केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में किया जाता है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण निर्यात गतिविधियां हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात प्रचालनों से अर्जित लाभ को पृथक रखा गया है और इस पर घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर संवर्धित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर विचार केवल घरेलू बाजार में रबड़ अनुप्रयोगों से संबंधित कार्बन ब्लैक के संबंध में किया गया है। यह देखा गया कि अभिनवतम समय में घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में तीव्र गिरावट आई। वर्ष 2009-10 में लाभदायकता में सुधार हुआ परन्तु तत्पश्चात इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। अभी हाल की अवधि की तीसरी तिमाही में घरेलू उद्योग को नुकसान सहन करना पड़ा।

ii) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2008-09 में घाटा हुआ और उनके द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार ये वित्तीय घाटे उत्पाद का पाटन होने के कारण हुए। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी एवं सहबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने कार्बन ब्लैक के संबंध में पहले भी पाटनरोधी जांच की थी जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अक्टूबर, 2007 से सितम्बर, 2008 को जांच अवधि के रूप में विचार किया था। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान हुआ वित्तीय घाटा मांग में कमी और उत्पाद का पाटन होने के कारण क्षति की वजह से हुआ।

iii) चीन जन-गण से संयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग के लाभ पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आयातों की लैण्डिंग कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है। आयातों से घरेलू कीमत में कटौती करनी पड़ रही है। घरेलू और चीनी उत्पाद के बीच कीमत में अंतर होने के कारण उपभोक्ताओं ने चीन का माल खरीदना बेहतर समझा। परिणामस्वरूप आयातों में तीव्र वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग के लाभ में तीव्र गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, इनपुट लागत में वृद्धि के कारण इसकी लागत में बढ़ोतरी हुई, परन्तु लागत में वृद्धि की तुलना के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई। इसका परिणाम हुआ कि घरेलू बिक्री का प्रति यूनिट लाभ आयातों में बढ़ोतरी से कीमत ह्रास हो रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में बढ़ोतरी करने में अक्षम रहे।

iv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास/कमी नहीं हुई। तथापि यह पाया गया कि न्यून कीमत वाले आयात की मौजूदगी के कारण, आयातों की लैण्डिंग कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। इसके अतिरिक्त आयातों में उद्देक के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतें लागत में बढ़ोतरी के अनुरूप बढ़ाने में अक्षम रही। यह घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री के संबंध में प्रति यूनिट लाभ में गिरावट से सिद्ध होता है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अत्यधिक हाल की अवधि में घाटा हुआ जिससे अक्षमता का कीमत ह्रास प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

v) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक लाभ में वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोटिस किया गया कि घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में वार्षिक रिपोर्टों में प्रदान कराई गई जानकारी कंपनी के समग्र निष्पादन से संबंधित है जबकि मौजूदा जांच रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक के घरेलू प्रचालनों से संबंधित है। अतः वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरण पर विचार नहीं किया जा सकता है।

vi) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कोलतार की आसन्न प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में तर्क दिया है। यह पाया गया कि मौजूदा स्थिति उस कच्चे माल में अन्तर से संबंधित नहीं है जिसका प्रयोग घरेलू उद्योग और चीन के उत्पादकों द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि घरेलू उद्योग अपने मौजूदा संयंत्रों में सी बी ओ का प्रयोग कर सकती है। तथापि मुद्दा उस कीमत से संबंधित है जिस पर चीन के उत्पादकों, घरेलू उद्योग और वैश्विक उत्पादकों का सी बी ओ उभल रहा है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि सी बी ओ की कीमतें चीन में और केवल चीन के उपभोक्ताओं के लिए बहुत कम हैं। वे इन कीमतों पर सी बी ओ का न तो चीन से आयात कर सकते हैं और न ही सी बी ओ की कीमतें वैश्विक बाजार में इतनी कम हैं।

vii) हितबद्ध पक्षकारों में से कुछ ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के बिक्री राजस्व में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि केवल बिक्री राजस्व को अलग से नहीं देखा जा सकता है। पुनः यह नोट किया जाता है कि बिक्री राजस्व में वृद्धि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री लागत में वृद्धि के कारण हुई परन्तु घरेलू उद्योग के लाभ में वर्षवार और तिमाहीवार दोनों तरह से काफी गिरावट आई है।

viii) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि चीन से आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ एक-दूसरे से प्रत्यक्षतः आनुपातिक हैं। यह देखा गया कि आयातों में बढ़ोतरी जुलाई-सितम्बर, 2011 से शुरू हुई और आयातों में उद्देक से घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में तीव्र गिरावट आई। अतः चीन से किए गए आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ एक-दूसरे से प्रत्यक्षतः आनुपातिक नहीं हैं।

ज. निवेश पर आय: घरेलू उद्योग ने निवेश पर आय के संबंध में रिपोर्ट केवल विचाराधीन उत्पाद से जुड़े घरेलू प्रचालनों से अर्जित व्यय एवं करपूर्व लाभ पर विचार करते हुए प्रस्तुत की है। लगाई गई

पूँजी पर विचार विचाराधीन उत्पन्न के केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में ही किया गया। निवेश पर आय का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूँजी और करपूर्व लाभ पर विचार करते हुए किया गया है। इस उद्देश्य के लिए लगाई गई पूँजी को निवल अचल सम्पत्ति तथा कार्यशील पूँजी के रूप में माना गया। यह देखा गया कि निवेश पर आय की भी वही प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जो लाभप्रदायकता की थी। निवेश पर आय जो वर्ष 2009-10 में 222 प्वाइंट था घटकर वर्ष 2010-11 में 111 प्वाइंट रह गया और यह अत्यधिक हाल की अवधि में और अधिक घटकर केवल 44 प्वाइंट रह गया। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के बीच लगाई गई पूँजी पर आय में सुधार के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह पाटनरोधी शुल्क लगाने का परिणाम था।

वित्त वर्ष	तिमाही	निवेश पर लाभ
		%
2008-09		(100)
2009-10		222
2010-11		111
	क्यू 1	122
	क्यू 2	78
	क्यू 3	44

(X) बाजार विकृति की चुनौती

86. नियमों में निम्नलिखित प्रावधान है -

(1) यह निर्णय करने के लिए की जाने वाली जांच में कि क्या संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को "बाजार विकृति" हुई है अथवा उसकी चुनौती उत्पन्न हुई है महानिदेशक, उद्देश्यपरक एवं गणनायोज्य प्रकृति के उन सभी तथ्यों, खासकर संबंधित वस्तु के आयातों में वृद्धि की समग्र एवं संक्षिप्त रूप में दर एवं राशि, संवर्धित आयातों का घरेलू बाजार में शेयर, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा सेजमर का मूल्यांकन करेंगे जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

7 क "बाजार विकृति की चुनौती" का आशय है बाजार विकृति का स्पष्ट एवं आसन्न खतरा।

87. यू.एस. - लैम्ब संबंधी पैनल ने विचार किया कि भविष्य में होने वाली किसी गंभीर क्षति के विश्लेषण के मद्देनजर जांच अवधि की समाप्ति से संबंधित उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों पर प्रकाश डालना तर्क संगत है। संगत उद्धरण निम्नलिखित है:

"हमारे विचार से, चुनौती विश्लेषण की भावी-उन्मुखी प्रकृति होने के कारण यह तर्क संगत प्रतीत होता है कि जांच अवधि की शुरुआत के समय घटित घटनाएं अवधि की समाप्ति के समय में घटित घटनाओं की तुलना में कम संगत हैं। हालांकि एस.जी. करार में किसी जांच में विचार किए जाने के लिए उपयुक्त समयावधि को विशेष रूप से नहीं बताया गया है परन्तु अर्जेंटीना-फुटवीयर के पैनल और अपीलीय दलों ने इस मुद्दे पर काफी हद तक विचार किया। दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि (वास्तविक गंभीर क्षति निर्णय करने के लिए) अत्यधिक हाल के अभिनव आंकड़े स्पष्टतः सर्वाधिक संगत हैं। खासकर, अपीलीय निकाय ने उल्लेख किया कि संगत जांच अवधि केवल निकट तक विगत में ही समाप्त नहीं हो जानी चाहिए, बल्कि जांच अवधि अभी हाल का विगत होना चाहिए।

इस बात पर विचार करते हुए कि गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न अत्यधिक प्रभावशाली समग्र व्यवधान अर्थात् किसी ऐसी घटना से संबंधित है जो निकट भविष्य में होने वाली है तो वही सिद्धान्त

मौजूदा गंभीर क्षति निर्धारण की तुलना में उसकी चुनौती निर्धारण के लिए भी सत्य होना चाहिए। इससे इस विचार को सहारा मिलता है कि यू एस आई टी सी जांच अवधि की समाप्ति से अत्यधिक हाल के उपलब्ध आंकड़ों पर प्रकाश डालने में सही था। हमारा विचार है कि 1997 और अन्तरिम 1998 के आंकड़े उपयुक्त एवं तर्क संगत समयावधि को पूरा करते हैं यदि प्रत्याशाओं द्वारा मौजूदा प्रवृत्तियों को आसन्न भविष्य एक्स्ट्रापोलेट करके अनुपूरक बना दिया जाए जिससे कि परिदृश्य विश्लेषण सुनिश्चित हो सके जो चुनौती का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित है।

अतः हमारा विचार है कि यू एस आई टी सी नें, अपना निर्णय सम्पूर्ण जांच अवधि की घटनाओं पर आधारित किए जाने के बाजाय जांच अवधि की अन्त की घटनाओं पर आधारित करके इस तथ्य का वैध मूल्यांकन करने के लिए कि क्या सम्मिल अवरोध निकट भविष्य में 'आसन्न' था, पर्याप्ततः हाल के आंकड़ों का विश्लेषण किया। उसी तरह, हम भी अपना निर्णय भविष्य में विभिन्न उद्योग संकेतकों के लिए अन्यतः प्रत्याशाओं पर विचार करने के बाजाय हाल के विगत की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों से करने पर विचार करते हैं, यू एस आई टी सी ने अपना चुनौती निर्धारण उद्देश्यपरक एवं गणनायोग्य तथ्यों के आधार पर किया, न कि "केवल आरोप-प्रत्याशा या सुदूर सम्भावना के आधार पर।"

88. यू एस - लैम्ब संबंधी पैनल रिपोर्ट ने एक निर्णय किया, जिसकी अपीलीय निकाय द्वारा उत्तरवर्ती समीक्षा नहीं की गई और जिसने इस प्रश्न का समाधान निकाला कि एक बार बड़े हुए आयातों से कुछ हद तक क्षति धारित हुई है तो गंभीर क्षति की चुनौती की मौजूदगी का विधिवत रूप से निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त सम्वर्धित आयातों की जरूरत नहीं होती है। संगत उद्धरण निम्नलिखित है-
 "शिकायतकर्ता दावा करते हैं कि अपनी चुनौती विश्लेषण की रक्षा करने में आयातों में भविष्य में होने वाली वृद्धि की प्रत्याशाओं का यू एस संदर्भ 'गंभीर क्षति की चुनौती' सहित "सम्वर्धित आयातों की चुनौती" के समरूप है जिसे अर्जेंटीना-फुटवीयर पैनल ने अनुमति देने योग्य नहीं पाया-----"
 हम शिकायतकर्ताओं के इस तर्क से सामान्यतः सहमत हैं कि सम्वर्धित आयातों की चुनौती को गंभीर क्षति की चुनौती के समान नहीं माना जा सकता है। तथापि, हमारे विचार से यह वह नहीं है जो यू एस आई टी सी ने इस मामले में किया है। इसके अतिरिक्त हम यह भी सम्भव मानते हैं कि बड़े हुए स्तर के आयातों यदि उन्हें रोका न गया तो जांच अवधि की समाप्ति पर और अधिक बड़े बिना दीर्घतर समय तक बने रहें, उनसे गंभीर क्षति कारित हो। (अर्थात् गंभीर क्षति करने की चुनौती उत्पन्न हो)। यह कि, यदि किसी निश्चित समय पर संवर्धित आयात गंभीर क्षति से कम क्षति कारित करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उनमें और अधिक वृद्धि होने अर्थात् आयातों में अतिरिक्त वृद्धि होने, से ही गंभीर क्षति की चुनौती हो सकती है। हमारे विचार से, किसी मामले विशेष परिस्थितियों में आयात पहले से ही संवर्धित स्तर पर बने रहना ही ऐसी चुनौती कारित करने के लिए पर्याप्त होता है।

89. चीन के आयात, भारत में निरपेक्ष संदर्भ के साथ-साथ उत्पाद और उपभाग के संबंध में भारी मात्रा में भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच अत्यधिक कीमत भिन्नता इस बात का संकेत है कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर बड़े हुए आयातों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों तथा प्रकाशित आयात आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि चीन जन गण से होने वाले आयात अधिकांशतः रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक के हैं। गैर-रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक के आयात काफी न्यून हैं। सम्बद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत पर विचार करते हुए, घरेलू और चीन की कीमत के बीच कीमत अन्तर बहुत अधिक है और इसके सकारात्मक बने रहने की सम्भावना है जिससे आयात अधिक लाभप्रद हो रहे हैं तथा संवर्धित आयात की सतत चुनौती सृजित हो रही है।

90. बाजार विघटन के लिए गंभीर खतरा निम्नलिखित कारकों से स्थापित होता है:-

(क) घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में बहुत अधिक अंतर है। इस प्रकार, आयात लाभप्रद बना रहेगा;

(ख) चीनी उत्पादकों की क्षमता बहुत अच्छी है। इसके परिणामस्वरूप वे यथासंभव अतिरिक्त बाजार खोज रहे हैं;

(ग) कच्चे माल अर्थात् सीबीएफएस और सीवीओ की कीमत के बढ़ते अंतर ने चीनी उत्पादकों को लाभप्रद स्थिति प्रदान कर रहा है। इसलिए इस बात की संभावना है कि चीनी उत्पादक भारतीय बाजार में अपनी गतिविधि बढ़ा दें;

(घ) चूंकि ऑटो उद्योग बढ़ रहा है और जांचाधीन उत्पाद की मांग भी बढ़ रही है इसलिए भारतीय बाजार लाभप्रद हैं और इसलिए बाजार विघटन का खतरा सन्निकट है।

91. घरेलू उद्योग बिक्री के अवसर गवां रहा है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद प्रवाह नहीं सुधर रहा है जिसमें कम कीमत के बढ़ते आयात के निरंतर ज़रूर रहने के कारण पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने के बावजूद भी सुधार नहीं आया। चीनी उत्पादकों द्वारा दी गई कम कीमत और उनके पास अत्यधिक स्वतंत्र रूप से उत्पादन का निपटान करने की क्षमताओं को देखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई कम कीमतों के बावजूद आयात आगे बढ़ रहा है। आयात बढ़ने के साथ ही आयात में बाजार का हिस्सा भी बढ़ा है और घरेलू बाजार का बाजार हिस्सा घटा है जिससे गंभीर बाजार विघटन का खतरा और बढ़ गया है।

(ख) क्षति के अन्य कारक:

92. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4(ख) में निम्नलिखित का उल्लेख है:

(ख) उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित निर्णय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह मांच, उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर यह प्रदर्शित नहीं कर देती कि संबंधित उत्पाद के संबंधित आयातों और गंभीर क्षति अथवा उसकी चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध हैं। जब, संबंधित आयातों के अतिरिक्त अन्य तथ्यों से घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो रही हो तो उक्त क्षति के लिए संबंधित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा।

93. जापान से कुछ हाट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर यू एस-पाटनरोधी उपायों के संबंध में अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार आयात के क्षतिकारी प्रभावों को उन अन्य सभी तथ्यों, जिनका स्थानीय उद्योग पर प्रभाव पड़ा, से अलग करके एवे विभेदकारी दिखाया जाना चाहिए।

94. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी ने उन अन्य संभावित तथ्यों का विश्लेषण किया जिन्हें घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य संगत हैं

इस संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक हैं:-

- क) उत्पाद की मांग से संभावित गिरावट: भारत में कार्बन ब्लैक की मांग में संकुचन नहीं है। पिछले वर्षों में भारत में इस उत्पाद की मांग में काफी वृद्धि हुई है।
- ख) उपभोग पद्धति में परिवर्तन: विद्युत्संधीन उत्पाद से संबंधित उपभोग की पद्धति में कोई बदलाव नहीं आया है। उपभोग की पद्धति में बदलाव आने से घरेलू उद्योग की क्षति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

- ग) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा: ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- घ) प्रौद्योगिकी का विकास: उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रौद्योगिकी का विकास क्षति का एक तथ्य नहीं है।
- ड.) निर्यात निष्पादन: घरेलू उद्योग को हुई क्षति का दावा, घरेलू परिचालनों के कारण हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने घरेलू परिचालनों के लिए लागत और क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है। घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति के लिए निर्यात को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

अवधि	कुल बिक्री कीमत (घरेलू उद्योग) (सूची बद्ध)	चीन से सी आई एफ आयात कीमत	निर्यात कीमत (सूची बद्ध)
	रूपये प्रति मी.टन	रूपये प्रति मी.टन	रूपये प्रति मी.टन
2008-09	100	82	79
2009-10	92	74	70
2010-11	111	85	79
2011-12 (दिसम्बर तक)	125	99	106

95. उपर्युक्त सारणी में दिये गए आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उनकी घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में कम थी। तथापि वर्ष 2011-12 के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत चीन से आयात कीमत की तुलना में अधिक है। घरेलू उद्योग को सुदृढ़ घरेलू भाग होने के बावजूद अपने माल का घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमतों पर निर्यात करता पड़ा। इसको ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के लिए निर्यात अधि जन्म विकल्प नहीं है। हानियों को कम से कम करने के लिए घरेलू उद्योग को निर्यात करना पड़ा है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के लिए निर्यात प्राथमिकता है। इसके अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया है जिससे यह पता चले कि घरेलू उद्योग ने भारत से उपयोगकर्ता उद्योग को घरेलू आपूर्ति करने से इंकार कर दिया है और इसके बाजाएँ उन्होंने स्वयं निर्यात का सहारा लिया है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर निर्यात करना पड़ा, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग निर्यात केन्द्रित नहीं है और इसने निर्यात को महत्व देते हुए घरेलू आपूर्तियों की अवहेलना नहीं की है।

(XII) बाजार विकृति अथवा बाजार विकृति की चुनौती और सम्बन्धित आयात के बीच कारणात्मक संबंध:

96. कोरिया-डेयरी संबंधी पैनल ने 'कार्य-कारण संबंध' का निर्धारण करने के लिए आधारभूत पहुंच व्यक्त की है:
- "कारणात्मक संबंध आकलन निष्पादन करने के संबंध में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने और यह निर्णय करने की जरूरत होती है कि उद्योग में हुए विकास, जिन पर राष्ट्रीय प्राधिकारी ने गंभीर क्षति प्रभावित करने के लिए विचार किया, संवर्धित आयात द्वारा किए गए हैं। कार्य कारण संबंध आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को विषयगत एवं परिमाणात्मक प्रकृति के उन सभी तथ्यों का मूल्यांकन करने अपेक्षित होता है जिनका उस उद्योग के हालात पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तथ्यों को

अभिज्ञात कर लिया जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि इन तथ्यों द्वारा कारित कोई क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित क्षति न मानी जाए।" कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रमाणित करना पड़ा कि इसके घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रमाणित करना पड़ा कि एस एम पी पी के आयातों के कारण दुग्ध पाउडर एवं अपरिष्कृत दुग्ध उत्पादक घरेलू उद्योग को क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात कोरिया के प्राधिकारी ने अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया।

97. उत्पाद को अधिकांशतः आयात की तुलना/प्रतिस्पर्धा में बेचा जाता है। आयातों की लैण्डेड प्राइस घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अत्यधिक कम है जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है। संबंधित उत्पाद के आयात घरेलू उद्योग से न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता बड़ा चढ़कर आयात का आश्रय ले रहे हैं, इससे घरेलू उद्योग पर उप-आप्टिमल कीमत पर माल देने का दबाव पड़ रहा है। घरेलू उद्योग के बिक्री अवसर समाप्त हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, कम कीमत पर आयातों की सतत उपस्थिति के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आवक कम हो रहा है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम की जा रही हैं। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभ और निवेश पर आवक में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात, चीन से कार्बन ब्लैक के संवर्धित आयातों का ही परिणाम है। अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को बड़े हुए आयातों के कारण ही क्षति हुई है।

चीन से आयात (इन्डेक्सड)

अवधि	घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत	आयात का सीआईएफ मूल्य	आयातों की लैण्डेड कीमत एडीडी के बिना	एडीडी युक्त आयात की लैण्डेड कीमत	एडीडी से कीमतों में कमी	एडीडी के बिना कीमतों में कमी
	रु०/मी.टन	रु०/मी.टन	रु०/मी.टन	रु०/मी.टन	रु०/मी. टन	रु०/मी.टन
2008-09	100	82	87	87	13	13
2009-10	92	74	79	85	7	13
2010-11	111	85	90	97	14	21
2011-12 (दिसम्बर तक)	125	99	105	112	13	20

98. घरेलू उद्योग का निष्पादन दर्शाता है कि पीओआई के दौरान कार्बन ब्लैक की मांग में बढोतरी के बावजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है और चीन से आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है। यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-10 में पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात चीन से आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क युक्त और पाटनरोधी शुल्क बिना दानों में कीमतों में कीमत कटौती बढ़ी है।
99. यह प्रेक्षण किया गया कि हाल की अवधि में आयात कीमत में वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी वह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा आयातों की

लैण्ड कीमत में भिन्नता आई। इसकी वजह से उपभोक्ताओं का चीन जन गण से आयातों की और बढ़ गया तथा इससे गंभीर बाजार विकृति हुई और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति पहुंची जो संवर्धित आयात और कारित विकृति के बीच कारणात्मक संबंध प्रदर्शित करता है।

100. विरोधी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि हाई-टेक थाईलैण्ड से आयात कर रहा था। यह स्पष्ट किया जाता है कि हाई टेक ने थाईलैण्ड से कोई आयात नहीं किया।

(XIII) जनहित

101. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

1. कोई सदस्य रक्षोपाय साधन के लिए केवल तभी आवेदन कर सकता है जब उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके जांच कर ली गई हो और उसे जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद के तारतम्य में उसे सार्वजनिक कर दिया गया हो। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को तर्कसंगत नोटिस दिया जाना और सार्वजनिक सुनवाई तथा अन्य समुचित उपाय शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने साक्ष्य तथा अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, उन्हें अन्य पक्षकारों की प्रस्तुतियों का उत्तर दिए जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा तथा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए कि रक्षोपाय साधन अपनाना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जिसमें उसके तथ्य एवं विधि के सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अपने तर्क युक्त निष्कर्ष एवं निर्णय होंगे।

102. कभी-कभी एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक घटकों के भिन्न-भिन्न एवं प्रतिस्पर्धी हित होते हैं। रक्षोपाय शुल्क का भिन्न घटकों को भिन्न ढंग से प्रभावित कर सकता है और जब उनके प्रतिस्पर्धी हित हो तो विभिन्न आर्थिक घटकों के लिए इसका प्रभाव सदैव उपयुक्त ही नहीं होता है। इसलिए विभिन्न आर्थिक घटकों के हितों का उपलब्ध जानकारी के आधार पर विश्लेषण किया गया।

103. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि कार्बन ब्लैक का सबसे बड़ा उपभोक्ता अर्थात् टायर उद्योग विभिन्न इनपुटों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क का सामना कर रहा है। इस मुद्दे का परीक्षण किया गया है। इस संबंध में परिवर्ती रक्षोपाय कानून के प्रमुख उद्देश्य, ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जो यह है कि चीन से बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निराकरण किया जाए। स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धी उद्योग के हित को ध्यान में रखना सभी के हित में है। यह स्पष्ट है कि यदि रक्षोपाय उपाय नहीं किए जाते हैं तो घरेलू उद्योग की कीमतें और उनका बाजार हिस्सा दोनों कम हो जाएंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अबहनीय सीमा तक घाटा होगा और उसके परिणामस्वरूप रोजगार तथा घरेलू बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यात्मिक और आर्थिक हित की क्षति होगी। रक्षोपाय शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी बना रहेगा और साथ ही, उपयोग करने वाले और क्रेता दोनों के पास अपनी भौतिक जरूरतों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्राप्त करने की व्यापक च्वाइस होगी।

104. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उपभोक्ता के लिए कार्बन ब्लैक की लागत 6% के लगभग होगी (यह तथ्य टायर उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से सत्यापित किया जा सकता है)। चीन का बाजार हिस्सा लगभग 11% है। मैं याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए आत्मनिवेदनों से सहमत हूँ; यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि उपभोक्ता उद्योग को इस उत्पाद का चीन से उसी स्तर पर आयात करना जारी रखना चाहिए और रक्षोपाय शुल्क लगाने से उपभोक्ता को चीन के आयातों की तुलना में 30% तक बड़ी (अनजितम सिफारिशों के अनुसार) हुई लागत प्राप्त होगी, इससे यह सिद्ध होता है कि उपभोक्ता उद्योग पर प्रभाव किसी भी हाल में 0.33% से अधिक नहीं होगा। यह इस तथ्य की अनदेखी कर रहा है

- कि प्रारंभिक निष्कर्षों में संस्तुत 30% अन्तिम रक्षोपाय शुल्क का प्रस्ताव भुगतान योग्य पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, का समायोजन किये जाने पर किया गया था।
105. यह तर्क देते हुए कि रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा, नोट किया जाता है कि ए टी एम ए ने इस संबंध में कोई परिभाषात्मक दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
106. उपर्युक्त हिस्से और कार्बन ब्लैक की अमहत्वपूर्ण लागत को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क को टायर उद्योग की कीमत पर शून्य या बहुत कम (0.19%) प्रभाव पड़ेगा।
107. पुनः यह नोट किया जाता है कि टायरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की 3 जांचें पहले ही की जा चुकी हैं और एक जांच चल रही है। इसलिए, टायर उद्योग पाटनरोधी शुल्क के आवरण में संसंरक्षित है। उपभोक्ता द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क का उपभोक्ताओं पर प्रभाव असहनीय होगा। साथ ही घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि चीन का बाजार हिस्सा देखते हुए प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का उपभोक्ता उद्योग पर नगण्य प्रभाव होगा। घरेलू उद्योग ने पुनः उल्लेख किया है कि प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप भी वह कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। जहां तक कार्बन ब्लैक पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद भारतीय बाजार में अत्यधिक आयात होते रहे जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची। इसलिए चरन जन गण से कार्बन ब्लैक का आयात करने पर रक्षोपाय शुल्क लगाना हित में होगा।

(XIV) साथ-साथ पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क

108. हितबद्ध पक्षकारों से कुछ निवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने दोनों शुल्क एक साथ लगाने की वांछनीयता के खिलाफ प्रस्तुतीकरण किया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि दोनों शुल्क एक साथ लगाना जनहित में नहीं होगा। इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया है। यह सच है कि पाटनरोधी शुल्क भी टैरिफ अवरोध बढ़ाकर पाटित आयातों के दुष्प्रभावों का मुकाबला करने और उन्हें निष्क्रिय बनाने के लिए एक व्यापार उपचार उपाय है। रक्षोपाय शुल्क टैरिफ अवरोध बढ़ाकर संवर्धित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों से घरेलू उद्योग की रक्षा करने का एक साधन है। दोनों ही शुल्कों का अन्य कार्यों के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ कार्य है अर्थात् आयातों के क्षतिकारी प्रभावों को निष्क्रिय करना। घरेलू उद्योग द्वारा मौजूदा आवेदन दायर करना विधिक रूप से न्यायाचित है। डब्ल्यू टी ओ कानून भी इसकी अनुमति देते हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी घरेलू या अन्तरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क भिन्न जांच अवधि पर आधारित था जबकि वर्तमान रक्षोपाय शुल्क, जिसका प्रस्ताव किया जा रहा है, अत्यधिक हाल की अवधि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। वास्तव में, निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी, ए टी एम ए द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क में पहले से मौजूद पाटनरोधी शुल्क का पूरा खयाल रखा जाएगा। अतः, इससे एक ही क्षति के लिए दोहरा संरक्षण नहीं होगा।

अन्य मुद्दे

जहां तक प्रतिस्पर्धा विधि का प्रयोज्यता का संबंध है, यह धारित किया जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके रक्षोपाय शुल्क या कोई अन्य शुल्क लगाना या न लगाना एक विधायी कार्य होने के कारण प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा की विषय-वस्तु नहीं है। दोनों अधिनियम दो भिन्न क्षेत्रों में सार्थक रूप से काम करते हैं।

(XVI) अनन्तिम उपाय

110. प्रारंभिक निष्कर्षों में यह धारित किया जाता था कि चीन जनवादी गणराज्य से कार्बन ब्लैक के बड़े हुए आयात के कारण कार्बन ब्लैक के घरेलू उद्योग/उत्पादकों के लिए बाजार विकृति हुई है या बाजार विकृति की चुनौती सृजित हुई है। यह भी पाया गया है कि ऐसी संवेदनशील परिस्थितियाँ मौजूद हो गई हैं जिनमें रक्षोपाय साधनों का उपयोग करने में जरा सी भी देरी से क्षति होगी जिसका सुधार करना मुश्किल होगा। घरेलू उद्योग द्वारा, ऊपर के पैराग्राफ में यथावर्णित कई संवेदनशील क्षति प्राचलों में वर्ष 2011-12 के दौरान सहन की गई बाजार विकृति पर विचार करते हुए यह धारित किया गया कि इस मामले में अपूरणीय क्षति की संभावना को निष्फल करने के लिए अनन्तिम उपाय की संस्तुति ठीक ही की गई थी। तथापि, मौजूदा मामले में आज की तारीख तक कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया गया है।

(XVII) निष्कर्ष

111. उपर्युक्त जांच-परिणाम के आधार पर यह देखा जाता है-
- क) विद्यमान उत्पाद के आयातों में क्षति अवधि के दौरान विशुद्ध रूप से वृद्धि हुई जबकि हाल की अवधि में उनमें तीव्र वृद्धि हुई।
 - ख) चीन जनवादी गणराज्य से कार्बन ब्लैक के संबंधित आयातों से घरेलू उद्योग/कार्बन ब्लैक के उत्पादकों को बाजार विकृति हुई है और उनके समक्ष बाजार विकृति की चुनौती हुई है। और
 - ग) यह स्पष्ट हुआ है कि घरेलू उद्योग को क्षति चीन जनवादी गणराज्य से संबंधित आयातों के कारण हुई; और
 - घ) चीन जन-गण से कार्बन ब्लैक के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जमझट में होगा।

(XVIII) सिफारिश

112. घरेलू उत्पादकों कार्बन ब्लैक की औसत उत्पादन लागत (गोपनीय) लगाई गई पूंजी पर तर्कसंगत अर्जन, आयात शुल्कों के मौजूदा स्तर तथा कार्बन ब्लैक की औसत बाजार कीमतों पर विचार करते हुए अध्याय शीर्षक 28030010 के अन्तर्गत आने वाले कार्बन ब्लैक (केवल रबड़ अनुप्रयोगों के लिए) पर एक विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क निम्नलिखित ढंग से अधिरोपित करने का प्रस्ताव है:

अवधि	विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क की दर
प्रथम वर्ष	30% यथामूल्य, देय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को कम करके
द्वितीय वर्ष	25% यथामूल्य, देय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को कम करके
तृतीय वर्ष	20% यथामूल्य, देय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को कम करके

113. उपर्युक्त रक्षोपाय शुल्क लगाने की संस्तुति जो चीन जनवादी गणराज्य से इस वस्तु के आयात पर अधिरोपित की जाएगी, को घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम जरूरत माना जाता है।

[फा. सं. डी 22011/12/2011]

इच्छाणी दत्त मजूमदार, महानिदेशक

DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2012

Subject : Safeguard investigation concerning imports of Carbon Black—Final findings—Reg.

G.S.R. 602(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 thereof;

A. Procedure

1. An application has been filed before me Under Rule 5 of the Custom Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 by M/s. Association of Carbon Black Manufacturers, 5A Raba Kailash, 55/4 Ballygunge Circular Rd. Kolkata-700019 on behalf of domestic producers of Carbon Black in India along with two of its member companies; i.e. M/s. Phillips Carbon Black Limited, 31, Netaji Subhash Road, Kolkata-700001, and M/s. Hi-Tech Carbon, Murdha Indl Area, P.O. Renukoot, Dist: Sonbhadra (U.P.) for imposition of Safeguard Duty on imports of Carbon Black (for rubber applications) into India from China PR, to protect the domestic producers of said Carbon Black against market disruption and threat of market disruption caused by the increased imports of the said Carbon Black into India from China PR.
2. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against imports of Carbon Black (for rubber applications) from China PR, was initiated vide Notice of Initiation dated 2nd December, 2011 and published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.
3. A Copy of the Notice of Initiation dated 2nd December 2011 along with copy of non-confidential version of the application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and other Ministries concerned, Govt. of China PR through their embassy in New Delhi and other interested parties listed below in accordance with Rule 6(2) & 6(3) of the Safeguard Rules, 2002:

(I) Domestic Producers

- a. M/s. Phillips Carbon Black Limited, 31, Netaji Subhash Road, Kolkata-700001

- b. M/s. Hi-Tech Carbon Murdwa Indl Area, P.O. Renukoot, Dist: Sonbhadra (U.P.)
- c. Continental Carbon India Limited, A-14 Industrial Area No. 1 South Side of GT Road Ghaziabad-201 001
- d. Ralson Carbon Black Ltd. Jhwal Kalan Tehsil Malerkotla Distt. Sangrur Punjab
- e. Cabot India Limited MIDC Plot No.3 Trans -Thane Creek area Thane Belapur Road Post Ghansoli Thane 400701 Maharashtra
- f. Himadri Chemicals & Industries Limited Registered Office Fortuna Tower 23-A, Netaji Subhas Road 8th Floor, Kolkata 700 001

(II) Importers

- a. M/s JK Tyres, Link House, 3, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
- b. M/s Birla Tyre, Shivam Chambers 53, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata-700 019, West Bengal.
- c. M/s Apollo tyres, Apollo House 7, Institutional Area, Sector-32, Gurgaon -122001 (Haryana)
- d. M/s CEAT Ltd., CEAT Mahal, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030
- e. M/s MRF Ltd., 124 Greaves Road, Chennai-06.
- f. M/s Ralson, Plot No: 3, New Industrial Area, Mandideep. Distt. Raichur, M.P. - 462046
- g. M/s Poddar Tyre, GT Road Jugiana, Ludhiana (PB) 141420
- h. M/s Oriental Rubber Industries, 525 Koregoan Bima Pune Nagar Road, Pune
- i. M/s Hindustan Rubber, 1 Janki Center OFF Veera Desai Road Andheri(W) Mumbai-53
- j. M/s. Agarwal Rubber, 15-1-503/49/A, Ashok Market, Siddiamber Bazar, Hyderabad 500 01, Andhra Pradesh
- k. M/s Exel Rubber, Flat no. 507, Sai Sadan Apts, Opp. SBI Bankampet, S.R. Nagar, Hyderabad - 500038
- l. M/s Tega Industries, First floor, No 210, 5th Main Road Vijay Nagar 2nd Stage Bangalore 560040
- m. M/s Phoenix Yule, Ideal Plaza, 4th Floor, 11/1, Sarat Road, Kolkata 600 02, West Bengal
- n. M/s Monotona Tyres, Mumbai, Mumbai 422 01, Maharashtra
- o. M/s TVS Srichakra, Perumalpatti road Velaripatti Road, Melur Taluq Madurai-625122

- p. M/s Ahuja Continental, 1109 Mittal Towers MG Road Bangalore
- q. M/s Midas Rubber, P. John Zachariah Buildings, Kottayam, Kerala, 686001
- r. M/s Tolins, M.C. Road, Kalady-683 574, Kerala
- s. M/s TM Tyres, 5-35, Survey No, 305 & 321 Kalakal Village Medak - 502320, Andhra Pradesh
- t. M/s Hartex Rubber (P) Ltd, Kamala Towers, 2nd Floor, Plot No.1-8-304 to 307, Patigadda Road, Begumpet, Hyderabad- 500 016. Andhra Pradesh.

(III) Exporters

- a. Hebei Daguangming Industry Group Co., Ltd., Western Side, Donghuan South Road, Shahe City, Hebei Province. P.R.China.
 - b. Shanghai Kargos International Trade Co., Ltd., T2-12F, No. 2601 Xietu Rd, Shanghai, P. R. China
 - c. Hebeijing country xinyuan rubber Chemical Co Ltd., Shengli road Guangsha district 31-1-101, Hengshui city, Hebei province, P.R.China
 - d. Hebei Yonghui Chemical Industries Import and Export Co., Ltd., No.199, Xinhua Road, Shijiazhuang, Hebei, P. R. China
 - e. Gansu Jinshi Chemical Co., Ltd., 109 #, West suburb, Minle County, Gansu, P. R. China
 - f. Shandong Shuangyan Chemical Co., Ltd., NO.787 Donger Road Dongying City, Shandong, P.R.China
 - g. Weifang Longzhou Industry and Commerce Co., Ltd., Luocheng Town, Shouguang City, Shandong Province. P.R.China
 - h. Laiwu Taishan Carbon Black Co., Ltd., Gaozhuang industrial zone, Laicheng, Laiwu, P.R.China
 - i. Qichang Chemical Co., Ltd., Beichenwang, tangyin County, Anyang City, Henan Province, P. R. China
 - j. Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd., Liyao, Jingdezhen City, Jiangxi Province, 333000, P.R.China Suzhou Boahua Carbon, Xushuguan Suzhou, P.R. China-21515
4. Questionnaires were sent to the known exporters from China PR, known importers/users in India and other interested parties as per the information available including the Govt. of China PR with request to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.
 5. Request to consider them as interested parties was received from M/s Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) and the request was accepted.

6. Requests for an extension of time to submit their replies were made by the following parties:
 - a. Exporting Nation, China PR.
 - b. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
 - c. Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc. Ltd., China.
7. After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, requests for extension of time to submit reply as per Rule 6(4) of Safeguard Rules'2002 were allowed.
8. Following interested parties made their submissions during the course of the investigations
 - a. China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters and China Rubber Industry Association.
 - b. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
 - c. Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc. Ltd. , China
9. Following parties provided information in the form of questionnaire responses
 - a. Hi-tech Carbon (Domestic Producer Questionnaire)
 - b. Phillips Carbon Black Ltd (Domestic Producer Questionnaire)
 - c. Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc. Ltd. , China (Exporter Questionnaire)
 - d. Apollo Tyres (Importer Questionnaire)
 - e. Ceat Tyre (Importer Questionnaire)
 - f. JK Tyre & Industries Limited (Importer Questionnaire)
 - g. Pheonix Conveyor Belt India (P) Ltd (Importer Questionnaire)
10. The information presented by the petitioners was verified to the extent possible, by onsite visits to the plants of the domestic producers. The non confidential version of verification report was placed in the public file.
11. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.
12. After expeditious conduct of investigation, Preliminary Findings were issued on 16th March, 2012, recommending imposition of provisional safeguard duty @ 30% ad-valorem on import of Carbon Black (for rubber applications) from China PR.
13. A Public Hearing was held on 25th May, 2012, which was attended by a number of interested parties. However, following interested parties made submissions at the time of oral hearing
 - a. Petitioners/domestic industry;

- b. China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters and China Rubber Industry Association.
- c. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
- d. Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc. Ltd., China

14. All interested parties who participated in the Public Hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

B. Views of Domestic Producers (Applicant)

15. The views expressed by the petitioners/domestic industry are summarized as follows: —

- a) The product under consideration is 'Carbon Black used in rubber applications'. It is an inorganic chemical used in production/ processing of rubber (including tyres), as reinforcing filler. Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black, lamp black, lampblack, thermal black, and noir de carbone. Carbon black for rubber applications is the Carbon black that is used in production/ processing of rubber (including tyres), as a reinforcing filler. The petition is in respect to increased imports of Carbon black used in rubber applications. Carbon black used in non-rubber applications, such as inks in copiers and computer printer cartridges, paints, crayons and polishes, is not within the scope of the present investigation. The subject goods fall under Chapter 28 of the Custom Tariff Act under subheading no. 28030010.
- b) There are four more producers of the goods but the applicant companies namely M/s. Phillips Carbon Black Limited and M/s. Hi-Tech Carbon account for more than 80% of production and hence are major producers.
- c) The Imports of the product under consideration have increased throughout the injury period in absolute terms with a sharp increase in imports in the most recent period. There is a sudden, sharp and significant increase in imports in the recent period. Imports have also increased in relation to production in India throughout the injury period with a significant increase in the most recent period. Imports of product under consideration have shown recent, sudden, significant and sharp increase. The condition prescribed under the rules in this regard is clearly met.
- d) The product under consideration has history of dumping causing injury to the Indian industry of the product under consideration.

- e) The import and injury related data for 4 year period has been filed by the petitioner. The petitioner has provided the quarter wise information for the injury period and month-wise information till December 2011.
- f) Basis of determination of import volumes: The petitioner considered information on imports reported by IBIS, DGCI&S and China Customs. The information published by DGCI&S and China Customs could not be adopted for the reason that they contained consolidated data including those imports of carbon black which are not for rubber applications.
- g) Imports as per China customs data: The China Customs statistics cannot be relied upon for the reason that the same includes imports of other types of carbon black as well, given that the imports are predominantly of the product under consideration and the entire requirement of other kinds of carbon black is extremely low, but the information published by the China Customs is nevertheless indicative of the fact that imports of carbon black have surged in significant volume.
- h) Increase in imports: Imports of the product under consideration has increased not only in absolute terms but also in relation to production and consumption with a significant increase in the most recent period. The reasons for increase in imports are as follows:
- i. Cost advantage: The domestic industry uses CBFS as a raw material for manufacturing Carbon Black whereas Chinese producers use CBO. There is a significant price difference between the two raw materials (CBO prices prevailing in China vs. CBFS prices prevailing in international market). The price difference between the two raw materials provides significant cost advantage to the Chinese producers which lead to low price imports of Chinese Carbon Black.
 - ii. In Carbon Black industry, the raw material cost plays a very important role and is the prime cost incurred by the producers of Carbon Black. Hence raw material prices play an important part in deciding the price trend of Carbon Black. The price trend would show that from the month of June, the prices of CBO have started to decline and at the same time the price of CBFS started increasing. Hence both domestic industry and China increased its prices. But despite such increase, there were huge difference between the price quoted by Chinese suppliers as compared to domestic industry prices and third countries prices. The price of Carbon Black from third countries i.e., Korea, Australia and Thailand have remained higher than the Chinese prices, which clearly establishes why the imports have increased from China and declined from third countries.
 - iii. China suppliers partly increased their prices in view of global increase in the prices as a result of increase in CBFS price. However, the Chinese prices still remained far lower than the prevailing prices of carbon black and resultantly, the Chinese carbon black became extremely lucrative for the consumers. It is this factor which has led to significant surge in imports of carbon black in India.

- iv. The price difference in the raw material has resulted in cheap Chinese imports of Carbon Black capturing the Indian market causing injury to domestic industry.
 - v. Also, even when the Anti-dumping duty is added to the imports from China, the prices of Chinese Carbon Black is still far lower than those of domestic industry, clearly leading to the price advantage to the Chinese producers.
 - vi. Excess Capacity: The Chinese producers have excess production capacities and are therefore looking for market opportunities. The Chinese Carbon Black market is expanding on year to year basis thereby increasing their export volumes. The capacity of Carbon Black with China has exceeded 5 million ton per annum and the output is 3.4 million tones. The price difference between the two raw materials has further increased after Oct., 2011. Considering the huge production capacities of the subject goods in subject country and their export orientation and the increasing demand for the subject goods in India, in all likelihood imports will continue to remain high compared to 2008-09 and 2010-11.
- i) Demand of the product concerned has increased throughout the injury period.
 - j) Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry. Decline in market share of the domestic industry has adversely impacted the production and capacity utilization of the domestic industry.
 - k) The domestic production increased up to 2010-11, but thereafter declined in the most recent period. The production process of carbon black is such that the domestic industry should attempt to produce more and more product in order to achieve not only economies of scale but also to arrest fixed cost associated with the plant and production efficiencies. However, so rapid is the increase in the imports that the domestic industry was forced to look for market opportunities outside India in order to dispose off the production which could not be sold in the domestic market. Despite these extra efforts by the domestic industry, the inventories levels with the domestic industry were rising to such an extent that the domestic industry were eventually forced to take production suspension.
 - l) The petitioners submit that the addition capacity is in view of present and potential demand of the product in the market. There is a decline in the capacity utilization year to year basis as well as quarterly basis.
 - m) The sales of the domestic industry increased up to FY 2010-11. But, it declined in the recent period. There has been significant decline in the sales volumes of the domestic industry as a result of increased imports. The domestic industry continues to face lower sales volumes. The decline in sales is despite the fact that the demand increased significantly. Sales of domestic industry declined whereas the imports have increased significantly.
 - n) The domestic industry is faced with the problems of accumulated inventories throughout the injury period. The levels of inventories have increased from 3,912 MT in 2008-09 to 9,832 MT in 2011-12.

- o) The landed price of imports is lower than the (a) selling price of the domestic industry and (b) cost of production of the domestic industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in price suppression and depression. It is relevant to point out that the gap between the cost of sales and selling price of the domestic industry shrink on quarter to quarter basis with cost of sales higher than selling price in last two quarters of 2011-12. Consequently domestic industry suffered financial losses in the recent period.
- p) The profitability of the domestic industry improved in 2009-10 but thereafter started declining significantly.
- q) the number of employees has increased throughout the injury period both yearly and quarterly. Hiring & firing of employees is the last resort situation of the domestic industry. Domestic industry submits that employment as a factor of injury may not show adverse impact of increased imports on the domestic industry in view of labour laws in the country and nature of the production process.
- r) In addition to the market disruption already inflicted on the domestic industry, increased imports of Carbon Black are threatening market disruption to the domestic industry.
- s) There are no other factors that may be attributing to the market disruption to the domestic industry other than dumping and the low priced imports. Dumping of the product from China PR (and other countries) caused significant injury to the domestic industry. However, the Designated Authority has already recommended imposition of anti dumping duties on such dumped imports. Therefore, the current injury to the domestic industry is after taking into account the injury caused to the domestic industry from dumped imports.
- t) The interim measures are imperative in view of the steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of the product under consideration.
- u) Petitioners requested imposition of provisional safeguard duty. The interim measures are imperative in view of the steep deterioration in performance of the domestic industry and the threat of market disruption as a result of increased imports of the product under consideration. The domestic industry has been forced to undertake production cuts. Domestic sales of the domestic industry have declined significantly. The capacity utilization of the domestic industry has steeply declined in the most recent period in view of decline in sales caused by surge in imports. Inventories with the domestic industry are rising significantly. Further, the domestic industry is facing financial losses from carbon black operations.
- v) Petitioners submit that the quantum of safeguard duty can be reduced by the amount of anti dumping duty. The domestic industry is not looking for dual protection, nor has asked for safeguard duty ignoring anti dumping duty. The

domestic industry requests the Director General to consider the injury to the domestic industry and address the gross injury to the domestic industry.

w) Public interest: Imposition of proposed safeguard duty shall be in public interest for the following reasons:

- i. The producers interest – Imposition of safeguard duty shall be in the public interest from Indian manufacturing sector point of view, as it would help preventing decline of the domestic industry in India, would prevent surge in import and would address the significant injury being caused to the domestic industry as a result of this surge in imports. The domestic industry has expanded its capacities and therefore needs to be protected against low priced imports.
- ii. Consumer's interest – Major use of the product under consideration is in manufacturing of tyres. The product under consideration is not a major cost element for consumer industry (major cost element is natural rubber). As per estimate of the domestic industry, cost of carbon black for the consumers is in the region of 6% (the fact can be established from the annual report of the tyre industry). Further, market share of China in demand for the product in India was in the region of 11% during the period of surge in imports. While the consumers need not import any carbon black from China and the domestic industry has sufficient capacities to meet the present and potential demand of the product in the Country; even if it is argued that the consumer industry should continue to import the product at the same level from China and imposition of safeguard duty shall result in cost to the consumer increasing by 30% in respect of these Chinese imports, it follows that the impact on consumer in any case shall not exceed 0.33% (even ignoring anti dumping duty). It is, however, submitted that even this would not be the impact on domestic industry for the reason that the tyre industry can source the entire volume from the domestic market and the domestic industry does not intend to increase its price because of imposition of safeguard duty.
- iii. The Govt. of India had earlier imposed safeguard duty on imports of one of the rubber chemicals (PX-13) wherein the Director General (Safeguards) came to the conclusion that imposition of safeguard duty on imports of PX-13 shall be in public interest.

C. Views of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)

16. The views expressed by the Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) are summarized as follows –

- a) Change of price data mid way by domestic industry: Domestic industry has changed the price data mid way through the investigation without providing any explanation of the same.
- b) Under reporting of export volumes of domestic industry by Director General (Safeguards) : The export volumes mentioned in page 16 of the Preliminary Findings does not match with the export volumes reported in the 'On-site

verification' report of the DI and it appears that the export volumes in the preliminary findings are grossly under reported.

- c) Preliminary Findings disregard the submission of importers: The Hon'ble DGS vide paragraph 65 of the preliminary findings has stated that: "ATMA has also not provided any information on imports of carbon black by its various members." However this statement by the Hon'ble DGS is incorrect as Apollo, JK Tyres and Ceat had provided details of import volumes, CIF Price and domestic procurement price of carbon black. ATMA has the acknowledgment receipt of the submissions made to the DGS.
- d) Excess confidentiality granted by Director General (Safeguards): Domestic industry vide its submission dated January 2, 2012 has stated that the plants of the domestic industry were shut down. However domestic industry has not provided the reasons for the same. It is the submission of ATMA that DI being a public listed company would have to provide the reasons for the shutdown of the plant to its shareholders. Thus the information cannot be termed as "confidential" or "business sensitive" as argued by the counsel for the domestic industry as the same would be available in the public domain.
- e) Domestic industry recognizes inherent competitiveness of coal tar as an input for production of Carbon black
 - i. In view of the apparent cost advantage in using coal tar, domestic industry has been trying to shift to coal tar. In this respect, the annual report of PCBL provides that PCBL has been using tar oil as an input product since F.Y 2008-09. Thus PCBL is already using Coal Tar oil as an input in production of Carbon Black. In this respect, it is the submission of ATMA that Non Injurious Price (NIP) for a company should be based on most efficient use of resources. Since PCBL is already using Coal Tar, NIP for the domestic industry should be determined as per the Coal tar prices and not as per CBFS prices.
 - ii. Furthermore PCBL has also commissioned a coal tar plant in Orissa. As per the annual report of PCBL, the plant is expected to be commissioned in the 2nd quarter of the financial year 2012-13. In this respect, it should be noted that domestic industry as per the petition has sought duty protection for 4 years. However in view of the fact that the coal tar plant will be commissioned in Q2 of (2012-13), a duty based upon the CBFS prices would be unjustified as the NIP would decrease further.
- f) Significant financial performance by DI
 - i. Installed capacity increased from 5,00,000 MT to 7,24,000 MT
 - ii. Production increased from 4,16,244 MT to 6,14,105 MT which is an increase of 48%. There was also an increase in average production per month which increased from 34,687 MT in 2008-09 to 51,175 MT in 2011-12.

- iii. Capacity utilization increased from 83% in 85%.
 - iv. Domestic sales decreased by a mere 4.8% from previous year but increased by a huge 32% from the base year.
 - v. Domestic sales value increased by 65% in 2011-12 as compared to 2008-09.
 - vi. DI is posting profits.
 - vii. Decline in profits is on account of Capacity expansion.
- g) No Price Suppression/ Depression: DG Safeguards in its previous ruling in *Coated Paper Board* dated 3/11/2009 has ruled that when there has been an increase in import prices, in absence of any contrary evidence submitted by the domestic industry, any decline in profits cannot be attributed to increased imports. As per the present petition, domestic industry has stated that the decline in profit is due to increase in imports from China PR. However in view of the above ruling, decline in profits cannot be attributed to imports from China PR. It should also be noted that DG Safeguards has not addressed the issue of the rise in domestic procurement price, even though the same was provided by ATMA on both confidential and non confidential basis.
- h) No threat of market disruption: DI has posted significant financial performance on all injury parameters including profits. However there has been a decline in profits in 2011-12. ATMA thus submits that a marginal decline in profits cannot lead to a conclusion of injury or threat of injury to the domestic industry.
- i) Alleged Injury to the DI covered by Anti dumping duty: The increase in domestic selling price is complemented by increase in domestic sales value which increased by 65% during the same period which clearly shows that the price increase did not negatively affect sales volumes. Thus ATMA submits that any injury to the domestic industry is covered by the existing anti dumping duty.
- j) Break in of Causal Link due to non segregation of injury: DGS not following its own practice of not permitting double duty protection. In exceptional circumstances a product may attract antidumping and safeguard duty. However simultaneous levy can be imposed, only if injury from the causes is 'segregated' as stated by Hon'ble DGS in the Safeguard investigation against import of Front Axle Beam, Steering Knuckle and crankshafts of medium and heavy commercial vehicles from China PR. Preliminary findings give no indication why existing antidumping duty is not sufficient to address market disruption, as required by the ruling in Front Axle Beam. This non segregation of injury in the present petition results in break in of the causal link between imports from China and the alleged injury to the DI.

D. Views of M/s Jiangxin Black Cat Carbon Inc. Ltd.

17. The views expressed by M/s Jiangxin Black Cat Carbon Inc. Ltd are summarized as follows –

- a) Inclusion of products not covered within the scope of product under consideration and incorrect import statistics
- i. The investigation is with respect to carbon black for rubber applications only and other grades of carbon Black used in non rubber applications are explicitly excluded from the scope of investigation. However, preliminary finding issued by DGSG is totally silent as to how import analysis was done and whether any exclusion was made or not.
 - ii. Data provided for Q2 2011-12 in the initiation notice and domestic industry petition is same, whereas there is a slight decline in preliminary findings. Figures for Q1 2011-12 are same in Initiation Notice, Preliminary Findings and domestic industry Petition.
 - iii. In the preliminary findings, DG SG has stated that for entire POI i.e 2008-09 till Oct 2011-12, it has relied upon IBIS import statistics provided by domestic industry. If that is the case, then there should not be any variance in the petition and preliminary findings. Even if it were to be assumed that in the preliminary findings DGSG excluded non -PUC from total import, then it is not clear as why Q1 2011-12 figures are same for all the above mentioned 3 sources.
- b) Market disruption claim is incorrect
- i. DG SG has accepted the arguments of domestic industry that in view of the surge in imports from China PR, it is facing market disruption and there is threat to market disruption in the future and provisionally held that domestic industry is facing market disruption and also threat of market disruption.
 - ii. Though domestic industry is heavily relying on Q2 2011-12 and Oct 2011 import figure surge in imports, yet it has neither been able to establish material injury nor any causal link between the injury and increased in imports.
 - iii. While revenue of HI- Tech Carbon has increased by 21% in 2011-12(on annualized basis) compared to 2010-11, Phillips Carbon Black has 30.43% increase in sales revenue during the same period. Overall, the domestic industry as a whole has been able to increase the sales revenue by almost 26% in 2011-12. Thus, imports from China PR have not stopped domestic industry to grow and domestic industry has been able to increase its sales.
 - iv. The quarter to quarter comparison of sales revenue for 2010-11 and 2011-12 shows remarkable increase in sales revenue of domestic industry. Revenue increased by 51% in Q1 and by 28% and 15% in Q2 and Q3 respectively. Since 2010, domestic industry has not suffered any loss or decline in revenue.

- v. Domestic industry's growth could be witnessed from ever increasing production and capacity addition for past 2 years. Compared to 2008-09, production as well as capacity of the domestic industry has increased by 45%. Compared to 2010-11, the performance of the domestic industry has improved. While production capacity has increased by 12%, production has also increased by 4% for the same period
 - vi. Thus as far as sales, production and production capacity is concerned, rising imports had absolutely no volume effect on the domestic industry.
 - vii. Post 2008-09, domestic industry has remained healthy and has been performing exceedingly well. No loss has been incurred by the domestic industry.
 - viii. In the preliminary findings, DG SG has rejected the profits stated in annual reports stating that the annual performance reported is not exclusively in respect of product under consideration. That being the case, the segregated information relating to production, capacity, sales revenue and profit for product under consideration and non-product under consideration should be provided. And if segregation is not possible, then DG SG is bound to consider the overall performance of domestic industry with respect to 'carbon black' as a whole.
- c) Other causes of injury: Domestic industry has not revealed to DG SG that one of its constituents HI-Tech Carbon imports goods from Thailand. Thus, any loss in market share of the domestic industry is due to the fact that exports from related entity have taken that share. Therefore DG SG should either terminate the investigation or refer the matter to DGAD to decide on the issue.
- d) No causal link: Imports from China and profit made by domestic industry are directly proportional to each other. Whenever the imports increased, the profits of the domestic industry also increased and when the profits of the domestic industry declined, the imports also witnessed a decline. There are other factors, which determine the performance of the domestic industry and clearly establish absence of causal link between the performance of domestic industry and import from China.
- e) Raw material cost: CBFS forms a major raw material and a major cost ingredient in production of carbon black. Changes in Carbon Black cost would to a large extent move in tandem with change in raw material prices i.e CBFS. Compared to Q1, CBFS prices declined by 2%. During the same period, cost of sales of the domestic industry increased by 10%. However, in Q3, CBFS prices increased by 8% compared to prices prevailing in Q2. As against this, cost of sales increased by only 1%. Thus there is no link between the change in the raw material price and resultant cost of sales. When a major raw material price is not having a significant impact on cost of Carbon Black, then it becomes obvious that there are other factors that are responsible for change in cost.
- f) China Specific Safeguard duty cannot be imposed: TPSS investigation against China is by nature exceptional, which is to be sparingly used by the other

Members countries of WTO and should not be used in every case of increase in imports.

- g) Safeguard duty and Anti –Dumping duty cannot be imposed simultaneously: Anti-dumping duties imposed in 2010 were based on injury margin. Hence anti-dumping duties so imposed have already taken care of injury caused to domestic industry by the imports.
- h) During the period of anti –dumping imposition, selling price increased by 24% while cost of production only increased by 12%. Even between April 2011 and Oct 2011, while CBFS price increased by 4%, selling price of the domestic industry during the same period increased by 8%. thus, even with increase in raw material price, domestic industry has been able to increase its selling price by an even bigger rate. Furthermore between the same period, import prices from China has increased by 17%. Clearly indicates that ever since anti- dumping duties were imposed, domestic industry has been able to consistently increase its selling price and earn profits. Along with increase in rise in selling price, Chinese import prices have also been consistently rising. Thus, there is no injury, which has not been covered by anti –dumping. Any safeguard duty imposed over and above the anti –dumping duties will only amount to double protection to domestic industry.

E. China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters and China Rubber Industry Association

18. The views expressed by the China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters and China Rubber Industry Association are summarized as follows –

- a) Inaccuracy and Insufficiency of Information in the Petition: It is a settled principle that a duly filled petition with 'sufficient' evidence regarding imports, injury and causal link is mandatory in order to initiate an investigation. However, as per the Submissions of the Petitioners dated 7th January, 2012, it can be seen that the Petitioners have in fact revised their Import Statement and Costing Information subsequent to the initiation. Hence, the initiation itself was based on insufficiently supported petition and does not justify the present initiation.
- b) Unreliable Source of Information accepted by the Authority: At paragraph 65 of the said Findings, the Hon'ble Director General (Safeguards) has relied upon privately sourced import data from IBIS as submitted by the Petitioners and not on the import data from DGCI&S. It is respectfully submitted that the reliance on privately sourced data is not in consonance with the established practice of the Hon'ble Director General (Safeguards) followed in earlier investigations wherein the Hon'ble Director General (Safeguards) has relied upon information sourced from DGCI&S at least to the extent possible.
- c) Post – Period of Investigation decline in Imports: It is respectfully submitted that in the light of the abnormal accumulation of imports in the months of September-October-2011 the Hon'ble Director General (Safeguards) ought to examine the

actual imports, post October- 2011 to correctly assess the position on imports into the country. In fact, the change in the demand pattern is clearly reflected in the actual import data post October 2011 which shows a rapidly declining trend in imports from China PR. A mere perusal of the import data, clearly reveals that the imports in period after September 2011 have actually declined and do not show a continued increasing trend required for the imposition of safeguard duty.

- d) Period of Investigation is not Recent: The Appellate Body of the WTO in *Argentina – Footwear (WT/DS121/AB/R dated 14th December, 1999)* explained that "the increase in imports must have been "sudden and recent." The dispute concerned provisional and definitive safeguard measures imposed by Argentina on imports of footwear in 1997. The Appellate Body found that an examination of import trends over a period of five years is not reasonable, in light of the "is being imported" language used in the WTO Agreement on Safeguards.
- e) In the factual matrix of the case at hand, the Period of Investigation begins from April 2008 and ends in October 2011. Clearly, the data which is upto 42 months old cannot be qualified to be "recent". The imports analysed by the Hon'ble Director General (Safeguards) are dated and distort the injury analysis.
- f) Raw material prices in China PR as "other factors" and not "unforeseen circumstances": Price trend of CBFS cannot be regarded as the "unforeseen developments" which will lead to increase in imports and cause injury or threaten to the domestic industry. The Hon'ble Director General (Safeguards) cannot exclude the possibility of increases in CBO which may become more expensive than CBFS. The Chinese Carbon Black industry cannot be penalised for using a more cost effective method of producing the subject goods by relying upon low cost raw materials
- g) Absence of Injury to the Domestic Industry
 - i. The evaluation of the requisite criteria does not reveal any negative impact to the Domestic Industry which is solely linked to the increased exports from China PR and hence, there is no injury to the Domestic Industry.
 - ii. As can be seen from the data, the Domestic Industry has been expanding and adding capacities, which has resulted in the installed capacity, domestic production and the capacity utilisation to grow. As can be seen the total sales of the Domestic Industry has been in tandem with the increase in production.
- h) Absence of threat of market disruption: It can be seen from the Chinese exports and the ratio to global exports has sharply decreased from Sept.2011 onwards. The increase in exports from China PR, was a temporary effect due to peculiar demand-supply situation in India and the trade flow is back to the normal level and thus there is no threat of market disruption.
- i) Non-attribution and absence of causal link: It is respectfully submitted that the alleged injury claimed by the Domestic Industry is not attributable to the increase in imports of the subject goods solely from China PR and there is an absence of causal link.

- j) The effect of the increase in imports from other sources such as Thailand, Russia and Korea must be analysed and considered by the Hon'ble Director General (Safeguards) and the injurious effects of the same, if any, ought to be segregated.
- k) Export Focus of the Domestic Industry: As compared to the base year of 2008-09, the exports have increased significantly as well as the export prices of the domestic industry. Thus the commercial choice of directing their sales whether in the domestic market and / or export market which has allegedly caused them injury cannot be attributed to an increase in imports from China PR. This is clearly a case of self-inflicted injury, if any.
- l) Efficacious Alternate Remedy is Available: It is respectfully submitted that the claims of the Petitioners can be adequately addressed by the Hon'ble Designated Authority at the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties in the impending Mid-term Review which is already in progress. Hence, the Petitioners already have an efficacious alternate mechanism by virtue of the which all claims of injury can be adequately redressed and the present transitional safeguard-duty investigation is unnecessary.
- m) Public Interest: The additional trade remedy protection will be further detrimental to the growth of the Indian tyre industry which is grossly damaging to the larger public interest and economical interest of the country.

F. Rejoinder of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA):

- a) The statement of the DI that the reason for increase in imports is due to the cost advantage of the Chinese producers which is on account of use of Coal Tar oil. As ATMA has clearly demonstrated in its POST PH WS as well this submission, DI is itself using coal tar oil since 2008-09 and moreover a coal tar plant will be commissioned in the next coming quarter, i.e. July 2012-September 2012. In view of the same, the NIP of the DI should be determined based on coal tar as an input.
- b) The injury figures along with the profit figures as provided by ATMA in its POST PH WS clearly illustrate that DI is not suffering from market disruption. Moreover DI has not been able to refute the claim of ATMA that domestic procurement prices have increased by 38-41% in Q4 of 2011-12 as compared to Q3 of 2010-11. The domestic procurement price clearly illustrate that imports have not had any effect on domestic prices especially since import prices have increased by 45% in Q4 of 2011-12 as compared to Q1 of 2008-09.
- c) ATMA request the Hon'ble DGS not to allow the DI to change its data mid way and if the same is allowed, an explanation for the same should be provided to all interested parties.
- d) ATMA would like to draw the attention of the Hon'ble DGS towards the break in of the causal link. ATMA in its previous submission had submitted that no break up of injury on account of dumping and on account of surge in imports has been provided either by the DI or by the Hon'ble DGS. Therefore in view of the past practice of the DGS as reflected in the Front Axle Beam, Steering Knuckle and

crankshafts of medium and heavy commercial vehicles from China PR17, the causal link between the imports and the alleged injury to the DI is broken.

- e) DI has not been able to show as to how the existing anti dumping duty is not sufficient to cover the injury to the DI. In this respect ATMA relies on its previous submissions. It should be noted that DI has not presented any arguments refuting the claim of ATMA.

G. Rejoinder of M/s Jiangxin Black Cat Carbon Inc. Ltd

- a) Since domestic producers are having a facility which uses only CBFS whereas Chinese producers use CBO, there is always bound to be difference between the costs of both the products.
- b) Increase in Chinese Imports only a temporary trend.
- c). TPSSM is an exceptional Measure.
- d). No injury to domestic industry.
- e). No loss suffered.
- f.) No threat of serious injury.
- g). Fit case to refer to DGAD.

H Rejoinder of China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters and China Rubber Industry Association

- a) The initiation of the present investigation is erroneous
- b) Period of investigation is not recent.
- c) Annualising/Extrapolating the imports is erroneous.
- d) Significant decline in imports post-period of investigation.
- e) Lack of injury to the Domestic Industry.
- f) Raw material prices in China PR as "other factors" and not "unforeseen Circumstances".
- g) Absence of Critical Circumstances.
- h) Difference in raw material prices and technology is clearly a non- attributive factor.
- i) There is no threat of market disruption to the domestic industry.
- j) The commercial choice of directing their sales whether in the domestic market and /or export market which has allegedly caused them injury cannot be attributed to an increase in imports from China PR.
- k) The imposition of safeguard duty will lead to dual remedy protection to the Domestic Industry.

- l) The additional trade remedy protection will be further detrimental to the growth of the Indian tyre industry which is grossly damaging to the larger public interest and economic interest of the country.

I. Rejoinder of Domestic Industry:

(i) On submissions of ATMA-

- a) The Director General has grossly inadequate/insufficient questionnaire response/information/cooperation from consumers of the product under consideration in India as (a) ATMA Member Companies constitute hardly 64% of total consumption of the product under consideration. (b) Consumption by ATMA Member companies participating in the present investigations constitutes quite lower consumption of the product under consideration in India. (c) Other consumers of the product under consideration have preferred non cooperation with the Director General. (e) The Director General may kindly consider consumer wise imports of the product. (d) The significant surge in imports is because of imports made by, inter-alia, Balakrishna Tyres, which, in fact is a non cooperating party.
- b) Neither the Chinese producers nor the Indian consumers' responses can be considered as "adequate". In other words, the Director General may kindly conclude that there was insufficient/inadequate response from the Chinese exporters and Indian consumers.
- c) There is a typographical error in the submission made before the Designated Authority. Instead of reporting imports from subject countries of anti dumping case (Australia, Thailand, China and Russia), the domestic industry has inadvertently mentioned only Chinese imports, that too an incorrect figure. It has already been clarified to the DGAD and also to the Director General. However, the imports statistics used in the present investigation are pertaining to China only. In any case, the Director General has adopted its own verified data and has not blindly applied the claims of the domestic industry.
- d) So far as information required on gross imports of the product in the Country is concerned, the information provided by the responding exporters or importers/consumers could not be relied upon for determining volume of imports because while disputing the claims of the domestic industry with regard to import volumes, ATMA has not lodged any verifiable claim with regard to total imports of carbon black in India from China and third countries.
- e) It is not the case where issue of use of CBO by China PR and DI is concerned. The issue concerns the price at which CBO is available to the Chinese producers, domestic industry and global producers. The domestic industry argued that CBO price is low selectively in China and only for Chinese consumers. They can neither import CBO from China at these prices, nor are CBO prices in the global market low.

- f) Increase in sales revenue is due to increase in the cost of sales of the product under consideration but the profits of the domestic industry have declined significantly both year-wise and quarterly.
- g) ATMA has access to 10 tyre manufacturing companies owing to their membership with ATMA but has submitted the data of only three companies (Apollo, JK Tyres and Ceat). The association has deliberately not disclosed the data pertaining to rest of its members. The injury margin after adding anti dumping duty is quite significant and establishes that the domestic industry is suffering injury despite anti dumping duty.

(ii) On submissions of M/s Jiangxin Black Cat Carbon Inc. Ltd

- a) The data provided in the petition is the raw data which includes all the Carbon Black imports. However, in the import statement, injury analysis and increased imports analysis, imports pertaining to Carbon Black for rubber applications only have been considered. In any case, the Director General (Safeguards) has considered imports as per their own analysis. The Director General has not considered the import volumes claimed by the domestic industry. Thus, there is no legal basis for the argument that the imports considered includes significant non-product under consideration.
- b) So far as data for Q2 (2011-12) i.e 25772 MT submitted in the application filed before DG(Safeguards) is concerned, it is fact that the said quantity has been mentioned in the safeguard petition, but the figure taken by DG(Safeguards) for Q2 (2011-12) is 25686 MT based on verification done. It is also submitted that none of these parties disputing the preliminary findings with regard to increased imports have provided any information with regard to gross imports of carbon black in India.
- c) That the import figures are different due to different sources adopted. In the initiation notification, the DGSD adopted the DGCI&S data wherein the petitioners have adopted IBIS data in the petition. However, in the Preliminary Findings DGSD has adopted IBIS data after doing their own analysis of transaction-wise data of the product under consideration.
- d) Increase in sales revenue is due to increase in the cost of sales of the product under consideration but the profits of the domestic industry has declined significantly not only year-wise but also quarterly. Increase in values per se does not indicate anything with regard to the performance of an industry. The increase in turnover may be a result of increase in raw materials (as the situation is case of tyre industry and carbon black industry).
- e) That capacity enhancement is a long term process driven out of macro-economic factors and the period of actual enhancement cannot be seen in isolation. Domestic industry has enhanced capacities considering present and potential demand for the product in the Country. However, due to the increased imports, the process of capacity enhancement of the domestic industry has slowed down.
- f) The profit earned by the domestic industry has thus been considered in relation to carbon black for rubber applications relating to domestic market only.

- g) The increase in profits as per the annual reports of the petitioner companies is pertaining to the overall performance of the company, whereas the present investigation is for domestic operations of Carbon Black for rubber application. Therefore statements in the annual reports cannot be relied upon.
- h) All information filed by the domestic industry and that relied upon by the Director General (Safeguards) is for the product under consideration only. Since the domestic industry has made available segregated data for the product under consideration, overall performance cannot be and need not be relied upon.
- i) The petitioner has not imported any goods from its related company during the injury period. The argument is purely imaginary. Further, imports from third countries collectively declined and Chinese imports increased. there are no other factor causing injury expect increased imports from China PR.
- j) The surge started from July-Sept., 2011 and with the surge in imports, the profitability of the domestic industry steeply deteriorated. Therefore, imports from China and profit made by domestic industry are not directly proportional to each other
- k) Cost of sales of the domestic industry has moved in tandem to the CBFS prices. Also in 2011-12, which is the surge period, the price of CBFS has increased and so the cost of sales. But the domestic industry was unable to increase its selling price in proportion to increase in cost of sales resulting in decline in profits. In 2011-12, the import price has increased, but same remained far lower than not only the selling price of the domestic industry but also its cost of sales.
- l) The accession treaty of China PR nowhere states that the Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism is exceptional and should be taken up only in rare situations. Notwithstanding, the situation being faced by the domestic industry is an exceptional situation wherein the domestic industry has been faced with decline even in volume parameters.

(iii) On submissions of China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters and China Rubber Industry Association:

- a) Imports of the product under consideration have increased over the injury period in absolute terms with a sharp increase in imports in the recent period. There is a sudden, sharp and significant increase in imports in the recent period. Both annual and quarter-wise imports volumes also show a significant increase in imports.
- b) There is a slight decline in imports in FY12-Q4, but the levels of imports remain even in this period was at the higher levels as compared to the previous quarters thereby showing a significant increase in imports. In any case, there is no legal requirement for a determination that imports are presently increasing. Rather, imports could have 'increased' in the recent past, but not necessarily be "increasing" upto the end of the period of investigation or immediately preceding the determination.
- c) No evidence has been provided by this interested party to show that IBIS data is not reliable. The Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules,

2002, do not specifically define the agency from where the import data should be taken but it is the discretion of the investigating authority to consider the data available to them. Also, there are cases in the past wherein IBIS data has been relied upon. Therefore it is in consonance with the established practice followed in earlier investigations.

- d) There are plethora of cases in the past like PX-13, Aluminum FRP & Foil, Phthalic Anhydride wherein Director General (Safeguards) has relied upon IBIS data.
- e) The POI has been taken by the Director General from 2008-09 onwards till Q3 of 2011-12. In view of the fact that full year of 2011-12 has not been included in the investigation, the data has been analyzed both annually and thereafter on quarterly basis. The quarterly analysis was considered important in order to take into account significant changes in the quarterly performance of the domestic industry.
- f) There is a significant price difference between the two raw materials (CBO prices prevailing in China vs. CBFS prices prevailing in international market). The price difference between the two raw materials provides significant cost advantage to the Chinese producers which lead to low price imports of Chinese Carbon Black. Resultantly, the Chinese carbon black became extremely lucrative for the consumers. It is this factor which is unforeseen under the given circumstances and has led to significant surge in imports of carbon black in India.
- g) That the price difference between CBO and CBFS started increasing from around April-June 2011 and became significant after July, 2011 period. The price difference has continually increased thereafter. The available information on market situations in China shows that the price of CBO in China started falling in Q1 2011-12 with further steeper fall thereafter.
- h) That both M/s PCBL and M/s Hi Tech are not export centric companies. Their Domestic sales continue to constitute majority of their sales. Moreover, the opposing parties have not provided any substantial information to corroborate their claim.

J Findings of the Director General (Safeguards) :

19. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, exporters and exporting nation. Submissions made by the various parties and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places in the findings below.

(I) The product under investigation:

20. The product involved is 'Carbon Black', classified under Customs Tariff Heading No. 28030010 under the Customs Tariff Act, 1975. Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black, lamp black, thermal black, and noir de carbone. Carbon black can be divided into two categories – rubber and non-rubber applications. Carbon black for rubber applications is used in production/ processing of rubber (including tyres), as a reinforcing filler. The present petition is in respect of increased imports of Carbon black used in rubber applications. Carbon black used in

non-rubber applications, such as inks in copiers and computer printer cartridges, paints, crayons and polishes, is not within the scope of the present investigation.

21. It is noted that the customs classification 28030010 is in respect of carbon black and includes all kinds of carbon black. However, the scope of the product under consideration in the present case is restricted to only carbon black used in rubber application. Therefore, the customs classification is not dedicated for the product under consideration.

(II) Domestic Industry:

22. Section 8C(7)(a) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:

(a) "Domestic industry" mean producers -

- as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India

23. The application has been filed by M/s. Association of Carbon Black Manufactures, 5A Raba Kailash, 55/4 Ballygunge Circular Rd. Kolkata-700019 on behalf of two of its member companies M/s. Phillips Carbon Black Limited, 31, Netaji Subhash Road, Kolkata-700001, and M/s. Hi-Tech Carbon, Murdha Indl Area, P.O. Renukoot, Dist: Sonbhadra (U.P.). There are four more known producers of Carbon Black in India namely M/s Continental Carbon India Limited, A-14 Industrial Area No. 1, South Side of GT Road, Ghaziabad-201 001; M/s Ralson Carbon Black Ltd., Jitwal Kalan, Tehsil Malerkotla, Distt. Sangrur, Punjab; M/s Cabot India Limited, MIDC Plot No.3, Trans -Thane Creek Area, Thane- Belapur Road, Post Ghansoli, Thane 400701 Maharashtra; M/s Himadri Chemicals & Industries Limited, Registered Office: Fortuna Tower, 23-A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata- 700 001. The applicants account for more than 80% of the Indian production and hence are major producers.

Financial Year	Quarter	Production			Share	
		Petitioners (MT)	Other Indian Producers(MT)	All Indian Producers (MT)	Petitioners	Other Indian Producers
2008-09		416,244	97,598	513,842	81%	19%
2009-10		492,862	121,766	614,628	80%	20%
2010-11		585,899	108,823	694,722	84%	16%
2011-12	Q1	163,458	29,086	192,544	85%	15%
	Q2	148,188	28,367	176,555	84%	16%
	Q3	137,035	34,854	171,889	80%	20%
2011-12(A)		598,241	123,076	721,317	83%	17%

24. After taking into account the information on record, it is determined that production of the domestic producers filing the petition and who have provided relevant information constitutes a major share in the total production of the product under consideration in India. Accordingly, petitioner companies constitute domestic industry as per Section 8C(7)(a) of the Customs Tariff Act 1975.

(III) Period of Investigation (POI):

25. The Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, do not specifically define what the Period of Investigation should be. However the issue of period of investigation has been dealt in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea. The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown":

"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analysed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports."(paras. 7.196, 7.199 and 7.201¹)

26. The Panel in the same US-Line pipe case ruled that:

"In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the domestic industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the

¹ WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, "the determination of whether the requirement of imports "in such increased quantities" is met is not a merely mathematical or technical determination." The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports "the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation". The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the domestic industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination." (Para 7.209)²

27. From the above it is clear that neither the domestic laws on Transitional Safeguard measures nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT, nor the Accession Protocol of the Peoples Republic of China provide specific guidelines on the period of investigation. However, having regard to the nature and purpose/objective of the present investigations, it is evident that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and market disruption and it should not only end in the very recent past but the investigation period should be the recent past.
28. Considering the long history of dumping of the product under investigation, levy of antidumping duty in 2009 and that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation, data has been considered from F.Y. 2008-09 to 2011-12 (Upto December). In the Notice of Initiation and Preliminary Findings, import data upto Oct 2011 had been considered. Now, the import data has been updated till Dec, 2011. The POI has been taken from 2008-09 onwards till Q3 of 2011-12. In view of the fact that full year of 2011-12 has not been included in the investigation, the data has been analyzed both annually and thereafter on quarterly basis. The quarterly analysis was considered important in order to take into account significant changes in the quarterly performance of the domestic industry.
29. The Imports of carbon black in India were examined over the entire period considered. Further, the pattern of imports was compared with the performance of the domestic industry as reflected in the economic parameters. The information provided by the interested parties with regard to market developments in India and China were also examined. The trends in major raw materials – CBFS and CBO were also examined over the period. It is seen that the price difference between CBO and CBFS started increasing from around April-June 2011 and became significant after July, 2011 period. The price difference has continually increased thereafter. The available information on market situations in China shows that the price of CBO in China started falling in Q1 2011-12 with further steeper fall thereafter. Having regard to all the information on record, it is considered appropriate

² WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

to consider Q2 and Q3 2011-12 as the surge period. Accordingly, imports in this period have been examined and compared with imports in preceding years in order to determine whether imports of the product under consideration have increased within the meaning of the rules. Further, information for April-Dec.2011 as a whole has also been considered and compared with the preceding years for the present determination. However, since this period is of nine months, figures have been compared with previous years after annualizing the same in order to arrive at a fair conclusion. It is considered appropriate that the six months period is sufficient and long enough to make a determination with regard to whether imports of carbon black have increased in India within the meaning of the rules and whether the domestic industry has suffered injury as a result of these increased imports.

(IV) Source of Information:

30. The product under investigation is imported into India under chapter heading 28030010 of the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of DGCI&S import data from 2008-09 to 2010-11 and data provided by the domestic industry from secondary data compiling agency (IBIS) for rest of the period. In the Preliminary Findings, the import data for the entire period has been considered on the basis of data provided by the domestic industry from secondary data compiling agency (IBIS). The information provided by the petitioners and other interested parties were examined and it was found that it included some imports of the products which are beyond the scope of the product under consideration. Therefore, even though the petitioners had reported imports as per IBIS which included imports under HS code 28030020 and 28030090 also; after scrutiny the imports falling under HS code 28030010 only has been considered. The analysis for increasing imports was carried out for the relevant period by considering imports of Carbon Black under chapter heading 28030010 of the Customs Tariff Act, 1975 for 'rubber applications' only.
31. The data on various economic parameters submitted by the domestic industry in their petition till Oct 2011 has been verified by this directorate to the extent possible and the non confidential version of verification report has been placed in public file for all concerned. The verified data has been taken into consideration for injury analysis. The data for Nov and Dec 2011 has been adopted on the basis of information furnished by the petitioners.
32. Some of the interested parties have made submissions disputing the claim of increased imports made by the domestic industry. The import volumes claimed by the domestic industry have also been disputed by some of the interested parties. Some interested parties have made reference to the submissions made by the domestic industry in the ongoing midterm review anti-dumping investigation by the Designated Authority and have alleged that import volumes claimed by the domestic industry in anti-dumping investigations are significantly different from import volumes relied upon by the Director General in the preliminary findings. The domestic industry has clarified to both, to the undersigned and the Designated Authority on Anti Dumping, that there was a typographical error in the import volumes reported by

the domestic industry in their submissions before the Designated Authority on Anti Dumping. So far as data for Q2 (2011-12) i.e 25772 MT submitted in their application filed before DG(Safeguards) is concerned, it is fact that the said quantity has been mentioned in the safeguard petition, but the figure taken by this office for Q2 (2011-12) is 25686 MT based on verification done. It is also noted that none of these parties disputing the preliminary findings with regard to increased imports have provided any information with regard to gross imports of carbon black in India for consideration. It is noted in this connection that questionnaire responses have been received from the following foreign producers.

a. Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc. Ltd. , China (Exporter Questionnaire)

33. Further, questionnaire responses have also been received from the following importers/consumers in India.

a. Apollo Tyres (Importer Questionnaire)

b. Ceat Tyre (Importer Questionnaire)

c. JK Tyre & Industries Limited (Importer Questionnaire)

d. Pheonix Conveyor Belt India (P) Ltd (Importer Questionnaire)

34. The information on imports provided by the responding exporters and importers/consumers have also been examined and analyzed. It is noted that these parties have provided information with regard to their own activities only. None of these parties have provided information with regard to gross imports of carbon black in India from China and third countries. Since the information was required on gross imports of the product in the Country, the information provided by the responding exporters or importers/consumers could not be relied upon for determining volume of imports. While disputing the claims of the domestic industry with regard to import volumes, I find that ATMA has not lodged any verifiable claim with regard to total imports of carbon black in India from China and third countries.

35. Some of the interested parties argued on reliability of IBIS data. However they have not provided any evidence to show that IBIS data is not reliable. The Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, do not specifically define the agency from where the import data should be taken but it is the discretion of the investigating authority to consider the data available to them. Also, there are cases in the past wherein IBIS data has been relied upon by this directorate. Therefore, reliance on IBIS data after thorough scrutiny at transaction level as source of import data is in consonance with the established practice followed in earlier investigations.

(V) Confidentiality of information submitted

36. The domestic industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The domestic industry provided non confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 2002 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated

06.09.1997. Further the domestic industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application.

37. The other interested parties have also provided some information on confidential basis and have requested for confidentiality of information and have submitted non confidential version of such submissions. However some of the interested parties have objected to the confidentiality claims of the domestic industry and have argued that the domestic industry has claimed excessive confidentiality and that meaningful argument can be put forward only with actual data on economic parameters is disclosed to the interested parties. These interested parties have argued that confidentiality should not be granted on such information.
38. Rule 7 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguards Duty) Rules, 2002 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information (there is no provision under Accession Treaty of the People's Republic of China in this regard). The rules provide that an interested party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.
39. Accordingly, I have considered the prayer for confidentiality wherever it has been sought by the domestic industry and other interested parties, and has been granted under the provisions of the aforesaid rule.

(VI) Anti-dumping Measures taken earlier:

40. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the Designated Authority notified its final findings vide Notification No.14/21/2008-DGAD dated 24th December, 2009 and recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of "Carbon Black used in rubber applications" originating in or exported from China PR, Australia, Russia and Thailand and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 6/2010-Customs dated 28th January, 2010. Investigation was carried out for the 12 months period starting from 1st Oct 2007 to 30th September, 2008 as the "investigation period" and the injury analysis was done considering the periods April 2005-March 2006, April 2006-March 2007, April 2007-March 2008 and Oct 2007- September 2008.
41. Based on these recommendations of the Designated Authority on Anti Dumping, the Govt. of India has imposed anti dumping duty on imports of the product vide notification no. 6/2010-Customs dated 28th January, 2010.
42. Thereafter M/s Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) has submitted an application before Directorate General of Antidumping and Allied Duties requesting for initiation of a midterm review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the product in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and

Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. On the basis of information made available by ATMA before the Designated Authority, the Designated Authority initiated a mid-term review of these anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR, Australia, Russia and Thailand vide notification no No.15/41/2010-DGAD dated 30th August, 2011. The period of investigation of the aforementioned Mid-Term Review is 1st April, 2010 to 31st March, 2011. The injury investigation period however covers the periods 2007-08, 2008-09, 2009-10 and the 2010-11. It appears that the Designated Authority has not yet recorded final findings in this review.

43. The application filed before the Designated Authority on Anti Dumping is based on claim by ATMA that the domestic industry is not suffering injury from dumped imports and there is no justification for continuation of anti-dumping duties. It is noted in this connection that Rule 23(1) of Anti-Dumping Rules provides for review of anti-dumping duty and states that the designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted. Further, the Designated Authority on Anti Dumping has stated as follows while initiating Midterm Review investigations.

Grounds for Review:

5. The Applicant has submitted that the import prices of Carbon Black have increased significantly; that domestic selling prices have also increased significantly; that the cost of raw material – Carbon Black Feed Stock (CBFS) has come down significantly and that with the fall in cost of major raw materials, the Non-injurious price (NIP) for the domestic industry has come down drastically. The petitioner has further submitted that coupled with a significant increase in import prices leading to an increase in the landed value of imports, the injury margin has come down and as a consequence, a need for reviewing the current level of duties has arisen.

Period of Investigation (POI)

10. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2010 to 31st March, 2011. The injury investigation period will however cover the periods 2007-08, 2008-09, 2009-10 and the POI (2010-11).

44. Thus, it is the case of ATMA (and Chinese exporters) that the product was not being dumped during April 2010– May 2011 period and that the domestic industry has not suffered injury during this period. The domestic industry has made available a copy of their submission before Designated Authority on Anti Dumping (post initiation submissions, written submissions and rejoinder submissions). Further, it is noted

that imports of the product under consideration started surging from Q1, 2011-12 and hence considered July-Dec.2011 as the surge period for the purpose of present investigations. It is thus noted that the investigation period considered for the present investigation is different from and is subsequent to the investigation period being considered by the Designated Authority on Anti Dumping.

(VII) Increased Imports

45. Section 8C of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows

"1. Notwithstanding anything contained in Section 8B, if the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India, from the People's Republic of China, in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause market disruption to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article"

46. The rules require an increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the rate and amount of the increase in imports, in absolute terms and as a percentage of domestic production as has been held by the panel and later confirmed by the Appellate Body in Argentina –Footwear case also.

47. In its evaluation of whether the investigation by the Argentine authorities demonstrated the required increase in imports under Articles 2.1 and 4.2(a), the Panel in Argentina-Footwear case stated the following:

... the Agreement requires not just an increase (i.e., any increase) in imports, but an increase in "such...quantities" as to cause or threaten to cause serious injury. The Agreement provides no numerical guidance as to how this is to be judged, nor in our view could it do so. But this does not mean that this requirement is meaningless. To the contrary, we believe that it means that the increase in imports must be judged in its full context, in particular with regard to its "rate and amount" as required by Article 4.2(a). Thus, considering the changes in import levels over the entire period of investigation, as discussed above, seems unavoidable when making a determination of whether there has been an increase in imports "in such quantities" in the sense of Article 2.1. (emphasis added)

48. Rule 2(iii) of Transitional Safeguard Duty Rules under the Customs Tariff Act, 1975 provides as follows

"Increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production

49. The analysis of the increased imports of Carbon Black in the light of the abovementioned provisions has been done. It is seen that Imports of Carbon Black (for rubber applications) from People's Republic of China into India have shown

sharp increase in absolute terms as well as in relative terms. It is also noticed that the rate of increase in imports from People's Republic of China is significantly higher than that imports from countries other than People's Republic of China, causing market disruption and threat of market disruption to the domestic industry.

a) Increase in Imports from China in absolute terms:

50. The imports of the product under consideration from China have increased in absolute terms throughout the injury period. There is a sudden, sharp and significant increase in imports in the recent period. Imports from China increased from 12971 MT in 2008-09 to 77804 MT in 2011-12 (Annualised basis), which is an increase of 600% over the period. **There is a sudden surge in imports in 2011-12 (A) over 2010-11 from China by 465% though increase in total import is only 173% during corresponding period.**

Financial Year	Quarter	Import from China (MT)		Total Import (MT)	% of Imports from China
		Annual	Quarterly		
2008-09		12971		39187	33
2009-10		17722		63244	28
2010-11		16724		61185	27
2011-12	Q1		5789	14828	39
	Q2		25686	32465	79
	Q3		26878	31972	84
2011-12(A)		77804		105686	74

51. The slight dip in import in 2010-11 from 2009-10 level is due to imposition of Anti-Dumping duty vide Notfn. No. 83/2009-Customs, dated 30th July, 2009 (Prov.) and vide Notfn. No. 06/2010- customs, dated 28th January, 2010 (final) on the subject goods. Since the definitive anti dumping duty became effective from 28th Jan'10, the volume of imports in 2010-11 reflected the same.

52. It is seen from the data above that imports of carbon black from China are increasing rapidly in absolute terms. The overall imports of carbon black from China have increased significantly from 12,971 MT in 2008-09 to 77,804 MT in 2011-12(A). The imports from China were 5789 MT in Q1 of 2011-12 which increased to 25,686 MT in Q2 of 2011-12. Also, the imports from China PR have increased significantly in Q2 of 2011-12 and Q3 of 2011-12.

53. As result of significant increase in imports from China, the overall imports of the product under consideration from various sources increased from 39187 in 2008-09

to 105686 in 2011-12 (A). Further, overall imports from various countries were 14828 in Q1 of 2011-12 which increased to 32465 MT in Q2 of 2011-12 and 31972 in Q3 of 2011-12. Thus, while the overall imports of the product under consideration averaged 9,797 per quarter in 2008-09, the same increased to 15,811 in 2009-10, declined marginally to 15,296 in 2010-11, but surged thereafter to 14828, 32465 and 31972 in Q1, Q2, and Q3 respectively in 2011-12.

54. Imports from third countries were as follows –

Financial Year	Quarter	Import from China (MT)		Third countries(MT)		Total Import (MT)	% of Imports from third countries
		Annual	Quarterly	Annual	Quarterly		
2008-09		12971		26216	6554	39187	66.90
2009-10		17722		45522	11381	63244	71.98
2010-11		16724		44461	11115	61185	72.67
2011-12	Q1		5789		9039	14828	60.96
	Q2		25686		6779	32465	20.88
	Q3		26878		5094	31972	15.93
2011-12(A)		77804		27882		105686	26.38

55. It is seen that imports from third countries represented major proportion in total imports of carbon black in India till Q1, 2011-12. However, with the surge in imports from China, the share of third countries rapidly declined and the imports from third countries collectively represented 21% and 16% in Q2 and Q3, 2011-12 respectively.

56. It is noted that so significant was the surge in imports that despite decline in imports from third countries after imposition of anti dumping duty, overall imports of the product under consideration in India showed significant surge.

(b) Increase in imports in relation to production of the domestic industry

57. The imports of Chinese Carbon Black in India have also increased rapidly in relation to production of the domestic industry. The production of domestic industry has declined in absolute terms in the recent period (2011-12) in view of the increased import from China PR. It is seen that imports of carbon black from China remained at a low level (between 3-4%) during 2008-09 and 2010-11 in relation to production of domestic industry. However, the imports have increased so rapidly thereafter in 2011-12 that the imports in relation to production constitute 13% of Indian production.

Financial Year	Quarter	Import from China (MT)	Production (MT)	% of China Import In relation to domestic production
2008-09		12971	416244	3
2009-10		17722	492863	4
2010-11		16724	585899	3
2011-12	Q1	5789	163458	4
	Q2	25686	148188	17
	Q3	26878	137035	20
2011-12(A)		77804	598241	13

(c) Imports in relation to Consumption/Demand

58. Changes in demand/consumption so determined over the period has been compared with the changes in the imports from various sources and supplies by the domestic industry in order to determine whether imports of carbon black in India have increased significantly in relation to consumption or demand for the product in the Country.

59. The imports of Chinese Carbon Black in India have increased rapidly in relation to Indian consumption of carbon black. It is seen that imports of carbon black from China remained at a low level (3%) during 2008-09 and 2010-11. However, the imports have increased significantly thereafter in 2011-12(A) to such an extent that the imports in relation to consumption constituted 11% of Indian consumption.

Financial Year	Quarter	Import from China (MT)	Total Demand/ Consumption (MT)	% of China Import In relation to domestic consumption
2008-09		12971	460048	3
2009-10		17722	582930	3
2010-11		16724	614152	3
2011-12	Q1	5789	160228	4
	Q2	25686	164671	16
	Q3	26878	165321	16
2011-12 (Total)		77804	653627	11

60. Imports from China in relation to domestic consumption increased from 3% in 2010-11 to 4% in Q1 2011-12. However, thereafter, imports from China in relation to domestic consumption increased to 16% in Q2 and Q3 2011-12. It is thus seen that imports of Chinese carbon black in India surged significantly in relation to domestic consumption.

61. In view of the above, it is observed that imports of Carbon Black from China PR have increased in absolute and relative terms and that the increase in imports is recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough to constitute "increased imports" within the meaning of Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975.
62. As regards the argument that increase in imports in September and October 2011 does not signify a trend and is an aberration, it is observed that the imports of the product under consideration have increased over the injury period in absolute terms with a sharp increase in the most recent period. There is a sudden, sharp and significant increase in imports in the recent period. The Imports from China have increased phenomenally from 12971 MT in 2008-09 to 77804 MT in FY 2011-12(A) which shows a significant increase. The increase in imports analysis is not based on only two months data. Even Q1, Q2 & Q3 of 2011-12 as a whole show increased imports.

(VIII) Unforeseen development

63. It is noticed in the domestic industry's submissions that there is no expressed obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules or under Accession Treaty of the People's Republic of China on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments. The Agreement on Safeguard also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. It is however, considered that it is important to examine the circumstances which have led to increased imports.
64. In Argentina — Footwear (EC) and Korea — Dairy, the Appellate Body held that "any safeguard measure imposed after the entry into force of the WTO Agreement must comply with the provisions of both the Agreement on Safeguards and Article XIX of the GATT 1994"³
65. Article XIX of GATT 1994 states as follows
1. (a) *If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.*
66. The Appellate Body in Argentina — Footwear (EC case) held that the phrase Unforeseen Developments means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause

³ Appellate Body Report on Argentina — Footwear (EC), para. 84 and Appellate Body Report on Korea — Dairy, paras. 76–77.

serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Body in the same case noted a GATT panel report which held that the development must have been unforeseen at the time of tariff negotiation. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

67. The Appellate Body, in Argentina — Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances":

68. The panel on US- Steel Safeguards⁴ concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development:

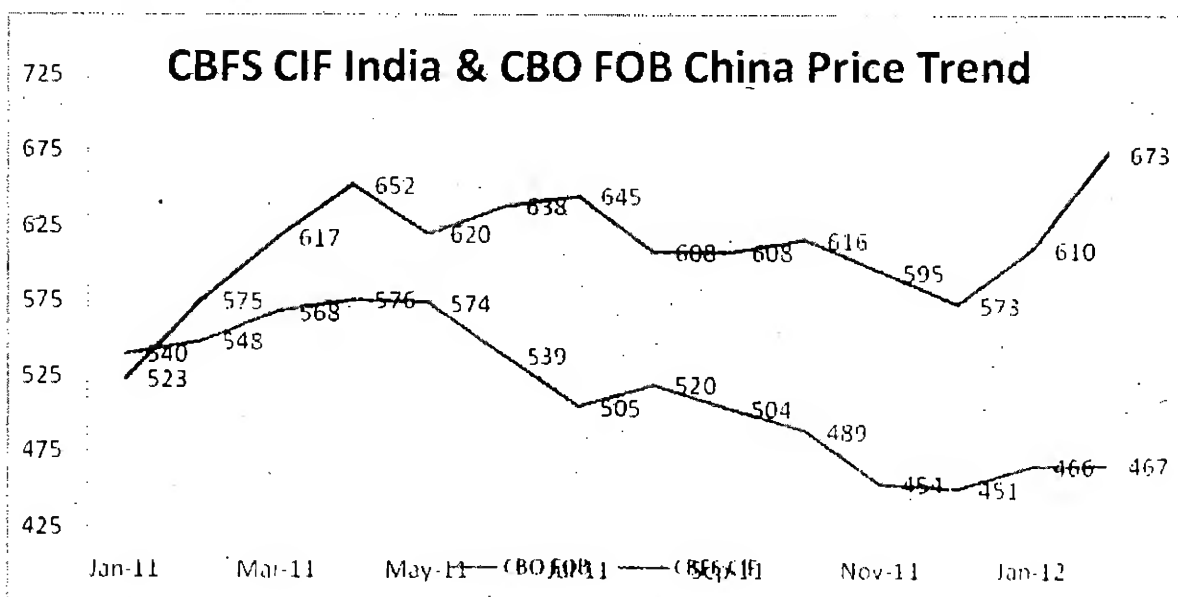
"The United States argues that the robustness of the US dollar was a development which combined with the other developments, namely, the currency crises in Asia and the former USSR and the continued growth in steel demand in the United States' market as other markets declined, lead to increased imports."

69. The petitioner has pointed out low price of raw material in China vis-à-vis raw material used by other countries including the domestic industry and its growing gap is the unforeseen development leading to surge in imports. It is observed that domestic industry largely uses CBFS (carbon black feed stock) as a raw material for manufacturing Carbon Black, whereas Chinese producers use CBO (carbon black oil), even though the domestic industry in India also uses CBO to the extent available and there are some plants in China as well which use CBFS. There is a significant difference in the price of these two raw materials. The price difference between the two raw materials provides cost advantage to the Chinese producers which led to low prices of Chinese Carbon Black.

70. In Carbon Black industry, the raw material cost is the major cost incurred by the producers of Carbon Black. Hence raw material prices play a major role in deciding the price trend of Carbon Black. After analyzing the price trend it was seen that throughout the injury period, there has been a price difference between CBO and CBFS. However, from the month of June'11, the prices of CBO started to decline and at the same time the price of CBFS started increasing which can be seen from table below. The domestic industry claimed following trends in prices of CBO and CBFS:

⁴ Para 86 of Korea Dairy case Appellate Body Report Of WTO 36

Month	China CBO FOB US\$/MT	CBFS CIF India US\$/MT	Gap between CBFS CIF India and China CBO US\$/MT
Jan-11	540	523	(17)
Feb-11	548	575	27
Mar-11	568	617	50
Apr-11	576	652	75
May-11	574	620	46
Jun-11	539	638	99
Jul-11	505	645	140
Aug-11	520	608	88
Sep-11	504	608	104
Oct-11	489	616	126
Nov-11	454	595	141
Dec-11	451	573	122
Jan-12	466	610	144
Feb-12	467	673	206



71. The BAIINFO Coal Chemical Weekly (report for the period 1st June to 7th June, 2012) submitted by the petitioner has been examined. The published reports suggest that the construction industry in China has faced slowdown due to some Govt. of China policy, as a result of which the prices of coal tar, industrial naphthalene and andhracene oil have significantly declined.
72. The report also suggests that purchase price of CBO in China has declined for the Chinese markets. It is also seen that in 2011, the total Carbon Black production in China far exceeds the total domestic demand, which indicates surge in exports from China in the ensuing period.

73. Thus, the evidence on record shows that the prices of raw materials involved in production of carbon black declined in Chinese market. In fact, whereas the prices of raw materials like CBFS globally increased, the same declined in the Chinese market. Since the raw materials cost constitutes majority of the cost of production (approx. 80 % of total cost of production is on account of raw materials), the price difference between the Chinese and global players has led to significant difference in the cost structures of the domestic industry and Chinese exporters. Resultantly, even when the Chinese producers have increased their prices in respect of exports to India the petitioners are suffering (despite their cost reductions) because the landed price of imports became significantly below the selling price of the domestic industry. The significant price difference between the domestic and imported product has resulted in significant surge in imports of Chinese carbon black in India.

	CBO FOB Price	CBFS CIF Price	Carbon black Import Price with ADD (Rs. Per MT)					
Months	RS./MT	Rs./MT	china	Australia	Korea (No ADD)	Thailand	Russia	Selling price Domestic Industry (Indexed)
Apr-11	26,044	29,457	56,012	67,492	60,766	61,781	56,683	100
May-11	25,814	27,878	59,410	65,813	60,596	60,611	59,540	102
Jun-11	24,621	29,136	60,144	66,448	79,838	65,184	57,238	101
Jul-11	22,993	29,342	61,890	74,700	74,197	64,787	58,117	104
Aug-11	23,264	27,198	60,676	77,415	72,906	65,390	---	107
Sep-11	23,459	28,313	62,010	80,508	73,244	81,266	60,507	107
Oct-11	24,278	30,547	65,646	85,015	78,138	84,048	67,362	108
Nov-11	22,725	29,770	69,720	79,403	91,707	-	70,576	106
Dec-11	23,740	30,129	70,615	-	86,931	-	76,226	105

74. It is seen from the above that the domestic industry increased its prices and, at the same time Chinese suppliers also increased their prices. However, despite such increases, the prices quoted by Chinese suppliers remained lower than domestic industry prices and third countries prices. The price of Carbon Black from other major supplier countries, i.e. Russia, Korea, Australia and Thailand, started increasing during the same period i.e. from June'11 onwards and were comparable or even higher as compared to the prices offered by the domestic industry. It is noted that this was the period when the imports from China have entered India in significant volumes capturing the Indian market by offering lower prices.

75. The price difference in the raw material for the most recent period Apr'11 to Dec'11 has resulted in cheap Chinese imports of Carbon Black capturing the Indian market causing irreparable market disruption.
76. It clearly shows that in spite of decline in raw material prices, China was able to increase its prices and yet are selling at price much lower than the other counterparts as the Chinese producers of Carbon Black are benefitted due to the raw material differences.
77. The price difference in the raw material can be seen as under:

Period	China CBO FOB US\$/MT	CBFS CIF India US\$/MT	Gap between CBFS CIF India and China CBO US\$/MT
Jan-11	540	523	(17)
Feb-11	548	575	27
Mar-11	568	617	50
Apr-11	576	652	75
May-11	574	620	46
Jun-11	539	638	99
Jul-11	505	645	140
Aug-11	520	608	88
Sep-11	504	608	104
Oct-11	489	616	126
Nov-11	454	595	141
Dec-11	451	573	122

78. The Chinese producers have created significant production capacities and are therefore looking for market opportunities. As per the information provided by the domestic industry and not refuted by opposing interested parties, including Govt. of China, the Chinese Carbon Black market is expanding on year to year basis thereby increasing their export volumes. The capacity of Carbon Black with China has exceeded 5 million ton per annum and the output is 3.4 million tones. Considering the huge production capacities of the subject goods in subject country lying idle and their export orientation and the increasing demand for the subject goods in India, in all likelihood imports will continue to remain high as compared to 2008-09 and 2010-11.
79. Some of the interested parties argued that raw material prices in China PR should be taken as "other factors" and not "unforeseen circumstances". It is noted that there is a significant price difference between the two raw materials (CBO prices prevailing in China vs. CBFS prices prevailing in international market). The price difference between the two raw materials provides significant cost advantage to the Chinese producers which lead to low price imports of Chinese Carbon Black. Resultantly, the Chinese carbon black became extremely lucrative for the consumers. I find that it is this factor which has led to significant surge in imports of carbon black in India and clearly therefore, raw material price is the unforeseen circumstance which lead to increase in imports.

(IX) Market disruption and Threat of Market disruption

80. Statutory framework: Under the Rules, "market disruption" shall be caused whenever imports of a like article or a directly competitive article produced by the domestic industry, increase rapidly, either absolutely or relatively, so as to be a significant cause of material injury, or threat of material injury, to the domestic industry⁵. "Threat of market disruption" means a clear and imminent danger of market disruption.
81. It is seen that the Annexure to Rule 8 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine market disruption or threat of market disruption. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which may show "material injury" to the domestic industry, and therefore may justify a finding of market disruption. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "material injury" to the domestic industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.⁶
82. Accordingly, in analyzing market disruption or threat of market disruption all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of market disruption or threat of market disruption, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of market disruption or threat of market disruption is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.
83. It is observed that the increased imports of Carbon Black from China PR have caused and are threatening to cause market disruption to the domestic producers of Carbon Black as reflected by the following factors:
- a. **Market share:** the market share of the domestic industry increased upto Q1 of 2011-12 but declined significantly thereafter. The market share of the domestic industry was 70% in 2008-09, when the domestic industry was suffering injury from dumped imports. The market share further declined to 69% in 2009-10, but improved thereafter to 72% (2010-11) and then to 74% (Q1, 2011-12) with the imposition of anti dumping duty. The market share of domestic industry declined from 74% in Q1 of 2011-12 to 61% in Q3 of 2011-12. This was the period when the Chinese imports entered the Indian market at significant rate capturing the Indian market. The market

⁵ Section 8C(7)(b) of the Customs Tariff Act, 1975

⁶ Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO

share of the subject imports from China increased from 3% in 2008-09 to 12% in 2011-12(A), while market share of imports from third countries in fact declined over this period. This sharp growth in Chinese market share led to decline in market share of both domestic industry and import from countries other than China. Further, the decline in the market share of the domestic industry was steeper and was despite imposition of anti dumping duty on various sources, including China. The surge in Chinese imports of carbon black has clearly adversely impacted the market share of the domestic industry. This decline in the market share of the domestic industry is despite significant addition to the production capacities by the domestic industry and significant increase in inventories with the domestic industry.

Financial Year	Quarter	Total Import (MT)	Import from China (MT)	Sales of domestic industry (MT)	Sales of other Indian Producers	Total Demand (MT)	% of Market Share		
							Domestic industry	China Import	Other Countries
2008-09		39187	12971	322809	98052	460048	70	3	6
2009-10		63244	17722	400295	119391	582930	69	3	8
2010-11		61185	16724	443430	109537	614152	72	3	7
2011-12	Q1	14828	5789	119327	26073	160228	74	4	6
	Q2	32465	25686	99206	33000	164671	60	16	4
	Q3	31972	26878	100608	32741	165321	61	16	3
2011-12 (A)		105686	77804	425521	122419	653627	65	11	4

- b. **Production:** - The production has been determined on the basis of production reported by the domestic industry in its excise records. It is seen that the domestic production increased up to Q1 of 2011-12, but declined in the next two quarters. The domestic production has fallen steadily from 163458 MT in Q1 (2011-12), to 148188 MT in Q2 (2011-12) and further to 137,035 MT in Q3 (2011-12) i.e. by 16%. The domestic industry has submitted that the production process of carbon black is such that the domestic industry should attempt to produce more and more of the product in order to achieve not only economies of scale but also to arrest fixed cost associated with the plant and production.

Financial Year	Quarter	Production (MT)	Per quarter(MT)
2008-09		416244	104061
2009-10		492863	123216
2010-11		585899	146475
2011-12	Q1	163458	163458
	Q2	148188	148188
	Q3	137035	137035
2011-12 (A)		598241	149560

As there is demand for the product, therefore the domestic industry had increased their capacity over the injury period. However, so rapid is the increase in the imports that despite these extra efforts by the domestic industry, the inventories levels with the domestic industry continued to rise to such an extent that the domestic industry were eventually forced to take recourse to production suspension. Increasing production with high capacity means inventory position will worsen further. The domestic industry contended that the increased imports of carbon black are leading to production suspension in the most recent period. The verification at the premises of the domestic industry showed that the domestic industry constituents had taken production shut down in order to arrest the trend of rising inventories.

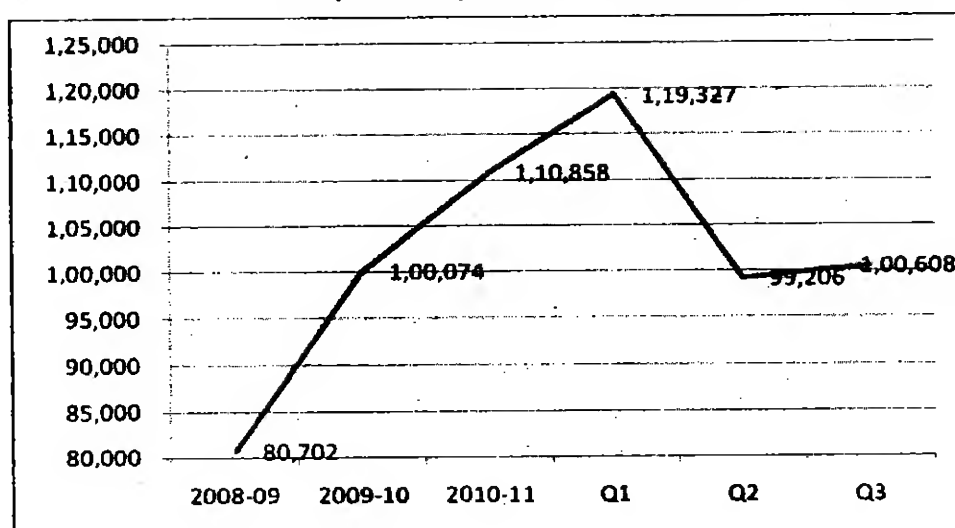
UNIT	Period of Shut Down		Days	Reason of Planned Shut Down
	From	To		
Phillips Carbon Black Ltd., Durgapur	07.09.2011	13.09.2011	7	Line-1 down due to high inventory
	16.09.2011	19.09.2011	4	CAT-1 down due to high inventory
	06.10.2011	31.10.2011	26	CAT-1 down due to high inventory
Phillips Carbon Black Ltd, Mundra	27.07.2011	07.07.2011	12	CAT-1 down due to market recession
	29.07.2011	04.08.2011	7	CAT-2 & CAT-3 down due to market recession
	26.09.2011	31.10.2011	37	R-2 down due to market recession
Phillips Carbon Black Ltd. Palej	12.09.2011	22.09.2011	11	Line-01 down due to high stock
	22.09.2011	27.09.2011	6	Line-03 down due to high stock
	25.10.2011	31.10.2011	7	Line-01 down due to high stock

84. It is also noted that demand for carbon black has shown consistent increase over the period. Thus, decline in production suffered by the domestic industry is despite continued increase in demand for the product in the Country. It is also noted that production of the domestic industry did not decline even during the dumping of the product in the Country. In fact, the domestic industry was able to improve its production despite dumping of the product. Further, the domestic industry increased its export volumes significantly in the most recent period. The domestic industry contended that the exports were undertaken considering domestic demand and off take of the product from the domestic market. However, even after undertaking additional exports, the domestic industry was faced with piling up of inventories and therefore had to reduce the production. The domestic industry eventually resorted to production suspension in order to contain rising inventories.

c. **Sales:** The sale has been determined on the basis of goods cleared by the domestic industry, as reported in their excise records.

Financial Year	Quarter	Production (MT)	Sales of domestic industry (MT)	Sales of other Indian Producers(MT)	Total Demand (MT)	Export (MT) by domestic industry
2008-09		416244	322809	98052	460048	94395
2009-10		492863	400295	119391	582930	89021
2010-11		585899	443430	109537	614152	141383
2011-12	Q1	163458	119327	26073	160228	44909
	Q2	148188	99206	33000	164671	45295
	Q3	137035	100608	32741	165321	35153
2011-12 (A)		598241	425521	122419	653627	167143

Graph: Per quarter sales of domestic industry



- i. It is seen that the sales of the domestic industry has increased up to FY 2010-11 and the trend continued till Q1, 2011-12 before the surge in Chinese imports started. However, the sales volumes of the domestic industry declined sharply in the most recent period from 443430MT in 2010-11 to 425521 MT in 2011-12(A). Sales declined in absolute terms from 119327 MT in Q1 of 2011-12 to 100608 MT in Q3 of 2011-12. This decline in sales is despite the fact that the total demand increased throughout the POI.
- ii. It is noted that in relative terms, sales of the domestic industry as percentage to total demand of the product has declined significantly with the surge in imports. Sales of the domestic industry as percentage of demand declined sharply from 74% in Q1 of 2011-12 to 61% in Q3 of 2011-12. This clearly shows that the domestic industry suffered loss in sales in absolute terms as well as in relation to demand.

Financial Year	Quarter	Sales as % of Demand.
2008-09		70
2009-10		69
2010-11		72
2011-12	Q1	74
	Q2	60
	Q3	61
2011-12 (A)		65

- iii. It is further noted that the Chinese imports have increased as a percentage of the domestic sales of the domestic industry. The Chinese imports were 4% of domestic industry sales in 2008-09, which increased to almost 18% in 2011-12 (Annualized) clearly showing the increase in imports and its effect on domestic sales of the domestic industry. In fact, during the surge period (Q2 and Q3 of 2011-12), Chinese imports were about 26% of domestic industry's sales volumes.

Financial Year	Quarter	Import from China (MT)	Sales of domestic industry (MT)	Chinese Imports as a % of sales of domestic industry
2008-09		12971	322809	4.02
2009-10		17722	400295	4.43
2010-11		16724	443430	3.77
2011-12	Q1	5789	119327	4.85
	Q2	25686	99206	25.89
	Q3	26878	100608	26.72
2011-12 (A)		77804	425521	18.28

- iv. The domestic industry contended that the rising imports of carbon black have prevented the domestic industry from selling its production in the domestic market. The domestic industry contended that so significant was the increase in imports that the same has led to decline in domestic sales of the domestic industry. This decline in domestic sales is despite the increase in demand and imposition of anti dumping duty. Domestic industry is being forced to export its production, despite significant domestic demand. So rapid was the increase in the imports that the domestic industry was forced to look for market opportunities outside India in order to dispose off the production, which could not be sold in the domestic market.
- v. The domestic industry further contended that there is a significant price difference between the domestic and imported product. The domestic industry also stated that even though the product is attracting anti-dumping duties, so significantly low the Chinese import prices are that even after adding the Anti-dumping duties, the landed price of imports are below selling price of the domestic industry. This significant price difference between domestic and imported product has led to increased sourcing by the consumers from Chinese producers. Resultantly, the sales of the domestic industry declined. Also the demand of the product increased by almost 39000 MT in 2011-12(A) from 2010-11 whereas the imports from China have increased by approx

61000 MT in the same period. This clearly shows that increase in imports is far more than increase in domestic demand of product under consideration in India, consequently the imports have captured significant market share of the Indian producers affecting sales of domestic industry, in the process causing market disruption.

- vi. As regards the argument that M/s PCBL and M/s Hi Tech are export centric companies, it is observed that both M/s PCBL and M/s Hi Tech have not been found to be export centric companies. Domestic sales of the two companies continue to constitute majority of their sales, as below:

Period	Quarter	Domestic sales(MT)	Export sales(MT)	Total sales(MT)	Share of domestic sales
2008-09		322809	94395	417204	77%
2009-10		400295	89021	489316	82%
2010-11		443430	141383	584813	76%
2011-12	Q1	119327	44909	164236	73%
	Q2	99206	45295	144501	69%
	Q3	100608	35153	135761	74%
2011-12 (A)		425521	167143	592664	72%

- vii. Moreover, the opposing parties have not provided any substantial information to corroborate their claim. It is noted that the inventories with the domestic industry rose sharply and significantly, despite production cuts and decline in capacity utilization. Had the Domestic Industry been export centric, they could have easily sold in the export market from inventories and by maintaining its production. The export was not a matter of choice but an effort to minimize the predicaments in wake of import surge.
- viii. The interested party in their submissions pointed out that export entries for Q1, Q2, Oct, 11, Q3 and 2011-12 (annualized) mentioned in preliminary findings does not match with the verified data placed in the public file. The matter was examined and it was found that the data placed in the public file is correct but inadvertently in the preliminary findings, due to typographical error, the value of the exports has been mentioned instead of quantity of exports. Even though this typographical error did not vitiate the injury analysis and conclusion, but for the sake of clarity and correctness of the data, a corrigendum has been issued on 21/06/2012.
- ix. The export price of the domestic industry was compared with their selling price in the domestic market. The data in table below shows that the export price of domestic industry was lower than their domestic selling price. Further no evidence has been brought on record to show that domestic industry has refused or delayed domestic supplies to the user industry in India and that the domestic industry has instead preferred exports

Period	Net Selling Price (DI) (Indexed)	Landed price of imports with ADD from China (Indexed)	Export Price (Indexed)
	Rs. per MT	Rs. per MT	Rs. per MT
2008-09	100	87	79
2009-10	92	85	70
2010-11	111	97	79
2011-12 (Till Dec.)	125	112	106

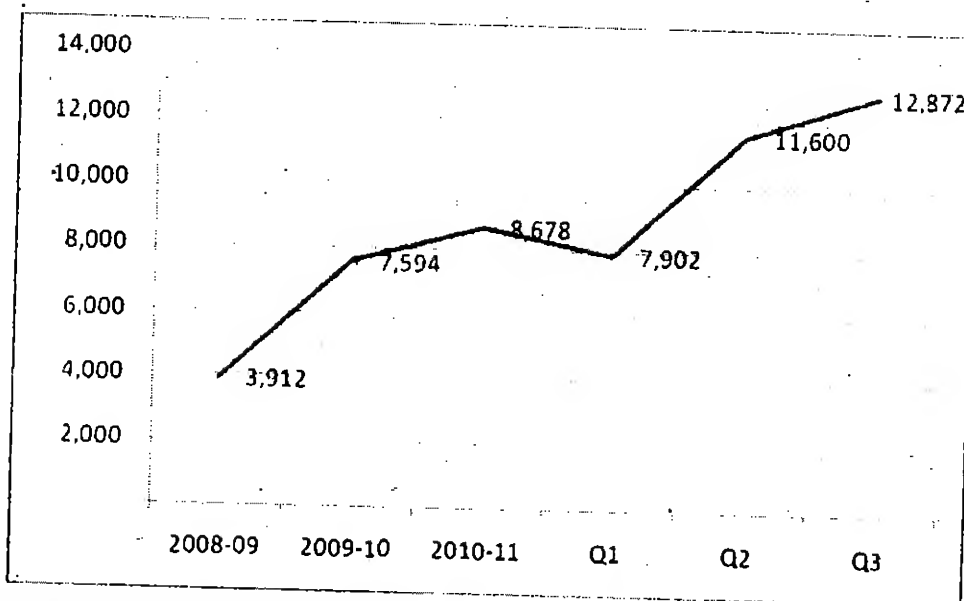
- d. Capacity utilization:** The domestic industry has added capacity over the period. The domestic industry contended that the addition to capacity is in view of present and potential demand of the product in the market. It is noted that the domestic industry added capacity upto Q1 2011-12 and despite these additions in capacities, the domestic industry was able to achieve 90% capacity utilization in Q1 2011-12. However, capacity utilization fell sharply thereafter in Q2 and further in Q3 to 82% and 76% respectively. The capacity utilization of domestic industry in the most recent period is at the lowest level. The expansion in capacity in 2011-12 was 9% over 2010-11 but the capacity utilization declined by 5% during the same period due to increase in market share of imports. It is noted that the capacity addition took place in Q1, 2011-12 and the domestic industry was able to achieve 90% capacity utilization in this period on the enhanced capacity. However, capacity utilization declined thereafter in Q2 and Q3 with surge in Chinese imports. It is thus noted that the decline in capacity utilization coincided with the surge in imports.

Financial Year	Quarter	Production (MT)	Installed Capacity	Capacity Utilisation (%)
2008-09		416244	500000	83
2009-10		492863	552500	89
2010-11		585899	667000	88
2011-12	Q1	163458	181002	90
	Q2	148188	181002	82
	Q3	137035	181002	76
2011-12(A)		598241	724008	83

85. Thus, the domestic industry was able to improve its capacity utilization despite additions of fresh capacities and dumping of the product in the Country. However, capacity utilization declined sharply in Q2 and thereafter Q3, when the imports have surged from China. Further, capacity utilization fell even when the domestic industry undertook additional exports in this period.

- e. **Inventory:** The level of inventories was considered as per excise records maintained by the domestic industry. It is seen that as the market share of the domestic industry was declining and that of imports was increasing, inventories with the domestic industry were rising. The domestic industry was unable to increase its sales volume (sales volumes in fact declined) and had to face the problems of accumulated inventories. The levels of inventories have increased significantly throughout the injury period. The table below depicts the inventory levels which have witnessed a massive surge from 3912 MT in 2008-09 to 12872 MT in Q3 of 2011-12, almost three times in 2011-12 from the 2008-09 level, reflecting the adverse effects of the surge in imports. The domestic industry contended that faced with rising imports, they made efforts to undertake additional exports in order to curtail the level of inventories and to maintain production to the extent feasible. However, increase in Chinese imports is so rapid that despite declining production and rising exports, the domestic industry is faced with rising inventories.

Financial Year	Quarter	Production (MT)	Sales of DI (MT)	Inventory(MT)
2008-09		416244	322809	3912
2009-10		492863	400295	7594
2010-11		585899	443430	8678
2011-12	Q1	163458	119327	7902
	Q2	148188	99206	11600
	Q3	137035	100608	12872
2011-12 (A)		598241	425521	12872



- f. **Employment and Productivity:** there is an increase in the level of employment with the domestic industry. The productivity of the domestic industry has shown the same trend as that of production. Productivity increased till Q1, 2011-12. Productivity however declined in Q2 and thereafter Q3, 2011-12.

Financial Year	Quarter	Employment (Nos)	Production	Productivity (MT per day)	Productivity (MT per employee)
2008-09		1,057	416,244	1,140	394
2009-10		1,133	492,863	1,350	435
2010-11		1,280	585,899	1,605	458
2011-12	Q1	1,290	163,458	1,816	127
	Q2	1,257	148,188	1,647	118
	Q3	1,302	137,035	1,523	105

- g. **Profit/loss:** The domestic industry has reported profit before tax, duly certified by a practicing Cost Accountant.

Financial Year	Quarter	Cost of Sales Indexed	Selling Price Indexed	Profitability Indexed
		RS/MT	RS/MT	RS/MT
2008-09		100	92	(8)
2009-10		77	85	8
2010-11		97	102	4
2011-12	Q1	92	96	3
	Q2	104	105	2
	Q3	104	103	(0.3)

- i. The profit reported by the domestic industry is considered in respect of product under consideration relating to its domestic operations only. It is noted that the domestic industry has export activities in relation to the product under consideration. Profit earned by the domestic industry in the exports operations have been segregated and has not been considered for the purpose of analyzing impact of increased imports on the profits earned by the domestic industry. The profit earned by the domestic industry has thus been considered in relation to carbon black for rubber applications relating to domestic market only. It is seen that profitability of the domestic industry has steeply declined in the most recent period. The profitability improved in 2009-10 but thereafter started declining significantly. The domestic industry suffered losses in the most recent period quarter (Q3).
- ii. It is seen that domestic industry suffered loss in 2008-09, and as contended by them, these financial losses are on account of dumping of the product. It is noted that Directorate General of Antidumping and Allied Duties had earlier conducted anti-dumping investigations in relation to carbon black, wherein the Designated Authority has considered October 2007 to September 2008 as the investigation period. It is, thus, concluded that the financial losses suffered in 2008-09 were in view of the injury caused due to decline in demand and dumping of the product.

- iii. There is a significant adverse effect on the profits of the domestic industry due to increased imports from China. PR. The landed price of the imports is significantly below the selling price of the domestic industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. As a result of significant price difference between the domestic and Chinese product, the consumers resorted to significantly higher sourcing from China. Resultantly, the profits of the domestic industry severely declined with the surge in imports. Further, whereas the costs have increased due to increase in input costs, the selling price did not increase in proportion to the increase in costs. Resultantly, the profit per unit of domestic sales declined with the surge in imports. The surge in imports is thus resulting in price suppression wherein the domestic industry is unable to increase its selling price in proportion to increase in cost.
- iv. It has been argued by the interested parties that no price suppression / depression has been caused to the domestic industry. It is however observed that due to presence of low priced imports, the landed price of imports were below the selling price of the domestic industry. Further, with the surge in imports, the domestic industry was unable to increase its prices in tandem with increase in costs. This is clearly established by decline in per unit profits of the domestic industry in respect of its domestic sales. Consequently the domestic industry suffered losses in the most recent period clearly establishing price suppression effect of the imports.
- v. Some of the interested parties argued that there is increase in profits as per the annual reports of the petitioner companies. It is however noticed that the information related to the performance of the domestic industry provided in the annual reports is pertaining to the overall performance of the company, whereas the present investigation is for domestic operations of Carbon Black for rubber application. Therefore, statements in the annual reports are not specific to the product under consideration and so no reliance has been made on them.
- vi. Some of the interested parties have argued on inherent competitiveness of coal tar. It is observed that the present situation is not that of difference in raw materials that can be used by the domestic industry and Chinese producers. Even the domestic industry can use CBO in its existing plants. However, the issue concerns the price at which CBO is available to the Chinese producers, domestic industry and global producers. The domestic industry argued that CBO price is low selectively in China and only for Chinese consumers. They can neither import CBO from China at these prices, nor are CBO prices in the global market low.
- vii. Some of the interested parties argued that the sales revenue of the domestic industry have increased. It is noted that sales revenue cannot be seen in isolation. It is further noted that the increase in sales revenue is due to increase in the cost of sales of the product under consideration but the profits of the domestic industry have declined significantly both year-wise and quarterly.
- viii. Some of the interested parties argued that imports from China and profit made by domestic industry are directly proportional to each other. It is observed that the surge started from July-Sept., 2011 and with the surge in imports, the profitability of

the domestic industry steeply deteriorated. Therefore, imports from China and profit made by domestic industry are not directly proportional to each other

- h. Return on investment:** The domestic industry has reported its return on investment considering profit before interest and taxes earned in the domestic operations relating to the product under consideration alone. Capital employed has been considered in respect of product under consideration for the domestic operations alone. Returns on investment have been determined considering profit before interest and capital employed by the domestic industry. Capital employed for the purpose has been considered as net fixed asset plus working capital. It is seen that return on investments showed the same trend as that of profitability. Return on investment declined from 222 points in 2009-10 to 111 points in 2010-11 and further declined to 44 points during the most recent period. As regards improvement in return on capital employed between 2008-09 and 2009-10, it is noted that the same is a result of imposition of anti dumping duty.

Financial Year	Quarter	ROI (Indexed)
		%
2008-09		(100)
2009-10		222
2010-11		111
2011-12	Q1	122
	Q2	78
	Q3	44

(X) Threat of market disruption

86. The rules provides as follows –

(1) *In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause "market disruption" to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.*

7a. *"threat of market disruption" means a clear and imminent danger of market disruption.*

87. The Panel on US — Lamb⁷ considered that a focus on the recent data available pertaining to the end of an investigation period was logical in view of the future-oriented nature of a threat of serious injury analysis. The relevant extracts are as follows:

"In our view, due to the future-oriented nature of a threat analysis, it would seem logical that occurrences at the beginning of an investigation period are less relevant than those at the end of that period. While the SG Agreement does not specify the appropriate duration of the time-period to be considered in an investigation, the Panel and Appellate Body in Argentina — Footwear both considered this issue to some extent. Both concluded that (for an actual serious injury finding) the most recent data were clearly the most relevant. In particular, the Appellate Body stated that 'the relevant investigation period should not only end in the very recent past, the investigation period should be the recent past'.

Given that a threat of serious injury pertains to imminent significant overall impairment, i.e., an event to take place in the immediate future, the same principle should hold true a fortiori for threat determinations compared with present serious injury determinations. This supports the view that the USITC was correct to focus on the most recent data available from the end of the investigation period. We also consider that data from 1997 and Interim-1998 cover an adequate and reasonable time-period if complemented by projections extrapolating existing trends into the imminent future so as to ensure the prospective analysis which a threat determination requires.

Therefore, we consider that, by basing its determination on events at the end of the investigation period (i.e., one year and nine months) rather than over the course of the entire investigation period, the USITC analysed sufficiently recent data for making a valid evaluation of whether significant overall impairment was "imminent" in the near future. By the same token, we also consider that, by basing its determination at all on data about events from the recent past, rather than relying exclusively on projections for the various industry indicators into the future, the USITC made its threat determination on the basis of objective and quantifiable facts, and 'not merely on allegation, conjecture or remote possibility'.

88. The Panel Report on US — Lamb, in a finding subsequently not reviewed by the Appellate Body, which addressed the question whether once imports have increased to already cause some degree of injury, there is no requirement of additional increased imports in order to legitimately determine the existence of a threat of serious injury. The relevant extracts are as follows:

"The complainants further claim that the US reference to projections of future increases in imports in defending its threat analysis amounts to equating a 'threat of increased imports' with a 'threat of serious injury', which the Argentina — Footwear panel found not to be permissible....

⁷ . Panel Report on US — Lamb, paras. 7.192-7.194

We agree in general with the complainants' argument that a threat of increased imports as such cannot be equated with threat of serious injury. However, in our view, this is not what the USITC has done in this case. Moreover, we also deem it possible that imports continuing on an elevated level for a longer period without further increasing at the end of the investigation period may, if unchecked, go on to cause serious injury (i.e., may threaten to cause serious injury). That is, if increased imports at a certain point in time cause less than serious injury, it is not necessarily true that a threat of serious injury can only be caused by a further increase, i.e., additional increased imports. In our view, in the particular circumstances of a case, a continuation of imports at an already recently increased level may suffice to cause such threat.

89. The Chinese imports are entering the Indian market in huge quantities in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. Significant price difference between the domestic and imported product indicates the likely adverse price effect of increased imports on Domestic Industry. It is seen from the published import data and imports of the product under consideration that the imports from China PR are largely of the carbon black for rubber applications. Imports of carbon black for non-rubber applications are quite low. Considering the net selling price of the domestic industry for the subject goods, the price difference between domestic and Chinese price is significantly high and is likely to remain positive making the imports lucrative and posing continued threat of increased import.
90. The threat of serious market disruption is established by the following factors:-
- (a) The price difference between domestic and imported product is too high. Thus, the imports will continue to remain lucrative;
 - (b) The Chinese producers are holding significant capacities. Resultantly, they are looking for additional markets to the extent possible;
 - (c) The increasing gap in the price of raw materials i.e. CBFS and CBO is providing significant mileage to the Chinese producers. The Chinese producers are therefore likely to intensify their activities in the Indian market;
 - (d) As the auto industry is witnessing growth and the demand of the product under investigation is also growing, the Indian market is lucrative and thus threat of market disruption is clearly imminent.
91. The domestic industry is losing sales opportunities. Consequently, production, capacity utilization, profits and return on investment is not improving even after imposition of anti dumping duties due to continued presence of low price increased imports. Given the low prices offered by the Chinese producers and significant freely disposable production capacities with them, the imports are surging further despite low prices offered by the domestic industry. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry causing serious market disruption and threatening to cause further damage.

(XI) Other Factors of Injury:

92. Article 4 (b) of the Agreement on Safeguards states as follows

(b) *The determination referred to in subparagraph (a) shall not be made unless this investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports*

93. According to the Appellate Body's decision concerning US-Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, the injurious effects of the import should be separated and distinguished from all the other factors which affected the local industry.

94. In the light of the above, the Authority has analyzed the possible other factors that may be attributed to the injury to domestic industry. Followings are relevant in this regard –

- a) Possible decline in demand of the product: There is no contraction in demand of Carbon Black in India. Demand of the product in India has shown significant increase over the years.
- b) Changes in the patterns of consumption: The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.
- c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- d) Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
- e) Export performance: The claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations. Petitioners have provided costing and injury information for domestic operation. Claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.

INDEXED

Period	Net Selling Price (DI)	CIF import price from China	Export Price
	Rs.per MT	Rs.per MT	Rs.per MT
2008-09	100	82	79
2009-10	92	74	70
2010-11	111	85	79
2011-12 (Till Dec.)	125	99	106

95. The data in table above shows that the export price of domestic industry was lower than their domestic selling price. However, the export price of the domestic industry during the year 2011-12 is higher than the import price from China. The domestic industry has to export the goods despite sound domestic demand at a price lower than its domestic selling price. In view of this, the export is not a preferred option for the domestic industry. The domestic industry has to export to optimize its resources. However, it cannot be said that the export is priority for domestic industry. Further no evidence has been brought on record to show that domestic industry has refused domestic supply to the User industry in India and have instead preferred exports. The fact that domestic industry has to export at price less than domestic sale price itself shows that the domestic industry is not export centric and has not focused on exports and ignored the domestic supplies.

(XII) Causal Link between Increased Import and Market disruption or Threat of Market disruption:

96. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyze and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the domestic industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports."

*To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its domestic industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the domestic industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analysed the situation of the domestic industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."*⁸

97. The product is largely sold in comparison/ competition with imports. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry as is evident from the table below. Subject imports are available at prices lower than the selling price of domestic industry. Consequently, the consumers are increasingly switching over to imports, thus forcing the domestic industry to offer sub-optimal prices. The domestic industry is losing sales opportunities. Consequently, production, capacity utilization, profits, return on investment is declining due to

⁸ Panel Report on Korea — Dairy, paras. 7.89-7.90

2847 9/12-14

continued presence of low-price imports. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. Consequently, the domestic industry has suffered decline in profits and return on investment. Exports undertaken by the domestic industry are a result of increased imports of carbon black from China. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports.

Import from China (indexed).

Period	Net Selling Price of domestic industry Rs/MT	CIF value of import Rs/MT	Landed price of imports without ADD Rs/MT	Landed price of imports with ADD Rs/MT	Price undercutting with ADD Rs/MT	Price undercutting without ADD Rs/MT
2008-09	100	82	87	87	13	13
2009-10	92	74	79	85	7	13
2010-11	111	85	90	97	14	21
2011-12 (Till Dec.)	125	99	105	112	13	20

98. The performance of domestic industry shows that despite increase in demand of Carbon Black over the POI, the market share of domestic industry has decreased and that of Chinese imports has increased. It is also seen that after imposition of Anti-Dumping duty(ADD) in year 2009-10, the price undercutting, both with and without ADD for imports from China has increased.

99. It is observed that even though there is a rise in import price in recent period, the same is far lower than the selling price of the domestic industry which has led to increase in price difference between domestic industry's Selling Price and landed price of import. This has resulted in consumers switching over to the imports from China PR and has caused grave market disruption and consequential injury to the domestic industry which establish the causal link between increased import and disruption caused.

100. It is argued by the opposing party that M/S Hi-tech was importing from Thailand. On the basis of examining the materials on record, It is clarified that there are no imports of product under consideration by M/s Hi-tech Carbon from Thailand.

(XIII) Public Interest:

101. Article 3 of the Agreement on safeguards states as follows:

1. *A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously*

established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.

102. In an economy there are varying and some time competing interests of different economic players. The imposition of safeguard duty can affect different players differently and the impact may not always be most suitable for all the different economic players when they have competing interests. Therefore interests of various economic player groups have been analyzed based on the available information

103. Some interested parties have argued that imposition of safeguard duty would not be in public interest as largest consumer of Carbon Black i.e tyre industry is already facing Anti-dumping duty and safeguard duty on various inputs. The issue has been examined.. In this respect, it is important to keep the prime objective of transitional safeguard laws in mind, which is to address injury to the domestic industry because of increased Chinese imports. It is in the interest of all to keep a healthy and competitive Industry. It is apparent that if the safeguard measures are not taken, both the prices and market share of domestic industry will further decline, resulting in financial losses to the domestic industry to the extent of getting the domestic industry unviable and consequent loss of employment as well as loss of strategic and economic interest to keep the domestic market competitive. The imposition of safeguard duty would allow the domestic industry to remain competitive and, at the same time, users/buyers will have a wider choice to source their material requirements, that too at competitive prices.

104. The petitioners have claimed that the cost of carbon black for the consumers is in the region of 6% (the fact can be established from the annual report of the tyre industry). The market share of China is around 11%. I agree with the submission made by the petitioner; even if it is argued that the consumer industry should continue to import the product at the same level from China and imposition of safeguard duty shall result in cost to the consumer increasing by 30% (as per provisional recommendation) in respect of these Chinese imports, it follows that the impact on consumer, in any case, shall not exceed 0.33%. This is ignoring the fact that the provisional safeguard duty of 30% recommended in the Preliminary Findings was proposed to be adjusted for anti dumping duty, payable, if any.

105. While arguing that imposition of safeguard duty shall not be in public interest, it is noted that ATMA has not provided any quantified claim in this regard.
106. Considering the above share and the insignificant cost of Carbon Black it is noted that there will be no or very minimal impact (0.19%) of Safeguard duty on the prices of the tyre industry.
107. Further, it is noted that already 3 investigations have been concluded on imposition of Anti-dumping duty on tyres and one is ongoing. Therefore, the tyre industry is well protected. It has not been demonstrated by the consumers that the impact of safeguard duty on the consumers will be unbearable. At the same time, the domestic industry has argued that given the market share of China, the impact of proposed safeguard duty on the consumer industry shall be insignificant. The domestic industry has further stated that it shall not increase its prices as a result of imposition of the proposed safeguard duty. As regards the Anti-dumping duty imposed on Carbon Black, it is noted that in spite of Anti-dumping duty being imposed on China, the imports kept on entering the Indian market at a significant volume causing injury to the domestic industry. Therefore it is in public interest to impose safeguard duty on imports of Carbon Black from China PR.

(XIV) Simultaneous Anti-dumping duty and safeguard duty:

108. There have been submissions from interested parties, who have submitted against the desirability of imposition of both duties simultaneously. They have also submitted that imposition of both duties at the same time is not in the public interest. The issue has been analyzed. It is a fact that anti-dumping duty is also a trade remedy measure to counter and neutralize the ill effects of dumped imports through raising tariff barrier. Safeguard duty is a measure to protect the domestic industry from injurious effects of increased imports by raising tariff barrier. Both the duties have one function in common i.e. neutralizing injurious effects of imports, besides other functions. The domestic industry is legally justified for filing the present application. WTO laws also permits the same. No violation of either domestic or international law has been pointed out by the interested parties. It is also noted that the anti dumping duty was based on a different investigation period, whereas the present safeguard duty being proposed is based on much more recent period. Further, the domestic industry is suffering injury despite the existing anti dumping duty. In fact, the Designated Authority on Anti Dumping is at present conducting a midterm review of existing anti dumping duty based on an application filed by ATMA. It is however clarified that the safeguard duty being proposed shall take into account the anti dumping duty that

is already in place. Therefore, there would not be dual protection against the same injury.

(XV) Other Issues

109. As regards the applicability of competition law it is held that the levy or non-levy of safeguard duty or other duty being a legislative act pursuant to the exercise of powers under the Customs Tariff Act can also not be a subject-matter of judicial review by the Competition Commission. The two Acts substantially operate in different fields.

(XVI) Provisional Measures:

110. In the Preliminary Findings, it was held that increased imports of Carbon Black from China PR have caused and threatened to cause further market disruption to domestic producers of Carbon Black. It was also observed that critical circumstances existed, where any delay in application for safeguard measures would cause irreparable damage to the industry. Considering the market disruption suffered by domestic industry during the year 2011-12 in a number of critical injury parameters, it was held that the provisional measures were rightly recommended in this case in order to thwart the possibility of irreparable damage. However, till date, no safeguard duty has been levied in the instant case.

(XVII) Conclusion:

111. On the basis of the above findings it is seen that
- Imports of the product under consideration have increased over the injury period in absolute terms with a sharp increase in imports in the recent period,
 - Increased imports of Carbon Black from People's Republic of China have caused and threatened to cause market disruption to the domestic industry/producers of Carbon Black and
 - It has been established that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports from People's Republic of China; and
 - It will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of Carbon Black from China PR.

(XVIII) Recommendation

112. Considering the average cost of production of Carbon Black by the domestic producers (confidential), a reasonable return on capital employed, the present

level of import duties and average import prices of Carbon Black, a Specific Safeguard Duty on Carbon Black falling under Chapter heading 28030010 (for rubber applications) is proposed for imposition in the following manner:

Period	Rate of Specific Safeguard Duty
First year	30% ad-valorem less anti dumping duty payable, if any.
Second year	25% ad-valorem less anti dumping duty payable, if any.
Third year	20% ad-valorem less anti dumping duty payable, if any.

113. Recommendation for leviability of the aforementioned safeguard duty is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, to be imposed on imports of such goods from Peoples Republic of China.

[F. No D-22011/12/2011]

INDRANI DUTT MAJUMDER, Director General